हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1 मार्च, 2012

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

विषय सूची

वीरवार, 1 मार्च, 2012

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(3)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)3
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)26
विभिन्न मामले उठाना	(3)26
गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, सैक्टर-32, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का अभिनन्दन	(3)28
चेयर पर आक्षेप करना/निलम्बन प्रस्ताव को वापस लेना	(3)28
नियम 30 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(3)32
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में पारदर्शिता संबंधी	(3)33
वक्तव्य— राजस्व मंत्री द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(3)34
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(3)39
बैठक का समय बढ़ाना	(3)84
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(3)85

मूल्य : 287

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 1 मार्च, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपराह्न) हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will make obituary references.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आजादी को हासिल करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और जिनको हमने खो दिया है। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं–श्री दीन दयाल, गांव ढाणी शोभा अहरोद, जिला रेवाड़ी और सरदार इन्द्रजीत सिंह भाटिया। यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता है और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के चचेरे भाई श्री राजबीर हुड्डा सुपुत्र श्री फतेह सिंह के 1 मार्च, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री राजबीर हुड्डा लोक निर्माण विभाग, हरियाणा से कार्यकारी अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे एक नेक, ईमानदार और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का सत्यनिष्ठा और लगन से पालन किया तथा सेवानिवृत्ति के बाद वे समाज सेवा के कार्य में लग गए। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन मुख्य संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर के छोटे भाई श्री समय सिंह राठौर के 27 फरवरी, 2012 को हुए असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। वे एक समाज सेवी एवं विकासशील विचारधारा वाले नवयुवक थे। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर की तरफ से जो शोक प्रस्ताव रखा गया है मैं भी अपने दल की तरफ से उसका समर्थन करता हूं। जो

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]
स्वतंत्रता सेनानी आज हमें छोड़कर चले गए हैं उनके नाम हैं—श्री दीन दयाल, गांव ढाणी शोभा अहरोद, जिला रेवाड़ी और सरदार इन्द्रजीत सिंह भाटिया। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन स्वतंत्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री के चचेरे भाई श्री राजबीर हुड्डा और मुख्य संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर के छोटे भाई श्री समय सिंह राठौर के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं भी अपने दल की तरफ से दिवंगतों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दिवंगतों में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम हैं—श्री दीन दयाल, गांव ढाणी शोभा अहरोद, जिला रेवाड़ी और सरदार इन्द्रजीत सिंह भाटिया। इन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही हमें आजादी मिली है। हमारे मुख्यमंत्री के चचेरे भाई श्री राजबीर हुड्डा जो लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी अभियन्ता रहे थे, के निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। हमारे सदन की सदस्या तथा मुख्य संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर के छोटे भाई श्री समय सिंह राठौर के 27 फरवरी, 2012 को हुए असामयिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the obituary references made by the Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by other Members of the House. I feel deeply grieved on the sad demise of Shri Rajbir Hooda S/o Shri Fateh Singh, cousin of Hon'ble Chief Minister, Shri Samay Singh Rathore, younger brother of Kumari Sharda Rathore, Chief Parliamentary Secretary and two freedom fighters of Haryana. Shri Rahbir Hooda retired as Executive Engineer P.W.D. (B&R) Department. He possessed the qualities of an educated, experienced and well-behaved officer, who served the State with all sincerity and dedication. Shri Samay Singh Rathore lost his life at a very young age. He was a great social worker. This is an irreparable loss to the bereaved family. The freedom fighters are always remembered by the society due to their selfless service to the society and deep love for the country and countrymen. I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood in silence as a mark of respect to the memory of deceased for two minutes.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour.

Students Appeared in SPAT

***919. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state—

(a) the district-wise number of students that appeared in the SPAT examination in the State togetherwith the amount spent on conducting the said examination during the period between 2009 to 2011; and

(b) the number of outstanding sports persons/players to whom employment in the State was given in accordance with their qualification during the period between March, 2005 to 2011 ?

खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) एस.पी.ए.टी. (स्पोर्ट्स एण्ड फिजिकल एप्टिट्यूड टैस्ट) पहली बार वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था । राज्य में स्पैट-2010 तथा स्पैट-2011 में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की जिलावार संख्या निम्नलिखित है :-

राज्य में स्पैट-2010 में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की जिलावार संख्या

क्रमांक	जिला का नाम	खिलाड़ियों की संख्या
1.	अम्बाला	1752
2.	भिवानी	5000
3.	फरीदाबाद	2335
4.	फतेहाबाद	1104
5.	गुड़गांव	2445
6.	हिसार	3459
7.	झज्जर	716
8.	जीन्द	2217
9.	कैथल	1196
10.	करनाल	1652

[श्री सुखबीर कटारिया]

क्रमांक	जिला का नाम	खिलाड़ियों की संख्या
11.	कुरुक्षेत्र	1498
12.	मेवात	420
13.	नारनौल	1021
14.	पलवल	1504
15.	पंचकूला	1609
16.	पानीपत	1155
17.	रेवाड़ी	2545
18.	रोहतक	4000
19.	सिरसा	1248
20.	सोनीपत	3300
21.	यमुनानगर	1185
	कुल	41,361

राज्य में सैट-2011 में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की जिलावार संख्या

क्रमांक	जिला का नाम	खिलाड़ियों की संख्या
1.	अम्बाला	1318
2.	भिवानी	18505
3.	फरीदाबाद	522
4.	फतेहाबाद	3087
5.	गुड़गांव	1367
6.	हिसार	9541
7.	झज्जर	4013
8.	जीन्द	7188
9.	कैथल	2646
10.	करनाल	3850
11.	कुरुक्षेत्र	1387
12.	मेवात	434
13.	नारनौल	7045
14.	पलवल	2747
15.	पंचकूला	966

क्रमांक	जिला का नाम	खिलाड़ियों की संख्या
16.	पानीपत	3671
17.	रेवाड़ी	3382
18.	रोहतक	6595
19.	सिरसा	3873
20.	सोनीपत	5934
21.	यमुनानगर	827
	कुल	88,898

एस.पी.ए.टी. 2010 के आयोजन पर कुल 21,35,643 रुपये की राशि खर्च की गई। एस.पी.ए.टी. 2011 के लिए 23,63,929 रुपये की राशि खर्च की गई।

(ख) राज्य में मार्च, 2005 से 2011 तक 361 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार दिया गया।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो अमाउंट मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पेट के लिए मैंशन की है यह स्पेट का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए है या इसमें स्कॉलरशिप भी शामिल है?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010 में 21,35,643 रुपये और वर्ष 2011 में 23,63,929 रुपये स्पेट के एग्जाम कंडक्ट करने पर खर्च किए गए हैं।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि क्या खिलाड़ियों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है वह अमाउंट भी इसमें इन्वौल्व है या अलग से है?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, स्कॉलरशिप के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक and according to qualifications, the sports persons/ players have been given the employment by the Govt. ? मैं यह जानना चाहता हूं कि ओलम्पिक, एशियाड और वर्ल्डकप में जिन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया उनके अलावा अर्जुन अवार्डी भी होते हैं। अर्जुन अवार्डी का अवार्ड जो है वह higher than Olympic players and higher than all the awards of other sports categories है। इसलिए जो अर्जुन अवार्डी हैं क्या उनको भी अप्वायंटमैंट की पॉलिसी में इन्क्लूड किया गया या नहीं किया गया? यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो भी खिलाड़ी एशियन, कॉमनवैल्थ आदि गेम्ज में पार्टीसिपेट करते हैं और ऐक्स्ट्रा ऑ र्डिनरी खिलाड़ी होते हैं उन्हीं को अर्जुन अवार्ड मिलता है। अभी तो अर्जुन

[श्री सुखबीर कटारिया]
अवार्डी खिलाड़ियों की कैटेगरी को नहीं लिया गया है लेकिन इसको भी ऐड कर रहे हैं और पॉलिसी अभी बनी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को अप्वायंटमैंट देने के लिए सरकार ने कोई अलग से पॉलिसी नहीं बनाई?

श्री सुखबीर कटारिया : सर, अलग से इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल डायरैक्ट इस सवाल से संबंधित तो नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स से ही संबंधित है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्पोर्ट्स मंत्री जी से जानना चाहूंगी हूं कि सरकार ने बहुत सी जगहों पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाये हैं। हमारे ब्लॉक में भी एक स्टेडियम बना लेकिन उसमें आज तक पानी का कनैक्शन और कोच की व्यवस्था नहीं हुई है। वहां पर कब तक पानी और कोच की सुविधा मिल पायेगी?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बताईये कि जो ओलम्पिक गेम्ज़ अब होने वाली हैं उनमें हरियाणा रीज़न के कितने खिलाड़ी सलैक्ट हुए हैं? उनके डिसिप्लिनज़ क्या-क्या हैं और अभी तक कितने स्पोर्ट पर्सन्स को इस पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा नौकरी दी जा चुकी है?

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, जो ओलम्पिक गेम्ज़ अब होने वाली हैं उसमें हरियाणा प्रदेश से विभिन्न गेम्ज़ में 9 खिलाड़ी सलैक्ट हो चुके हैं जिनमें एथलैटिक्स में कृष्णा पूनिया व ओम प्रकाश राणा, बाक्सिंग में जय भगवान, मनोज कुमार, विकास व कृष्ण, हाकी में संदीप सिंह व सरदारा सिंह, शूटिंग में संजीव राजपूत व अनुराज सिंह।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister can you tell me how many players of different games have been given jobs so far by the Government ?

श्री सुखबीर कटारिया : स्पीकर सर, अब तक भिन्न-भिन्न खेलों के 361 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस पॉलिसी के तहत वर्ष 1999-2005 तक सिर्फ 136 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, वैसे तो दो बातें मंत्री जी ने बड़ी अच्छी तरह से बता दी हैं फिर भी मैं इसको थोड़ा सा क्लीयर करना चाहूंगा। जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया है हरियाणा सरकार ने एक Definite Employment Guarantee Scheme बनाई है। इस बारे में जैसा कि श्री भारत भूषण बतरा जी ने पूछा कि हमारे जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं क्या उनको भी कोई रोज़गार देने का प्रावधान है। The policy is very brief, I will just to tell you three contours of the policy that will clarify the whole matter. सर, अर्जुन अवार्डी हों या दूसरे अवार्डी हों, the medal winners of Olympics Games and Gold Medal Winners in Asian Games, both these categories are given guaranteed Class-II Gazetted Officers appointment in Government Department or Board or Coporation. It is for the first time that any State in this country has done so.

Similarly, Silver and Bronze Medals winners of Asian Games, Gold and Silver Medal Winners of Commonwealth games and Gold Medal Winners of

World Championships or any cup that is organized by recognized Sports Federation, they are given guaranteed appointments on a minimum of Class-III posts. Participants of Olympics Games, Bronze Medal Winners of Commonwealth Games, Silver and Bronze Medals winners of World Championships or any cups and Medals winners of Asian Championships organized by recognized Sports federation will be suitably accommodated as per their qualifications in Government Departments, Boards and Corporations. These are recognitions, for achievements in Sports. They are conferred for achievements in Sports because a player excelled in a particular sport because he or she gets a gold medal, silver or bronze medal in a particular championships or in a particular cup or in a particular participating game at National and International level. That's why consequently Government of India recognizes you by conferment of an Arjuna Award. Arjuna Award is conferment of an honour. Consequently, anybody who is already here, all Arjuna Awardees will automatically be covered, Sir. A point was raised and the Minister answered.

Mr. Speaker : An Hon'ble Member also asked that there is no water connection or sewerage connection in a stadium of her constituency.

Shri Randeep Singh Surjewala : I straightway answer that Government has already decided that coaches will be appointed in each stadium and process of selection has been completed in many districts and in many districts, it is under process. For purposes of expeditious appointment, we have appointed a committee headed by Deputy Commissioner of the District. My learned friend can check with the Deputy Commissioner and the Hon'ble Minister will also check and come back to her. As soon as appointments are completed in Karnal District, we will make sure that a coach and other grounds staff will be appointed.

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, as you have been the Public Health Minister, she wants water connection there.

Shri Randeep Singh Surjewala : Absolutely, Sir. We are aware of that and requisite money is also sanctioned for provision of water connection alongwith appointment of ground staff. We are very conscious about it. Sir, for the first time in the State of Haryana, 361 sports persons were appointed. Sir, it is for the first time that not only were these appointments made but 12 Deputy Superintendent of Police were appointed direct for excelling in Sports. One Inspector was appointed, 30 Sub-Inspectors were appointed, 318 Constables and many other were appointed. 37 more players, I can say today itself, are being appointed now, 5 as Deputy Superintendents of Police, 18 as Inspectors and 14 as Sub-Inspectors, the Hon'ble Chief Minister has already declared that.

Criteria for Repair of Raods by HSAMB

***934. Shri Ashok Kumar Arora :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the criteria fixed to repair the roads of Haryana State Agricultural Marketing Board ?

Agriculture Minister (Sardar Paramveer Singh) : Sir, HSAMB conducts two kinds of repair on its roads—Annual repairs and Major repairs. Annual repairs involve routine patch work and berms repair. They are undertaken whenever the need arises on a regular basis. Repairs costing more than Rs. 44,000 per km. are classified as major repairs during the current year. Where major repairs are required, these works are carried out on a case to case basis depending on the condition of the road.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मार्केटिंग बोर्ड की गांव से गांव को और गांव को मंडियों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं उन पर पिछले कई सालों से आवागमन बढ़ा है जिसके कारण वे सड़कें जल्दी टूट जाती हैं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मार्केटिंग बोर्ड का निर्धारित मापदंड पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) के मापदंड के बराबर करेंगे? मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन सड़कों की रिपेयर कब तक कर दी जायेगी?

Sardar Paramveer Singh : Sir, we have improved the norms. Earlier this ordinary repair was upto just Rs. 16,000/- per kilometre. We have revised it to Rs. 44,000/- per kilometre. This is for ordinary repair, this is for minor repair. It is not for major repairs. For major repairs, we have improved the crust thickness and it is on the same pattern that PWD (B&R) is having now.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया । मेरा सवाल यह है कि मार्केटिंग बोर्ड के जो मापदंड हैं वह पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) से काफी कम हैं जिसके कारण वे सड़कें जल्दी टूट जाती हैं । मंत्री जी कह रहे हैं कि 44 हजार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से सिम्पल रिपेयर की जाती है । क्या मंत्री जी बताएंगे कि मेजर रिपेयर के लिए कितना खर्च करेंगे?

Mr. Speaker : Let the Hon'ble Minister answer the question.

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सड़कों की हालत चाहे कितनी भी खराब हो मेजर रिपेयर में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा । (शोर एवं व्यवधान) There is no limit.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेजर रिपेयर के लिए कितना रुपया प्रति किलोमीटर खर्च किया जायेगा?

Sardar Paramveer Singh : There is no limit. I am saying that it will be on the PWD pattern. इन सड़कों की रिपेयर के लिए जितना भी पैसा लगेगा हम उसका प्रावधान करेंगे ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये सड़कें कब तक रिपेयर हो जायेंगी?

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सड़कें हैं मैं उन सबके बारे में बता दूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट का इश्यू है केवल मेरे हल्के का नहीं है। मार्केटिंग बोर्ड का सड़कों की रिपेयर का मापदंड पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) से कम है जिसके कारण ये सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वे उस क्राइटेरिया को पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) के पैटर्न पर करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी कह तो रहे हैं कि उन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) को ट्रांसफर कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) बहुत सी रोड़ज ट्रांसफर की हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उसकी लिस्ट तो हमारे पास आ गई है। सवाल यह है कि क्या वे पैटर्न बराबर करेंगे या नहीं?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बी.एण्ड आर. से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Let the Hon'ble Minister speak.

सरदार परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) के पैटर्न पर मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के नॉर्म फिक्स करेंगे या नहीं? मेजर रिपेयर में हम पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) के नॉर्मज अपनायेंगे और क्वालिटी में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी लेकिन हम इसको फिक्स नहीं कर सकते कि कितने रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से नॉर्म फिक्स होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या ये पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) के नॉर्मज फिक्स करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने बता तो दिया कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) के बराबर नॉर्म फिक्स करेंगे, बात खत्म हुई।

श्री जगदीश नय्यर : मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं पिछले सदन की बैठक में यह सूची जारी की थी कि आपकी ये सड़कें गुड कंडीशन में हैं और ये सड़कें रिपेयर हो चुकी हैं। उस अरसे से जब तक सदन की बैठक नहीं हुई तब तक मैं एक-एक सड़क पर गया हूं और सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। यह झूठी रिपोर्ट आई है और पिछले 7 साल से ये झूठे आँकड़े पेश किये जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इसका कोई तरीका निकाल रहा हूं।

श्री जगदीश नय्यर : मेरे हल्के की एक भी सड़क रिपेयर नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय जी सात साल से झूठे आँकड़े पेश किए जा रहे हैं। मेरे हल्के की एक भी सड़क रिपेयर नहीं हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये Please (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नय्यर : अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के की कुछ सड़कें बिड़की से बिघोली मन्दिर, सपोरा से मरोली, बिड़ौग से औरंगाबाद और पिंगोल से नगरौला ऐसी कई सड़कें हैं जो

सात साल से रिपेयर नहीं की गई हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये Please (शोर एवं व्यवधान) अजय चौटाला जी पहले आप बोलिये उसके बाद मैं अपनी व्यवस्था दूंगा ।

डॉ० अजय सिंह चौटाला : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उन्होंने ही एक ये पत्र भिजवाया है जिसमें सभी विधायकों को सूचित किया है ।

श्री अध्यक्ष : आपको भी मिला है ।

डॉ० अजय सिंह चौटाला : हां जी, मुझे भी मिला है । जिसमें मेरे इलाके की साठ रोड्ज का जिक्र किया गया है । परन्तु सर, वहां पर आज हालत यह है कि सड़क नाम की कोई चीज नहीं है बल्कि गड्डों में से सड़क ढूंढनी पड़ती हैं कि सड़क है या नहीं? इसके लिए या तो माननीय मंत्री जी को विभाग ने गुमराह किया है या फिर माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । जरा बताएं, कब तक इस स्थिति को ठीक करेंगे?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आप बैठिए । हाऊस में अगर कोई स्टेटमैंट माननीय मंत्री जी ने दी है और वह फैक्चुवली गलत है जैसा कि मुझे बताया गया तो आप इस बारे में मुझे लिख कर भेजें । मेरी व्यवस्था यह है कि उसके लिए मंत्री जी की ऐक्सप्लेनेशन काल करेंगे ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अरोड़ा साहब तो मंत्री भी रहे और ये अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन भी हैं, हम इनका रिगार्ड करते हैं । इनकी जानकारी में होगा अगर नहीं भी होगा तो मैं आपकी अनुमति से सदन को और इनको बताना चाहूंगा । Speaker Sir, based on excel load and traffic density, thickness of the crust and thickness of the base is decided. National Highways has separate yardsticks and norms. Other district roads in the State have separate yardsticks and norms. State Highways of PWD (B&R) Department have separate yardsticks and norms. Village roads of Marketing Boards have totally separate yardsticks and norms. So, nobody can say that village roads should have thickness of a National Highway. That way precious national resources will be wasted. (Interruptions) So, National Highway will have its norms and PWD will have its norms. (Interruptions).

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, the member has pointed out that the roads which were developed to facilitate the agriculture uses are being used by the dumper-owners and they are breaking these roads and these roads cannot survive in the given circumstances. So, what should we do about it ? Why do you allow these dumpers on these roads so that they get broken in three days ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, the point is well taken and we have noted it. The fact remains that Indian Road congress has laid down certain norms. For Marketing Board also, as the concern is expressed by my learned friend, we have now decided that the crust thickness will be increased from 225 mm to 400 mm in future. We have decided that even for Marketing Board Roads.

International Horticulture Marketing Terminal

***1044. Shri Jai Tirath :** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an International Horticulture Marketing Terminal in Sonepat district; if so, the total amount likely to be incurred on the project; and

(b) the time by which the aforesaid Terminal is likely to be completed ?

Agriculture Minister (Sardar Paramveer Singh) : Yes, Sir. There is a proposal and we are setting up an International Horticulture Marketing Terminal at Gannaur and the likely expenditure on the project is estimated at Rs. 1264.67 crores and the Market is expected to start operations by end of the year 2012. All the planned activities are, however, expected to be completed by 2015.

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यहां सभी अंग्रेजी भाषा समझने वाले सदस्य नहीं बैठे हैं । जब भी कोई इस तरह का प्रश्न आता है और उसका उत्तर इंग्लिस में दिया जाता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि प्रश्न करने वाले मैंबर को ही नहीं पता होता कि उसके प्रश्न का उत्तर जो इंग्लिश में दिया गया है उसका क्या मतलब है । अतः अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज, इस तरह की व्यवस्था करने की कृपा करें कि जो प्रश्न है उसका उत्तर हिंदी में भी माननीय सदस्यों को मिल सके ताकि वे लोग जो अंग्रेजी भाषा से वाकिफ नहीं हैं वे भी अपने प्रश्न के उत्तर से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें ।

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, सदन में हर सवाल का जवाब हिंदी भाषा में टेबल पर रखा होता है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य का प्रश्न हिंदी में होता है जो अंग्रेजी भाषा से नावाकिफ है अगर उसके प्रश्न का अंग्रेजी भाषा में जवाब दिया गया तो उस माननीय सदस्य के लिए उस जवाब का क्या महत्व रह जायेगा ।

Mr. Speaker : Try to make the Members comfortable with language of Hindi also.

Construction of Road

***944. Shri Rajbir Singh Brara :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the main road which leads from Sadhaura road to Barara village in Barara town of Mullana Constituency is likely to be constructed ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, this road, which already exists, is likely to be repaired by 31.05.2012.

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि प्रश्न के जवाब में लिखकर आया हुआ है कि जो सड़क सढ़ौरा से बराड़ा गांव को जाती है वह सड़क 31.05.2012 तक पूरी हो जायेगी । यह सड़क पिछले दो साल से बंद पड़ी है । यह सड़क तीन गांवों की सड़कों को जोड़ती है । क्या इसका कोई टैंडर हुआ है, अगर हुआ है तो कब तक इसके बनने की संभावना है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त की चिंता वाजिब है, इसका टैंडर हो चुका है और क्योंकि हरियाणा में जो स्टोन क्वैरीज हैं उन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंध लगा हुआ है और माइनिंग पूरी तरह से बंद हैं, इस कारण इसमें देर हुई । यह सड़क हरिजन बस्ती के बीच में से जाती हैं, इस पर पानी खड़ा होता है और जो नॉर्मल क्रस्ट है यदि उस पर पानी खड़ा होगा तो वह फिर सिपेज कर जायेगा । मैंने विभाग को यह भी कहा है कि जहां-जहां पानी की स्टैगनेशन है यानि के बस्ती के अंदर, वहां सी.सी. ब्लॉक्स लगा दिये जायें चाहे कोस्ट थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाये । मुझे उम्मीद है कि मई के आखिर तक यह सड़क बना देंगे ।

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जगाधरी से जो सरावां रोड़ आती है, उसकी मंत्री जी ने मंजूरी दे दी है, उसका आधा भाग मंत्री जी ने मंजूर कर दिया है और आधे भाग के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि उसको बनाने का क्या कोई प्रावधान है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपके अनुरोध पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने उसे मंजूर किया है और बाकी के लिए ये लिखकर दे गये हैं, हम उसे प्रोसैस कर रहे हैं ।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन सड़कों के बारे में मंत्री महोदय सदन में तीन-तीन बार आश्वासन दे चुके हैं और समयबद्ध आश्वासन है कि इतनी तारीख तक ये सड़कें तैयार हो जाएंगी लेकिन उसके बावजूद भी इन सड़कों पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इन सड़कों पर कब तक काम पूरा किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं एक और आश्वासन देने का काम करूंगा कि जैसे ही स्टोन क्वैरीज खुल जाएंगी, इन पर काम शुरू कर देंगे ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह क्वैरीज कब तक खुल जाएंगी?

श्री अध्यक्ष : यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि क्वैरीज बंद थीं, तो मैं जानना चाहूंगा कि जितना पैसा इस काम के लिए अलोकेट हुआ था वह पैसा तो खर्च नहीं हुआ होगा, मैं जानना चाहूंगा कि कितनी राशि बची है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं । दो सदस्य एक साथ बोल रहे हैं, कैसे समझ में आयेगा, मेरे ही समझ

में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

Sewerage Treatment Plants and Canal Based Water Supply

***1026. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) the total number of Sewerage Treatment Plants and Canal Based Water Supply schemes launched by the Government in Ganaur, Kharkhoda and Gohana townships togetherwith the total amount to be incurred on the aforesaid project; and

(b) whether any delay has occurred in completion of these projects; if so, whether any responsibility of the officers/officials for causing delay in this regard has been fixed or not ?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में क्वैश्चन पूछा है इसलिए मुझे डिटेल में ही जवाब देना पड़ेगा। गन्नौर टाऊन का जो कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स है उसकी कैपेसिटी 9 एम.एल.डी. है और इसकी ऐस्टीमेटिड कॉस्ट 27.73 करोड़ है और अप-टू-डेट ऐक्सपैंडीचर 27.70 करोड़ हम कर चुके हैं सिर्फ 3 लाख बाकी रहता है। जो सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी 7 MLD and estimated cost is Rs. 15.8 and upto date expenditure has already been incurred to the tune of Rs. 15 crores and the rest is in process. We are also carrying out the work forward. Similarly, about Kharkhoda Canal Based Water Works, its Capacity is 4.50 MLD and estimated cost is Rs. 13.91 and expenditure incurred upto date is Rs. 13.88 and the capacity of Sewage Treatment Plant of Kharkhoda Town is 4.5 MLD and cost of project is Rs. 6.50 and expenditure incurred ये कार्य पूरा हो चुका है upto date is Rs. 6.50 crores. The capacity of Gohana Town Canal Based Water Works is 14 MLD and its estimated project cost is Rs. 42.45 crores and expenditure incurred uptodate is Rs. 23.83 crores and the rest is in the process. The capacity of Sewage Treatment Plant is 8.30 MLD and the estimated project cost is Rs. 16 crores and the expenditure incurred uptodate is Rs. 11.30 crores और यह 11.30 करोड़ खर्च हो चुका है and the rest is in the process.

Mr. Speaker : There is a second part also of this question.

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, Hon'ble MLA has also asked whether there was any delay which has occurred for these projects. Unfortunately, the answer is 'Yes'. There has been some delays but these delays have not been due to any kind of laxity on the part of the Department. यह डिले वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम गन्नौर, खरखौदा और वाटर सप्लाई स्कीम, गोहाना में इसलिए हुई हैं due to delay in acquisition of land, release of electrical and raw water outlet connections, कई

[Smt. Kiran Chaudhary]
जगह पर जैसे गन्नौर में परमीशन लेनी पड़ती है रेलवेज से and addressing of inter-department clearances of Mining, Forest and PW (B&R) Departments. But the work is in process and will be completed very fast.

Mr. Speaker : Can we also fix a target ?

Smt. Kiran Chaudhary : If you want, I can tell you.

Mr. Speaker : You read that much piece of note, but can you orally tell me as this pertains Gannaur also.

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, I would like to inform you that an added cost on we have put in more money *i.e.* 1156 lacs have already been approved on 19.12.2011 under State Planning of Outlaying Distribution Water in the Town and work is in process and this will be completed by the 30th June of 2012. Similarly sewage in all three areas will be completed by 30th of June, 2012. Similarly, the position of sewerage in all the three areas are also same about which he has asked. I have all the details if you wish and I can give it to you, Sir.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब में यह बताया है कि ये प्रोजैक्ट्स डिले हुए हैं लेकिन इनके विभाग के आफिशिएल की इस काम में कोई कमी नहीं रही । क्या ये बतायेंगी कि इन प्रोजैक्ट्स के लिए इनके विभाग ने किस विभाग को कब एप्लाई किया, कब इनको इस काम के लिए उस विभाग से क्लीयरैंस मिली और क्लीयरैंस को मिलने में कितनी डिले हुई? दूसरे ये सारे प्रोजैक्ट्स कब पूरे होंगे, जो इनके पूरे होने के शडयूल में कितनी डिले हुई है और जो डिले हुई है उससे इनकी कॉस्ट्स में कितनी इन्क्रीज हुई है?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि गन्नौर में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम को बनाने के लिए उसके लिए एस्टिमेट और डिजाईन रेलवे विभाग ने अप्रूव किया है लेकिन रेलवे की परमिशन 25.01.2012 तक भी नहीं आई है आप जानते हैं कि इस प्रोजैक्ट के लिए कितनी प्रॉब्लम हैं because we are still awaiting the permission. As far as the sewerage is concerned, the position is also same *i.e.* the estimates and designs have been approved from the Railways on 25.01.2012 and payment has already been made but the permission is yet awaited. So, the entire thing is according to circumstances which are beyond our control, Sir. इसी तरह से खरखौदा में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की सैंग्शन के लिए रॉ वाटर आऊटलैट जी.डब्ल्यू.एस. चैनल के लिए चीफ इंजीनियर इरीगेशन ने दिल्ली के ई.आई.सी. इरीगेशन विभाग को लिखा है जिसकी सैंग्शन 03.11.2011 तक अवेटिड है । ये सारे के सारे प्रोजैक्ट्स if all these sanctions come on time they are likely to be completed by 30.06.2012. As far as Kharkhoda is concerned उसमें एक प्रॉब्लम और भी बहुत जबरदस्त आई है कि तीन मेन होल्ज हैं जो भटिण्डा रोड पर हैं जिस पर काम हैल्डअप हो गया था क्योंकि इस में जमीन के मसले के बारे में कोर्ट से स्टे हो गया था जब कोर्ट से स्टे वेकेट होगा तभी हम काम को आगे

कर सकते हैं । इसलिए वहां पर यह सारा का सारा प्रोजैक्ट डिले हो गया है ! But even then we are now in the process of getting it through and I believe that the project is likely to be completed again by December, 2012. जहां तक गोहाना की बात है वहां पर तीन प्रोजैक्ट्स हैं वे सारे के सारे सैंग्शन हो चुके हैं और इन सबको हमने 03.11.2009 को बनाना शुरू कर दिया था। तीन बुस्टिंग स्टेशन बनाने के लिए जो कान्ट्रैक्टर बीच में काम छोड़ गया था उसके खिलाफ क्लॉज II के तहत कार्यवाही शुरू हो चुकी है । I would also like the Hon'ble Member to know that as far as the water supply project in Gohana is concerned, this is going to be completed by 30.09.2012 और इसमें डिले नहीं हुआ है । इसको बनाने के लिए तीन साल का समय दिया गया था और निर्धारित समय के अन्दर हम उसको पूरा कर रहे हैं और गोहाना में सीवरेज बनाने का कार्य 30.06.2012 तक समय सीमा में ही पूरा कर देंगे ।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, why do not you depute an officer specially to pursue these permissions ? Why should we wait for them ?

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, your point is taken. The department is very actively pursuing the whole thing but you know Sir, certain problems come in during the course of acquisition of land. Then there are court cases or any other exigencies or other things where the permissions have to be granted. For example like the Railways, I mean these are the places where they go upon their own time. The department has been persistently and consistently pursuing the whole thing and I would like to tell the Hon'ble M.L.A. that it is for the first time after the Congress has come to power that जहां पर गन्नौर में एस.टी.पी. नहीं थी वहां पर इतने करोड़ों रुपयों की पहली बार एस.टी.पी. दी जा रही है । इसी तरह से खरखौदा में पहले सीवरेज ट्रीटमैंट प्लान्ट नहीं था अब वहां पर साढ़े छः करोड़ रुपये की लागत से वहां पर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट बनाने जा रहे हैं । गोहाना में जो पहले सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट था उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है । इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो खर्चा इनके विधानसभा क्षेत्र में अब तक हमने खर्च किया है वह जुलाई, 1999 से फरवरी, 2005 तक 269.1 लाख रुपये था और वर्ष 2005 से लेकर अब तक 55.44 करोड़ रुपये है जो कि 25 गुणा ज्यादा है । सरकार इतना पैसा दे रही है ताकि लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए । Speaker Sir, in this current State Plan, now we have put another ₹ 300 Lacs, which was approved on 4.5.2011 for laying balance pipelines and the work in progress. It will be completed by December, 2012. Speaker Sir, similarly, I would like to put on record for the satisfaction of the Hon'ble Members that as far as Kherkhoda is concerned, (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूं बल्कि मैं यह बता रही हूं कि कितना पैसा पहले लगा था और कितना पैसा हम लगा रहे हैं और इसके लिए Hon'ble Members should be grateful and thankful. यह पैसा हम इनके लिए या उनके लिए नहीं लगा रहे बल्कि हम सबके लिए काम करना चाहते हैं । जहां-जहां कमी हैं हम वहां-वहां कहीं 25 गुना ज्यादा और कहीं 16 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं ।

HUDA Sector at Barwala

***1096. Shri Ram Niwas Ghorela :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a HUDA Sector in Barwala city ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

Extension of Anaj Mandi

***910. Shri Zile Singh Sharma :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for the extension of Anaj Mandi at Assandh town; if so, the time by which the extension work of the aforesaid Mandi is likely to be completed ?

Agriculture Minister (Sardar Paramveer Singh) : Yes, Sir. As soon as the suitable land is available, further action for extension of this Anaj Mandi would be taken.

Repair of Roads of Market Committee

***958. Shri Raj Pal Bhukhri :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads of the Market Committee in Sadhaura Constituency; if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired ?

कृषि मंत्री (श्री परमवीर सिंह) : जी हां, श्रीमान् । सढ़ौरा निर्वाचनक्षेत्र में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सभी सड़कों की मरम्मत 31.12.2012 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड इनके अंडर आता है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1.5.2005 से लेकर आज तक रादौर में कितनी नई सड़कें बनाई गई हैं ।

श्री परमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक सैपरेट प्रश्न है ।

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, Hon'ble member has to give a separate notice in this regard.

Erosion of Agricultural Land

***985. Shri Ashok Kashyap :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is a fact that there is huge erosion of Agricultural Land every year due to the flow of Yamuna river; if so, the steps taken or likely to be taken to stop the erosion of land of farmers in the State particularly in Indri Constituency ?

Irrigation Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : No, Sir.

श्री अशोक कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के इन्द्री में लगातार कई वर्षों से यमुना नदी में बाढ़ आती है। इससे किसानों की कई एकड़ फसल तबाह हो जाती है। पिछली बार की बाढ़ में तो फसल के साथ-साथ किसानों की सैंकड़ों एकड़ जमीनें भी यमुना में चली गईं। यह प्रश्न मैंने पिछली बार भी सैशन में लगाया था तब भी मुझे सरकार की तरफ से 'ना' में जवाब मिला था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे इन्द्री हल्के में किसानों के प्रति इस तरह का रवैया सरकार कब छोड़ेगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात गलत है कि इनके हलके की सैंकड़ों एकड़ जमीन बाढ़ में बह गई। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो केवल 40 एकड़ जमीन बाढ़ में रुक गई थी और 40 एकड़ जमीन में हमने 10 बांध प्रपोज किए थे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Member, is it the way that मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं और बिशन लाल जी आप बीच में बोल रहे हैं? आप तो बहुत समझदार हैं। प्लीज आप बैठें।

Sardar Harmohinder Singh Chattha : Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Chair that in the last six years, जब विपक्ष के साथी पावर में थे, उस समय बाढ़ रोकथाम पर 17.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। (विघ्न)

Mr. Speaker : Atleast let him complete his answer.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, जब हम पिछली जानकारी देते हैं तो इनको पीड़ा क्यों होती है? अध्यक्ष महोदय, इनके समय में 17.78 करोड़ रुपये बाढ़ रोकथाम के लिए खर्च किए गए और अब 96.68 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय साथी को भी बताना चाहूंगा कि इन्द्री में भी बाढ़ रोकथाम के लिए पूरी परपोजल बनाई है जिससे इन्द्री में फ्लड आने की संभावना कम रहेगी।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पानीपत में ड्रेन नं० 1 है जिसके लिए पिछले बजट में पैसे का भी प्रावधान किया गया था।

श्री अध्यक्ष : जैन साहब, यह सेप्रेट क्वैश्चन है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यमुना नगर वाई.डब्ल्यू.एस. में बाढ़ को रोकने के लिए ब्लॉक बनाने के लिए पैसा दिया गया था। उसमें बड़ा भारी 44 करोड़ रुपये का घपला हो गया। जिसमें अनूप सिंह, चीफ इंजीनियर और अनिल अग्रवाल पर पैनल्टी इम्पोज करने के लिए ड्यूटी लगाई गई और काम 90 प्रतिशत हो गया है। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : There is no speech happening here. It is a question hour.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Not to be recorded.

Shri Randeep Singh Surjewala : He should have given a call attention motion, he should have given an adjournment motion, he should have made a specific mention and he should have written to the Minister. How he disrupts the question hour in this fashion ? He cannot disrupt the question hour.

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिये ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां पर जो पैसा लगा है वह ईमानदारी से लगा है । उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, जवाब आ गया है जो आप कह रहे हैं वह गलत बात है । (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. He is trying to make a speech. Please sit down.

Establishment of University in Panchkula

***967. Shri Devender Kumar Bansal :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to establish an University in Panchkula ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में एजूकेशन की अपग्रेडेशन के लिए कई कदम उठाये गये हैं । कई यूनिवर्सिटीज और कालेज एजूकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए खोले गये हैं जिससे प्रदेश के छात्रों को बहुत सुविधा मिली है । पंचकुला के अंदर 5 हजार छात्र चण्डीगढ़ को माईग्रेट हो जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या कोई प्राईवेट या सरकारी यूनिवर्सिटी पंचकुला में बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, please give the specific answer regarding any proposal to come up with a Government or Private University in Panchkula ?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Speaker Sir, presently there is no proposal under the consideration of the Government to establish a University in Panchkula. लेकिन माननीय साथी ने प्राईवेट या सरकारी यूनिवर्सिटी खोलने की बात की है ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

प्राईवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम प्राईवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आये हैं जिसके तहत 6 प्राईवेट यूनिवर्सिटीज खोली हैं और 3 पाईप लाईन में हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यदि कोई पंचकुला में प्राईवेट यूनिवर्सिटी का परपोजल लेकर आता है तो उसको जरूर कंसीडर किया जायेगा।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहती हूं कि राजीव गांधी एजूकेशन सिटी में अब तक कितने प्रोजैक्ट्स आये हैं? इसके अलावा माननीय मंत्री महोदया जी यह भी बताने की कृपा करें कि राजीव गांधी एजूकेशन सिटी में कौन-कौन सी इंटरनेशनल लैवल की यूनिवर्सिटीज़ आई हैं?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहैल : स्पीकर सर, वैसे तो यह सैपरेट क्वैश्चन है फिर भी मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि एजूकेशन हमारी सरकार की टॉप प्रॉयरटी पर है। Higher Education is the priority sector of the Government. We want to make an educational hub. (Interruption) हम हरियाणा और विशेषकर सोनीपत को एक एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं। राजीव गांधी एजूकेशन सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजैक्ट है। वहां पर नैशनल और इंटरनेशनल लैवल की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। (शोर एवं व्यवधान) जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है कि राजीव गांधी एजूकेशन सिटी को हम एजूकेशन हब बनाने जा रहे हैं। राजीव गांधी एजूकेशन सिटी के लिए चार यूनिवर्सिटीज़ में से तीन को एल.ओ.आई. इश्यू हो चुकी है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं एस.आर.एम. यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी और अशोक यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एफ.आई.ए. यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद की है इसकी एल.ओ.आई. अभी पैंडिंग है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बताना चाहूंगी कि जब राजीव गांधी एजूकेशन सिटी के लिए जमीन एक्वायर की गई थी तो उस समय यह कहा गया था कि राजीव गांधी एजूकेशन सिटी में इंटरनेशनल लैवल की यूनिवर्सिटीज़ आयेंगी। क्या माननीय मंत्री महोदया जी इस बारे में कुछ बतायेंगी?

श्री अध्यक्ष : कविता जी, जो यूनिवर्सिटी वहां पर आ गई हैं वे भी अब इंटरनेशनल लैवल की बन जायेंगी। These universities will become of an international level.

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या के साथ-साथ जो माननीय सदस्य शोरगुल कर रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हम इंटरनेशनल लैवल की लॉ यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजूकेशन सिटी में लेकर आ रहे हैं जिसका बिल भी अतिशीघ्र आने वाला है।

Mr. Speaker : That is an achievement. I must compliment you. National Law University is a big thing for Haryana. Now, next question please.

Construction of ROB

***999. Smt. Savitri Jindal :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the

[Smt. Savitri Jindal]

Government to construct a Railway Over Bridge at Suryanagar in Hisar;

(b) if so, whether the matter has been brought into the notice of the Ministry of Railways by the Government; and

(c) if the reply to part (b) above be in affirmative, the present position thereof?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, Sir.

(b) & (c) Question does not arise.

श्रीमती सावित्री जिंदल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहूंगी कि अगर हिसार में मेरे द्वारा बताई गई जगह पर बाई-पास विजीबल नहीं है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समस्या का कोई और कारगर हल हो सकता है जिससे वहां पर शहर के निवासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जी ने जो चिंता जताई है मैं भी उससे अपने आपको जोड़कर यह बताना चाहूंगा कि जो सूर्या नगर का इलाका है यह हिसार-जाखल और हिसार-रेवाड़ी रेलवे लाईन के बीच में हिसार शहर के अंदर सिचुएटिड है और अब यह इलाका नगर पालिका के अंदर आता है। यहां पर हुडा ने सैक्टर 1 व सैक्टर 4 और सैक्टर 3 व सैक्टर 5 भी डैवेल्प किया है और सूर्या नगर भी हुडा की परिधि के अंदर ही आ जायेगा। अभी यहां पर आर.ओ.बी. के लिए सफिशिएंट ट्रैफिक नहीं है लेकिन जो वहां पर एक रेलवे क्रॉसिंग थी जो कि पहले ही हिसार-जाखल रेलवे लाईन पर थी हमने रेलवेज़ को बोलकर उसको सैक्टर 1 व सैक्टर 4 और सैक्टर 3 व सैक्टर 5 की डिवाइडिंग रोड पर शिफ्ट कर दिया है। अगर वहां पर आवागमन में कोई व्यवधान है तो उसे इससे आसानी मिलेगी और जैसे ही वहां पर आर.ओ.बी. के लिए सफिशिएंट ट्रैफिक अवेलेबल होगा तभी हम वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की प्रपोज़ल को नॉर्म्ज़ के मुताबिक कंसीडर करेंगे।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, माननीय विधायिका जी ने जो डबल फाटक के ऊपर ओवरब्रिज की बात कही है और उसके बाद जिंदल इण्डस्ट्रीज के साथ बने ओवरब्रिज की भी बात कही है। यह थिक्कली पापूलेटिड एरिया है और इस क्षेत्र में शहर की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। जहां तक ट्रैफिक की बात है यह हो सकता है कि वहां पर ओवरलोडिड ट्रक्स वगैरह न जा रहे हों लेकिन जो शहर का आम ट्रैफिक है वह सबसे ज्यादा इस एरिया में है। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि मंत्री जी इसको दोबारा कंसीडर करें। दूसरी बात मैं अपने इलाके के बारे में कहना चाहता हूं जो कि हिसार शहर के अंदर ही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर एक बाई-पास सैंग्शन किया है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। वहां पर भी इसी प्रकार से दो फाटक आते हैं। Sir, you will appreciate कि अगर बाई-पास बनेगा तो ओबिईसली उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक होगा। मैं इन्हें बताना चाहता

हूं कि वहां पर ओवरब्रिज बनाने के लिए भी वे इस मामले को गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया के साथ टेक-अप करें। क्या इस बारे में कोई लैटर भेजेंगे ताकि वहां पर भी बाई-पास मंजूर करवाया जा सके? एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कुछेक ऐसी जगह पर रेलवे लाईन के दोनों तरफ सड़कें बनी हुई हैं लेकिन वहां पर रेलवे फाटक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में पी.डब्ल्यू.डी. क्या बंदोबस्त करेगी? क्या इसके लिए कोई प्रावधान सरकार के पास है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो श्रीमती सावित्री जिन्दल जी ने पूछा था और सम्पत सिंह जी आपने भी अपने आपको उस चिन्ता से जोड़ा था कि यहां पर काफी ट्रैफिक है। उस बारे में मेरा कहना है कि हमने अभी सर्वे करवाया है जिसके मुताबिक वह भारत सरकार के रेलवे ओवर ब्रिज के नॉमर्ज में कवर नहीं होता लेकिन फिर भी श्रीमती सावित्री जिन्दल जी ने और श्री सम्पत सिंह जी ने कहा है इसलिए हम इस बारे में पी.सी.यूज. का फ्रैश सर्वे करवा लेते हैं अगर यह नॉमर्ज में कवर होता होगा तो सरकार को इसको मूट करने में कोई समस्या नहीं है।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सूरजपुर-रामपुर-सियुड़ी से पिंजौर-नालागढ़ रोड़ स्थित सुखोमाजरी-बसौला बाई पास है जिसके लिए 2009 में 33 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन इस काम को शुरू करने में देरी क्यों हो रही है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता दुरुस्त है यह एक सैप्रेट प्रश्न है। इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। मुझे जहां तक ध्यान है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बतला देता हूं कि हमने इसको बी.ओ.टी. आधार पर बनवाने के लिए बात की है और नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि वे इसको टेकअप करने के लिए तैयार हैं। अगर माननीय सदस्य पूरी जानकारी चाहते हैं तो वे मुझसे पूछ लें मैं सूचना इकट्ठी करके उनको कल बतला दूंगा।?

तारांकित प्रश्न संख्या 979

(इस समय माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न नहीं पूछा गया।)

Construction of ROB at Gharaunda

***1005. Shri Narender Sangwan :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Railway Over Bridge near village Kohand on NH-I, Assand road, in District Karnal; if so, the details thereof?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री नरेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने रेलवे ओवर ब्रिज के बारे में मंत्री जी से पहले भी पूछा था और उस समय भी इनका जवाब 'ना' में ही था। यह मामला तो कोहंड का मामला है लेकिन इससे पहले घरौंडा कस्बे का मामला था जहां पर जाम की स्थिति बनी

[श्री नरेन्द्र सिंह सांगवान]
रहती है जिसका जवाब मंत्री जी ने 'ना' में दिया और अब भी जवाब 'ना' में दे रहे हैं। हम जितने भी प्रश्न पूछते हैं मंत्री जी उनका जवाब 'ना' में ही देते हैं।

Mr. Speaker : No need to answer.

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले सैशन में कहा था कि आप अपनी मांग के बारे में लिख कर भेज दिया करें। हम उस बात को मानते हैं और मैंने माननीय मंत्री जी को दो महीने पहले इनके ऑफिस में जा कर किसी पुल के बारे में लिख कर दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसका जवाब कब तक आ जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और सांगवान साहब को भी मैंने पिछली बार भी कहा था कि नैशनल हाईवे का ग्रेडियंट इस पुल से देखें तो वह नॉर्मस में कवर नहीं होता। हमारा नॉर्म 1×30 है इस पर रिफाइनरी का भी ट्रैफिक आता है। इसका जो नैशनल हाईवे से डिस्टैंस है वह इसको परमिट नहीं करता कि वहां से हम फ्लाई ओवर बना सकें। अगर इसको बनाया गया तो वह सीधा नैशनल हाईवे पर जा कर उतरता है और उसका अंजाम गलत होगा। इसलिए उसको बनाया नहीं जा सकता। इसको हमने इग्जामिन करवा लिया है। ट्रैफिक भी जस्टीफाई करता है। There is no space or gradient available. We cannot possibly cause accident. नैशनल हाईवे पर पुल सीधा नहीं उतारा जा सकता।

Mr. Speaker : Alright, this is well-understood and well taken.

To Increase the Load of Transformers

***975. Shri Prithvi Singh :** Will the Power Minister be pleased to state the time by which load of transformers in Narwana Constituency is likely to be increased to meet out the load of motors installed on tubewells ?

बिजली मंत्री : (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, वांछित कार्य तीन महीनों में पूरा हो जाएगा।

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने 2010-11 में भी मंत्री जी से पूछा था कि कादमा पॉवर हाउस को 33 के.वी. से 132 के.वी. के लिएं अपग्रेड करने की जरूरत है

15.00 बजे

क्योंकि वहां पर ट्रांसफार्मर बहुत जलते हैं। उस पर मंत्री जी का जवाब आया था कि 132 के.वी. का तो नहीं बनाएंगे लेकिन उसका अपग्रेडेशन 15 MVA से 20 MVA कर देंगे। आज एक साल हो गया है अब तक 5 MVA का ट्रांसफार्मर भी वहां नहीं पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका? Please बैठिए आप।

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उसको अपग्रेड करके उसको 132 KV का करेंगे या वो 5 MVA को घटाएंगे या बढ़ाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सैप्रेट प्रश्न है। इसके लिए माननीय सदस्य अलग से लिख कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It is a separate question.

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, जैसा कि मेरे साथी पृथ्वी सिंह जी ने प्रश्न पूछा कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के कारण किसानों की नलकूपों की मोटर जल जाती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने नरवाना में कोई ऐसा सर्वे करवाया है कि कौन-कौन से ट्रांसफार्मर या पावरहाऊस ओवरलोड हैं और क्या उनको अपग्रेड करवाया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : आप नरवाना के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सोचा आप नरवाना में बिजनैस कर रहे हो।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा बिजली महकमे से विशेष लगाव है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, नरवाना में कुल 73 ट्रांसफार्मर हैं जिसमें से 26 को हमने ऑगूमैंट कर दिया है और जो बाकि बचे हैं उनको अगले तीन महीने में हम ऑगूमैंट कर देंगे। पूरे स्टेट में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में 3121 और दक्षिण में 2425 ट्रांसफार्मर हैं जिनमें से 797 और 200 क्रमशः उत्तर और दक्षिण में हमने ऑगूमैंट कर दिये हैं। इसके अलावा 1259 ट्रांसफामर्ज उत्तर में और 1949 दक्षिण में बचे हुये हैं, उनके ऊपर तकरीबन 3675 लाख रुपये खर्च होंगे तथा उनको भी हम अगले तीन महीने में ऑगूमैंट कर देंगे।

Merger of C&V Cadre with T.G.T. Cadre

***1050. Shri Sher Singh Barshami :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to merge C&V cadre (of teachers) with TGT cadre;

(b) whether it is a fact that in view of (a) above, the ratio of number of posts of Middle School Head Masters, TGT, Lecturers etc. will change; and

(c) if the reply to (b) above, is in affirmative, whether the interests of the employees, category wise, for promotion, shall be protected by maintaining their existing ratio of promotion ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :

(a) No, Sir.

(b) & (c) Question does not arise.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब 'ना' में है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो Classical और Vernacular Teacher हैं इनका अलग से कोई

[श्री शेर सिंह बड़शामी]
प्रोमोशन का प्रावधान किया है या नहीं ताकि इनको भी टी.जी.टी. के बराबर सुविधा मिल सके, इनको भी प्रोमोशन मिल सके, क्या इसका कोई मामला विचाराधीन है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि क्या मर्जर का कोई प्रपोजल है, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारे पास मर्जर का कोई प्रपोजल नहीं है लेकिन हमने हमारी एप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार C&V कैडर को डिमनिसिंग और डाइंग कैडर कर दिया है और जहां तक आपने प्रोमोशन की बात कही है, जिस तरह इनकी प्रोमशनज पहले होती थी उसी प्रकार एग्जस्टिंग स्नेरियो में होती रहेंगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 1007

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय श्री राजेंद्र सिंह जून सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Disposal of Sewerage Water

***1057. Shri Ganga Ram :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is fact that there are no proper arrangements for the disposal of sewerage water released from Rewari City; if so, whether there is any proposal under the consideration of the Govt. for proper disposal of sewerage water in the aforesaid city ?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Sir, there is an arrangement for the disposal of partially treated sewage water of Rewari City into the escape channel of Irrigation Department. However, due to objection of Irrigation Department, an alternative system to carry the partially treated sewage water from Rewari City to Massani Barrage is being explored.

Construction of Road

***993. Col. Raghbir Singh :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from Chang road to Balkara *via* Dhadi Chillar in Badhra constituency for which an assurance was given by the PWD Minister during February-March, 2011 Session; if so, the reasons for which the action has not been taken so far togetherwith the time by which the aforesaid road is likely to be constructed ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir. An assurance was made for roads where available consolidation path is 6 karams

wide. For this particular road, width of consolidation path in hadbust of village Changror is only 4 karams. स्पीकर सर, कर्नल साहिब आज मुझसे मिले भी थे और इन्होंने ये कहा कि मौके पर जो कंसोलिडेशन पाथ है वो चार करम नहीं बल्कि छह करम हैं तो मैंने ये कहा है कि कर्नल साहिब अगर कोई फैक्चुअल त्रुटि है तो बैठकर इसे चैक करवायेंगे तथा मैं डिपार्टमैंट को भी बोलूंगा। अगर कंसोलिडेशन पाथ चार करम की बजाय छः करम है तो सड़क बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं।

Construction of Bye-Pass

*904. **Shri Pardeep Chaudhary :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that there was a proposal for construction of bye-pass near Pinjore from Surajpur to Sukhomajra Bassolan; if so, the reasons for which the work of aforesaid Bye-pass has not been started so far ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. The construction of this road could not be started so far because earlier it was decided that this road would be constructed by HUDA but lateron this link was included in the proposed 4-laning project of Pinjore-Nallagarh (HP) Section of NH-21A. स्पीकर सर, इसके अलावा जो उन्होंने सप्लीमैंटरी में भी पूछा था ये उसके अंदर एड कर लिया गया है और इसको अब नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है (शोर व विघ्न)

To attach the Dhanies with Panchayat/Municipality

*1074. **Shri Krishan Kamboj :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that various Dhanies, surrounding Rania City, have neither been attached with any Panchayat nor with any the Municipality; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to attach/include these Dhanies with any of the Panchayat or Municipality; if so, the details thereof ?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Government is considering to attach these Dhanies with the nearest Panchayat. स्पीकर सर, हमने यह देखा है कि यह ढाणियां किसी पंचायत से एडेड नहीं थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं कि इन ढाणियों को जो क्लोजैस्ट पंचायत हैं उनके साथ एड कर देंगे।

श्री कृष्ण कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो ढाणियां हैं उनमें कई वोटर रह रहे हैं। यह ढाणियां न तो शहर के अंदर आती हैं और न ही गांव के अंदर आती हैं। अतः या

[श्री कृष्ण कम्बोज]
तो शहर का क्षेत्र 2 किलोमीटर बढ़ाया जाये या इन ढाणियों को नगरपालिका के साथ जोड़ा जाये या फिर इन ढाणियों को गांव की पंचायत के साथ जोड़ा जाये ।

श्री अध्यक्ष : कंबोज जी ये तो डिमांड है, आप सवाल पूछो । (विघ्न)

Sh. Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, the demand is accepted. The Hon'ble Chief Minister has already ordered. आपकी बात वाजिब है इन ढाणियों को नजदीकी पंचायत के साथ मिला दिया जायेगा ।

Mr. Speaker : Shri Kamboj ji, your demand is accepted. All the twenty questions have been taken up today. Hon'ble Members, now the question hour is over.

***अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर**

विभिन्न मामले उठाना

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमने और हमारी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने अपने कालिंग अटैंशन मोशन दिये थे उनका क्या हुआ ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे ये कालिंग अटैंशन मोशन बहुत ही जरूरी हैं । (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप एक-एक करके बोलें, सभी एक साथ न बोलें । (शोर व व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए ।

मौहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : आप एक-एक करके बोलिये । Nothing is to be recorded.

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे) (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इनकी एक आदत बन चुकी है कि ये जीरो आवर में कोई मिनिंगफुल बात नहीं होने देंगे (शोर एवं व्यवधान) ।

---

*सभी अतारांकित प्रश्नों के उत्तर बहुत ज्यादा बड़े होने के कारण हरियाणा विधान सभा पुस्तकालय में रखे गए ।

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, मैं आपके अनुरोध को अस्वीकार कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप सभी बैठ नहीं जायेंगे और मुझ से बोलने की पहले परमिशन नहीं लेंगे तब तक मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। इलियास जी, पहले आप बैठकर हाथ खड़ा करें कि मैं बोलना चाहता हूं उसके बाद ही मैं आपको अलाऊ करूंगा।

श्री मोहम्मद इलियास : सदर साहब, हमारी पार्टी के सम्मानित सदस्यों द्वारा पाला गिरने से किसानों की फसल को हुए नुकसान के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उस पर बोलने के लिए जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी भी हूं। हरियाणा प्रदेश में पाला गिरने से किसानों की फसल को बड़ा भारी नुकसान हुआ है चाहे वह सरसों की फसल हो या फिर गेहूं की फसल हो। यह सर्वविदित है कि गेहूं की फसल के लिए सर्दी बहुत जरूरी होती है लेकिन इस साल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बर्फ पड़ने के कारण बहुत ज्यादा पाला पड़ा है जिसके कारण गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में तो बर्फ पड़ी ही नहीं। क्या हरियाणा के किसी आखिरी गांव में बर्फ पड़ी है? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ******

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। विज जी, मैं खड़ा हुआ हूं आप बैठ जाइए। मैं एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दे रहा हूं। इसलिए आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहां पर उठाया गया, इसके बारे में सारे सदन को सोचना चाहिए कि यह विषय केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा कि इस पर इतने लोग बोल रहे हैं, यह प्रश्न स्वयं में महत्वपूर्ण है। It is a historical significant लेकिन इस तरह की व्यवस्था में आप चर्चा कराना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि जितना महत्वपूर्ण विषय आप यहां उठा रहे हैं, उसका सारा महत्व समाप्त हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस विषय में मेरे साथ आप कोऑपरेट करें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कालिंग अटैंशन मोशन का फेट बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded whatever is saying without my permission. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपके इतना समझाने का क्या इन पर कोई असर हुआ है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने हरियाणा में भारी पाले के कारण फसलों को हुए नुकसान के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन दी थी, आप उसका फेट बता दें।

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन डिसअलाऊ हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने नगर-पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में ठेके/तदर्थ आधार पर सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने संबंधी जो कालिंग अटैंशन मोशन आपकी सेवा में दिया था, उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन भी डिसअलाऊ हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, सैक्टर-32, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का अभिनन्दन

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सैक्टर-32, चण्डीगढ़ के छात्र आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो अपने आपको राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल के सदस्य कहते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि सदन की कुछ मर्यादाएं हैं और देश की अगली पीढ़ी यहां सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठी हुई है, इन बातों से देश की यह अगली पीढ़ी क्या शिक्षा लेकर जाएगी? यह पीढ़ी सोचेगी कि क्या सदस्य एक इतने जिम्मेदार स्पीकर से ऐसा व्यवहार करते हैं। हमको कम से कम सदन की मर्यादाओं का तो निर्वहन करना चाहिए। सदन की मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

चेयर पर आक्षेप करना/निलम्बन प्रस्ताव को वापस लेना

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने हरियाणा में विद्यालयों में राईट-टू-एजूकेशन एक्ट के तहत बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उसका फेट क्या है?

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, पहले आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इलियास, श्री जगदीश नैय्यर, श्री फूलसिंह खेड़ी और पृथी सिंह नम्बरदार और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अनिल विज सदन की वैल में आ गये और जोर-जोर से बोलने लग गये।)

Mr. Speaker : Please go back to your seats (Interruptions).

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप यह कागज ले लीजिए। आप हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, papers cannot be given to the Hon'ble Speaker by a Member like this. (Interruption) अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। ये माननीय सदस्य हाउस की वैल में आकर इस प्रकार से आपको कोई कागज न तो दे सकते हैं और न ही माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इस प्रकार से कोई कागज लेकर उसे कंसीडर करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर विज, आप इस तरह से वैल में आकर चेयर के सामने नहीं बोल सकते। आप अपनी सीट पर जाईये। मैं आपको बोलने का समय जरूर दूंगा। आप इस तरह से वैल में आकर कुछ भी कहें, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपनी सीट पर जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, ******

Mr. Speaker : Not to be recorded. आप अपनी सीट पर जाईए, उसके बाद मैं आपको बोलने का समय दूंगा। आप मुझे कुछ भी डिक्टेट करोगे वह मैं नहीं मानूंगा। (शोर एवं व्यवधान) No, no please. It is not a matter of joke. आप इसे मजाक समझते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। He cannot run a dialogue like this.

श्री अध्यक्ष : विज जी, आपको यह कोई राईट नहीं हैं कि आप हाउस को इस तरह से डिस्टर्ब करें और हाउस को चलने न दें। Please go back to your seats. (Interruption) Please go back to your seat. You cannot speak here. Go back to your seat. You do not know how to speak. You cannot speak here. Vij Sahib, you can't speak without my permission (Interruption). I warn you Mr. Vij. (Interruption) Please go back to your seat. I warn you Mr. Vij. (Interruption).

Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That Shri Anil Vij, M.L.A. be suspended from the service of the House for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming the member of this august House and grossly disorderly conduct in the House for the remainder of the sittings of the present Session.

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Vij Sahib cannot cast aspersion on the Chair like this. I strongly object it. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ******

Mr. Speaker : Can you blackmail me ? I cannot be blackmailed by anybody.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कोई ब्लैक मेल वाली बात नहीं है, सबका चेयर के प्रति सम्मान है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, he cannot cast aspersions on the Chair. It is totally unacceptable conduct.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अनिल विज जी की सस्पैंशन वापस लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर इस हाउस में हो रहे हैं और उन पर सप्लीमैंट्रीज का पूरा मौका मिल रहा है फिर सदन की वैल में आकर ब्लेकमेल करके यह कहना कि हमें बोलने दो नहीं तो हम हाउस नहीं चलने देंगे ठीक नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम तो रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि हमें बोलने का पूरा समय दे दिया करो। हम में से किसी की सप्लीमैंट्री तो पूछने ही नहीं दी गई और न ही हमारे प्रश्नों का कोई जवाब आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या इधर से भी तीन प्रश्नों पर मैंने कोई सप्लीमैंट्री नहीं होने दी थी? जब कोई सप्लीमैंट्री थी ही नहीं तो मैं कैसे कोई सप्लीमैंट्री होने देता। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा तो नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अजय सिंह जी, आप उनको आहिस्ता-आहिस्ता समझा तो रहे हैं लेकिन ये कब समझेंगे ये पता नहीं। ये कहीं और बैठे हैं और आपकी बात कम मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात को सभी मानते हैं। (शोर एवं

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

व्यवधान) आप सामने बैठने वालों की सारी बातें न माना करो बल्कि हमारी भी कुछ मान लिया करो । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, if Hon'ble Member assures that he will not cast any aspersions on the Chair, I will withdraw my motion.

श्री अध्यक्ष : चेयर पर एस्पर्शन करना गलत है ।

Shri Randeep Singh Surjewala : It is not acceptable.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अनिल विज जी की सस्पैंशन वापिस ले लें ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, आप बैठ जाइए ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का एक मौका दे दो । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Alright, Mr. Vij, you are not sitting. (Interruption) You are not acceding to my request. Please sit down. (Interruption) आप बिना पूछे खड़े नहीं होंगे । आप केवल हाथ रेज करेंगे, बोलेंगे नहीं । बस, अगर आप अब भी बिना मेरी परमिशन के बोलेंगे तो I read this motion, आप हाउस को चलने नहीं देना चाहते हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अब मेरा हाथ खड़ा है । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I read the motion because he is not amending himself.

Shri Sher Singh Barshami : Speaker Sir, please withdraw this motion.

Mr. Speaker : Alright, I withdraw it, as senior Members are requesting to withdraw this motion but Hon'ble Member Shri Anil Vij should behave in the House.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अनिल विज जी अब चेयर पर एस्पर्शन नहीं करेंगे ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं चेयर का रिगार्ड करता हूं और मैं अपनी तरफ से आपको कोपरेशन देने के लिए एश्योर करता हूं लेकिन आप मुझे बोलने का मौका जरूर दे दिया करें ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, श्री अनिल विज इस सदन के वरिष्ठ और जिम्मेवार सदस्य हैं। चाहे वे विपक्ष में हैं फिर भी हम सब एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते और एक दोस्त होने के नाते इनका आदर करते हैं। चाहे हम सत्ता पक्ष में हों, चाहे विपक्ष में हों परन्तु हम सबकी एक मर्यादा है और इस सदन की भी मर्यादा है कि जो स्पीकर हैं और जो हम सबके अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हम सब उनकी चेयर की गरिमा का ध्यान रखें। हम आपस में कई बार वाद विवाद और उत्तेजना कर लेते हैं पर आखिर में Speaker Sir, you are the custodian of the house. अगर चेयर पर हम एस्पर्शन करते हैं तो यह अनुचित है और निंदनीय है। माननीय सदस्य ने बैठते हुए यह कहा है कि वे चेयर का हाइस्ट रिगार्ड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि चेयर के प्रति कम से कम ये अपनी टिप्पणियों पर नियंत्रण रखेंगे। दूसरे साथी अजय सिंह चौटाला जी और अरोड़ा जी ने भी उनके बिहाफ पर यह कहा है कि उनकी सस्पैंशन वापस ली जाए तो मैं समझता हूं कि उनकी एश्योरैंस को मानते हुए यदि आपकी इजाजत हो तो I withdraw it.

Mr. Speaker : Alright, the motion is withdrawn and this matter is closed now.

नियम 30 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for suspension of Rule 30.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government Business on Thursday, the 1st March, 2012.

Sir, I also beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 1st March, 2012.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government Business on Thursday, the 1st March, 2012.

AND

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 1st March, 2012.

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding transaction of Government Business on Thursday, the 1st March, 2012.

AND

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 1st March, 2012.

(The motion was carried)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में पारदर्शिता संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 7 from Shri Bharat Bhushan Batra, MLA regarding transparency in Public Distribution (PDS) in Haryana. Mr. Batra may please read his Calling Attention Notice.

Shri Bharat Bhushan Batra : I want to draw the kind attention of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that transparency in Public Distribution System (PDS) is an ideal advocated by the present Prime Minister, Dr. Manmohan Singh as also a number of National Leaders over a period of time. PDS is a key driver for percolation of benefits to the last man in the line i.e. to poorest of poor in remotest of the areas. Crores are given by way of subsidy by Central and State Governments for providing adequate food security in terms of food grains, pluses, oil, sugar, kerosene oil etc. through PDS. Government, administrators, social organizations and policy analysts have repeatedly pointed out the fact of non-availability of these benefits to the poor in PDS on account of its inherent leakages and pilferage at various steps in the distribution hierarchy. He has further requested the Government to make a statement on the floor of the House regarding total number of PDS beneficiaries in the State, quantum of benefits provided through PDS and steps taken to make PDS more effective, transparent and reliable as also to ensure that leakages/ pilferages in the system are plugged once for all by use of Information Technology or any other measure.

Mr. Speaker : Now, the concerned Minister will make a statement.

वक्तव्य

राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों पर, अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (बी.पी.एल.) करने वाले लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा क्रमशः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में की जाती है। भारत सरकार द्वारा ही राज्य में बी.पी.एल. और अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की संख्या निर्धारित की जाती है। भारत सरकार ने हरियाणा हेतू अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों की अधिकतम सीमा 3.02 लाख परिवार तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य परिवारों की अधिकतम सीमा 4.86 लाख परिवार, इस प्रकार कुल 7.89 लाख को बी.पी.एल. परिवारों के रूप में मान्यता प्रदान की है। जबकि ग्रामीण विकास और शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 12.97 लाख है। इस समय भारत सरकार 7.89 लाख बी.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्न का आबंटन कर रही है। जबकि हरियाणा सरकार ने बचे हुए 5.08 लाख बी.पी.एल. परिवारों को भी बी.पी.एल. दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इन परिवारों को राज्य बी.पी.एल. परिवारों के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा दिये गये ए.पी.एल. के खाद्यान्न का एक हिस्सा राज्य बी.पी.एल. परिवारों को उपलब्ध करवाया जाता है और दरों के इस अन्तर की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस उद्देश्य के लिये इस वर्ष 43.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. सरकार द्वारा आबंटित किये गये आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग के पास जिला, ब्लॉक और जमीनी स्तर पर एक व्यापक संरचना है। मिट्टी के तेल के इलावा अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में कानफैड एक थोक विक्रय के रूप में कार्य करता है। तेल कम्पनियां मिट्टी तेल के वितरण के लिए थोक विक्रेता नियुक्त करती है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने 9364 उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की है जिसमें से 2699 शहरी क्षेत्र में तथा 6665 ग्रामीण क्षेत्र में है। गत् वर्ष राज्य सरकार द्वारा 5.81 लाख मिट्रिक टन गेहूँ का आबंटन विभिन्न श्रेणियों जैसे अन्त्योदय अन्न योजना, बी.पी.एल., राज्य बी.पी.एल. और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) वाले लाभार्थियों को किया गया जिसमें लगभग 435 करोड़ रुपये की सबसिडी दी गई। इसमें से लगभग 27 करोड़ रुपये की सबसिडी हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई।

3. राज्य सरकार ने वास्तविक लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए कई कदम उठाये हैं। लक्षित परिवारों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए गांवों एवं वार्डों में निगरान समितियों का गठन किया गया है जिन्हें वास्तविक वितरण पर चौकस नजर रखने का अधिकार है। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में एक निर्णायक भूमिका निभाने का अधिकार दिया गया है जिसमें नया राशन कार्ड बनाने, डिपो आवंटन करने हेतू नाम की सिफारिश करना व वास्तविक वितरण कार्य प्रणाली की निगरानी करना आदि शामिल है। जिला शिकायत निवारण

समिति की मासिक बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की जाती है। शिकायत यदि कोई हो तो, तो सभी सदस्यों की उपस्थिति में उसका निपटान किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की जांच हेतू विशेष अभियान चलाया गया। वर्तमान वर्ष में, दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(i)	पुलिस में दर्ज मामले	:	19
(ii)	गिरफ्तार व्यक्ति	:	06
(iii)	लाईसैंस रद्द	:	137
(iv)	सुरक्षा राशि जब्त (रु०)	:	6.75 लाख
(v)	मिट्टी के तेल के थोक व्यापारी लाईसैंस रद्द/निलंबित	:	2

4. राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा राज्य को भारत सरकार के स्मार्ट कार्ड पायलट प्रोजैक्ट को शुरू करने का गौरव प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह पायलट प्रोजैक्ट केवल हरियाणा और केन्द्रीय शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में ही लागू किया गया है। इस प्रोजैक्ट से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली गड़बड़ियों को उचित तकनीकी समाधान प्राप्त होगा। इस प्रोजैक्ट पर कुल 137.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इस प्रोजैक्ट पर राज्य द्वारा कार्य शुरू किया जा चुका है।

5. राज्य के लगभग 56 लाख परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार स्मार्ट राशन कार्ड जारी किये जाएंगे। स्मार्ट राशन कार्ड पर विभिन्न श्रेणियों के परिवारों के लिए अलग-अलग रंग की धारी (अन्त्योदय अन्न योजना के लिए गुलाबी, बी.पी.एल. के लिए पीली और ए.पी.एल. के लिए हरी) होगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुऐं प्राप्त करने के लिए परिवार के 3 सदस्यों के उंगलियों के निशान स्मार्ट कार्ड में संग्रहीत किये जायेंगे तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुऐं अधिकृत प्राप्तकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के बाद ही जारी की जायेंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लेनदेन वास्तविक उपभोक्ताओं को ही हुआ है। हरियाणा में स्मार्ट कार्ड प्रोजैक्ट की विशेषता यह है कि इसका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किये जा रहे आधार कार्ड के साथ समावेश किया गया है।

6. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा पूर्ण बॉयोमीट्रिक पुनर्मिलान करने के बाद खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा ये कार्ड जारी किये जायेंगे जिनमें यह सुनिश्चित होगा कि फर्जी तथा नकली राशन कार्ड बनने का सिलसिला हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की मासिक पात्रता भी स्मार्ट राशन कार्ड की चिप में संग्रहीत की जायेगी।

7. प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के मालिक को एक सुरक्षा स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित प्रत्येक परिवार की मासिक पात्रता निहित होगी। उचित मूल्य की दुकान के मालिक को एक आधुनिक बिक्री उपकरण उपलब्ध करवाया जायेगा जोकि बेचे जाने वाले सामान की प्रक्रिया में सहायता करेगा। यह उपकरण लाभार्थी के कार्ड और उंगलियों के निशानों का सत्यापन करने में सक्षम होगा।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

8. परियोजना के पहले चरण में चार खण्डों अम्बाला, सिरसा, सोनीपत व घरौंडा को प्रायोगिक आधार पर चुना गया है। इन चार खण्डों में सभी परिवारों के 12 साल से ऊपर के सभी सदस्यों की दसों उंगलियों के निशान लेने हेतू शिविर आयोजित किये गये हैं। इसके अलावा परिवार में 5 साल की उम्र से ऊपर के सदस्यों का आईरिस डाटा भी पुर्नमिलान हेतू लिया गया है। यह डाटा यूआईडी को पुर्नमिलान व आधार नम्बर जारी करने के लिए भेज दिया गया है।

आज तक 6.40 लाख निवासियों का डाटा डिजीटल किया गया है। जिसमें से 5.80 लाख निवासी शिविरों में भाग ले चुके हैं तथा 4.32 लाख को यूआईडी संख्या जारी की जा चुकी है। आवश्यक तकनीकी ढांचे को हरियाणा राज्य डाटा केन्द्र में स्थापित कर दिया गया है तथा खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मुख्यालय में एक विशेष आई.टी. सेल स्थापित कर दिया गया है। परियोजना के जून 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों को कितना (गेहूं, शूगर, करोसीन ऑयल) राशन दिया जाता है और उसका सारा खर्चा कौन वहन करता है? इसी तरह से ए.पी.एल. कार्ड धारकों को कितना राशन दिया जाता है और उसका सारा खर्चा कौन वहन करता है? इसके अतिरिक्त ए.पी.एल. का कितना शेयर बी.पी.एल. में कन्वर्ट किया जाता है? आज के दिन सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या यह है कि ए.पी.एल. कार्ड धारकों को कोई रिलीफ नहीं मिलता। APL card is above poverty line उनका राशन बी.पी.एल. में कन्वर्ट किया जाता है बाकी राशन मार्केट में बिकता है। इसका कारण यह है कि ए.पी.एल. कार्ड धारकों को 10 किलो राशन मिलता है और 10 किलो राशन लेने के लिए ए.पी.एल. कार्ड धारक डिपू होल्डर के पास नहीं जाते। मंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि ए.पी.एल. का कितना राशन कन्वर्ट किया जाता है और कितना राशन नॉन यूटीलाईजेशन में जाता है? आज के दिन बी.पी.एल. की एक ज्वलंत समस्या हमारे सामने है और बी.पी.एल. कार्ड बनाने के साथ-साथ इस पूरे सिस्टम में भी इम्प्रूवमैंट होनी चाहिए क्योंकि जब एक बार राशन कार्ड बन जाता है फिर उसको बाद में नॉर्म्ज़ फुलफिल न करने के कारण काटते हैं इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो वह क्यों होता है, क्या इसके ऊपर गवर्नमैंट मशीनरी प्रॉपर वर्क करती है या नहीं करती है और उसके बाद उसमें क्या मॉनिटरिंग है? गलत बी.पी.एल. कार्ड को बनाने के लिए who is responsible ? क्या कन्ज्युमर रिस्पांसीबल है या सरकार के अधिकारी रिस्पांसीबल हैं? ये मेरा पहला सप्लीमैंट्री है। मंत्री जी पहले इसके बारे में बतायें उसके बाद मैं अपनी दूसरी सप्लीमैंट्री पूछना चाहूंगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि पी.डी.एस. एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है उस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि पी.डी.एस. सबके लिए नहीं है। इस बारे में पहली बात तो यह है कि इसमें जो ए.ए.वाई. हैं वे गरीबी रेखा से भी नीचे हैं और एक वे हैं जो बी.पी.एल. हैं। जैसा कि मैंने इसमें शुरू में ही कहा था कि गांवों में डी.आर.डी.ए. द्वारा ग्रामीण इलाकों में और अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा शहरों में किये गये सर्वे द्वारा तकरीबन 12.97 लाख परिवारों को आईडैंटीफाई

किया गया है। जो समस्या माननीय सदस्य जी ने उठाई है यह समस्या सारे देश में ही व्याप्त है। जहां तक हमारे राज्य में इस समस्या की बात है वह सारे देश के दूसरे तमाम राज्यों से बहुत कम है। हमारे यहां आबादी और यूनिट के लिहाज़ से तकरीबन 56 लाख के करीब ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. कार्ड हैं। हमारी यूनिट्स 2 करोड़ 48 लाख के करीब हैं। यहां पर फर्जी कार्डों की समस्या नहीं है अगर इस बारे में कहीं कोई समस्या है तो वह ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. कार्ड के बीच की समस्या है। आज हमारे प्रदेश की आबादी 2 करोड़ 55 लाख के करीब है अर्थात् कार्डों और यूनिटों के अंदर बोगस की समस्या नहीं है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य और सदन को यह बताना चाहूंगा कि गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. कार्डों की संख्या को 12.97 लाख पर फिक्स कर दिया है। अभी तक 7.89 लाख कार्ड ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. परिवारों को दिये गये हैं और जो 12.97 लाख में से तकरीबन 4.86 लाख परिवार ऐसे हैं जो बकाया बच गये हैं इनको भी हमने कवर करने का प्रयास किया है। ए.ए.वाई. कार्ड के माध्यम से जो गेहूं अलॉट होती है उसमें से तकरीबन आधा गेहूं जिसकी सबसिडी स्टेट गवर्नमैंट देती है वह उन परिवारों को स्टेट बी.पी.एल. कार्ड के माध्यम से हम दे देते हैं। जो हमारे अब तक के सर्वे के मुताबिक 12.97 लाख कार्ड हैं उन पर 28 करोड़ रुपये के करीब सबसिडी है। इसको इयरमार्क तो 43 करोड़ रुपये किया गया था लेकिन 28 करोड़ रुपये के लगभग सबसिडी सरकार की तरफ से दे करके उनको वह राशन हम मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह किया है कि कितना-कितना लिफ्टिंग एलोकेशन अलग-अलग कैटेगरी का है। यह भी मैं सदन और माननीय सदस्य को बताता हूं। वर्ष 2011-12 के दौरान 2 लाख 34 हज़ार 300 टन गेहूं अलॉट किया गया जिसमें से तकरीबन 2 लाख 19 हज़ार टन गेहूं लिफ्ट किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 1 लाख 3 हज़ार 342 टन गेहूं अलॉट किया गया जिसमें से 98 टन गेहूं अलॉट किया गया है इसके अतिरिक्त 2011-12 ए.ए.वाई. में भारत सरकार द्वारा 3 लाख 30 हज़ार टन गेहूं अलॉट किया गया। यह सारे साल का है। महीनेवार यह तकरीबन 35 हज़ार टन के करीब बनता है जिसमें से 2 लाख 19 हज़ार 800 टन लिफ्ट किया गया। इस गेहूं का स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारी परिवारों को 4.88 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से हम आधा गेहूं ए.ए.वाई. के परिवारों के परिवारों के लिए और बाकी का आधा बी.पी.एल. परिवारों के आबंटन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि तकरीबन 15-16 हज़ार के करीब बनता है।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, असलियत में ए.पी.एल. राशन कार्ड होल्डर्स राशन नहीं लेते। वे 10 किलो लेने जाते हैं तो 9 किलो राशन तो वैसे ही मिलता है और उसमें से भी 1 किलो चक्की वाला काट लेता है, उसका वह क्या करेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि ए.पी.एल. का जो राशन है उसको एस.बी.पी.एल. में कन्वर्ट कर दिया जाये उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राशन मिल सकता है जिससे जो 2 रुपये 15 पैसे की सब्सिडी है वह भी बढ़ जाये। स्पीकर सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ये जो राशन के डिपो होते हैं उनमें तकरीबन 300 से 1200 तक राशन कार्ड होल्डर होते हैं जिनमें 300 बी.पी.एल. के होते हैं। एक डिपो के लिए 2700 रुपये मिलते हैं तो ऐसे में 2700 रुपये में कौन डिपो चलायेगा और कैसे चलायेगा? इससे आप समझ सकते हैं कि ये पिलफ्रिज और लीकेज कहां पर है? इस पर भी सरकार को चैक रखना चाहिए। एक इन्सपैक्टर कितने डिपोज को चैक कर सकता है।

[श्री भारत भूषण बतरा]
60-70 डिपोज एक इन्सपैक्टर के पास होते हैं और वह रैगूलर चैकिंग नहीं कर सकता। इसका भी कोई प्रावधान किया जाना चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्वाइंट आउट किया है वह काफी हद तक सही है। लेकिन जहां तक ए.पी.एल. की बात है हमने इन बातों के मध्यनजर आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको एलोकेट नहीं किया है। उसमें से आधा गेहूं जो हम स्टेट बी.पी.एल. में कन्वर्ट कर सकते थे वह हमने कर दिया है और इसी वजह से हमने उसको रोका है। लेकिन फिल्ड से माँग फिर बढ़ रही है जिनमें आप जैसे पब्लिक रिप्रैजैंटेटिव हैं वे भी कह रहे हैं कि ए.पी.एल. को भी राशन दिया जाना चाहिए। जो लेने वाले हैं वे ले लेते हैं लेकिन यह भी सही है कि इसमें से डायवर्सन की सम्भावना काफी है इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि 2700 रुपये में डिपो होल्डर डिपो को कैसे चला रहा है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका यह सवाल बहुत वाजिब है। 1991 में भी यह सवाल उठाया गया था तब तो एक डिपो होल्डर को 500 रुपये ही मिलते थे, उस समय जो उत्तरी भारत की श्री मैन कमेटी थी मैं भी उसका मैम्बर था। हमने यह सवाल उठाया था कि एक तरफ तो हम डिपो होल्डर पर अंकुश लगाते हैं और ईमानदारी की उम्मीद करते हैं और दूसरी तरफ बेईमानी के लिए खुला छोड़ते हैं। जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो वह कुछ न कुछ तो करेगा ही। उस समय इनका मार्जिन बढ़ाया गया। आज के दिन यह 2700 रुपये नहीं है। मेरे हिसाब से यह 1500 से 2000 रुपये के आसपास है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : मंत्री जी, इसके लिए कुछ कीजिए ना।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : इसके लिए जो मार्जिन है उसको भारत सरकार फिक्स करती है। सब्सिडी सरकार दे रही है। इससे ज्यादा कंज्यूमर पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। इससे ज्यादा या तो स्टेट को वहन करना पड़ेगा। स्टेट पहले ही 28 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। लेकिन यह चिन्ता वाजिब है। इसके लिए हम भारत सरकार से फिर आग्रह करेंगे। यह केवल हरियाणा का ही इश्यू नहीं है बल्कि पूरे देश का है और इसमें हमें मार्जिन बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यता है। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर और कमेटी स्तर पर भी विजिलैंस कमेटी मौजूद हैं और उनकी शिकायतें डिस्ट्रिक्ट ग्रीवैंस में भी और जिला परिषद में भी आती हैं उनका निवारण भी चाहे कोई चोरी की है और चाहे डायवर्सन की है, किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लाई जा रही है जो कि आधार कार्ड से जोड़ कर चलाई जायेगी। यह हमने चार ब्लॉक्स में चालू की है। इसके शुरू होने के बाद इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगेगा कि यह डायवर्सन न हो।

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि क्या पंचकूला जिले में बी.पी.एल. कार्ड से मिलने वाला मिट्टी के तेल का

कोटा क्या बंद कर दिया गया है? अगर बंद कर दिया है तो क्यों किया गया है? अगर यह कोटा दिया जा रहा तो एक ए.पी.एल. कार्ड पर कितना कोटा दिय जा रहा है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ए.पी.एल. का कोटा तो सब जगह ही बंद कर दिया गया है। तीन-चार महीने से बी.पी.एल. के कोटे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। उसमें से कुछ हिस्सा मिट्टी के तेल का हम स्टेट बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्ज के नाम से बांटते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री प्रदीप चौधरी : सर, हमारा एरिया आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मामला उठाया है इसी वजह से ये ए.पी.एल. कार्ड बंद कर दिए गये हैं। अगर इनकी डिमांड है तो इसको बांटना शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है मंत्री जी, आपका जवाब क्लीयर है। Shri Ashok Arora want to make a suggestion please.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बत्रा जी ने कहा कि डीपू होल्डर कोई भी व्यक्ति हो जब तक उसको उसकी मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से चोरी की संभावना बढ़ेगी। अगर चोरी होगी तो BPL के कार्ड होल्डर का राशन कटेगा। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि अगर स्टेट गवर्नमैंट सरकारी दुकानें खोल कर उनसे वितरण कराए तो हो सकता है कि इसमें कुछ कमी आ जाए क्योंकि पहले भी स्टेट गवर्नमैंट ने सरकारी दुकानें खोल कर राशन का वितरण कराया था। आप इस काम को किसी अन-एम्पलाइड आदमी को DC रेट पर करायें तो इससे चोरी भी बचेगी और काम भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मंत्री जी से एक अनुरोध और करूंगा कि पूरे प्रदेश के अन्दर आज रसोई गैस की काला बाजारी बहुत जोरों पर है। इसके बारे में भी आप महकमें की तरफ से ऐसा प्रबन्ध करें ताकि काला बाजारी को रोका जा सके क्योंकि आज रसोई गैस लेने में इतनी लूट मच रही है कि जितनी लूट कभी नहीं हुई। इसके बारे में भी विचार करें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion on the Governor's Address will be resumed. Shri Parminder Singh Dhull will speak now.

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम जी ने जो अभिभाषण 23 तारीख को पढ़ा उसमें विभिन्न मुद्दों पर बात की गई है। विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया गया है। पेज नं० 3 पर किसानों के बारे में बताया गया है। पेज नं० 6 पर सिंचाई से सरोकार बताया है। पेज नं० 10 पर ग्रामीण विकास, पेज नं० 13 पर शिक्षा के बारे में और पेज नं० 15 पर युवा एवं खेल के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष महोदय,

[श्री परमिन्द्र सिंह ढूल]
इस पूरे अभिभाषण के अन्दर जो विवरण दिया गया है, यदि वह उस विवरण के बारे में इस वर्ष कैग की रिपोर्ट के साथ अवलोकन करें जो माननीय गवर्नर साहब के भाषण के बाद इसी महान सदन में पेश की गई तो यह अभिभाषण झूठ का पुलिन्दा साबित होता है। (CAG) कैग की रिपोर्ट में जीन्द जिले के बारे में पेज नं० 4 के पैरा नं० 1.513 में लिखा है :–

"विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास गतिविधियों कार्यान्वियन की स्थिति तथा प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जीन्द जिला केन्द्रिक लेखा परीक्षा संचालित की गई थी। जांच ने प्रकट किया कि जिला योजना समिति ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी। जिला में स्वास्थ्य केन्द्रों, न्यूनतम मूलभूत संरचना तथा डाक्टरों की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप यह शिशु-मृत्युदर, जन्मदर तथा मृत्युदर को कम करने और जन्मपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रवासों इत्यादि में वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में 777 स्कूलों के मुरम्मत कार्यों के निष्पादन की मानिटरिंग की कमी थी, जोकि मानिटरिंग की जानी चाहिए थी। कई स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएँ नहीं थी। 2006-11 के दौरान किए गए 8969 नमूनों में से कुल 851 नमूनों में जीवाणु विज्ञानी सम्मिश्रण थे।" अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अगर इनका अवलोकन पूरे सिलसिलेवार किया जाये तो किसी भी रूप में आज यह गवर्नर साहिब का भाषण किसी भी तरह से विकास करने हेतु हमारे जिले के लिए खरा नहीं उतरता। जिला योजना समिति ने जिले के समग्र विकास हेतु गतिविधियों को आवृत्त करते हुए पंचवर्षीय सदृश योजना तथा एक संगठित जिला योजना तैयार नहीं की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अंतराल चिन्हित करने हेतु घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं किये गये थे, जहां स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य संस्थाओं में डाक्टरों की कमी थी। अध्यक्ष महोदय, चालिस परसैंट डाक्टरों की कमी थी तथा मूल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रदान करने हेतु अपर्याप्त सुविधायें थीं। लगभग 20 से 22 परसैंट अन्य स्टाफ की कमी दिखाई गई। अध्यक्ष महोदय, इसी कैग की रिपोर्ट के पेज नं० 71 पर 2006 से 31 मार्च 2011 तक जींद जिले के समेकित विकास के लिए मात्र 185.45 करोड़ रुपये दिये गये, उसमें से भी 14 करोड़ 75 लाख रुपये आज भी बकाया हैं। इससे ग्रामीण विकास का जो वास्तविक चेहरा है वह माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो लिखा है उसको पढ़ कर पता चलता है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अंतराल चिन्हित करने हेतु घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण किया जाना उपेक्षित था। यह अवलोकित किया गया कि जिले में ऐसा कोई कभी सर्वेक्षण करवाया ही नहीं गया, यह कैग की रिपोर्ट के पेज नं० 72 पर लिखा है। अध्यक्ष महोदय, सी.एच.सी. और पी.एच.सी. की हमारे जिले में बहुत भारी कमी है। लगातार कहने के बाद आज भी 46 सी.एच.सी. और पी.एच.सी. कम हैं। यह मैं नहीं कह रहा बल्कि यह तो कैग की रिपोर्ट कह रही हैं। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट के पेज नं० 75 पर लिखा है कि 6432 कोल्ड चेन उपकरणों में से 1722 आज भी उपकरण खराब पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी रिपोर्ट के पेज नं० 78 पर लिखा है कि 2006 और 2011 के दौरान 91.99 करोड़ रुपये का आबंटन प्राथमिक शिक्षा के लिए किया गया जिसमें से केवल 81 प्रतिशत खर्च किया गया। इसके कारण हमारे जिले के प्राथमिक स्कूलों की स्थिति आज भी अत्यंत नाजुक है। आज भी जिले के अंदर चाहे प्राचार्य हैं चाहे मुख्याध्यापक हैं चाहे अध्यापक हैं इनके अंदर 60 परसैंट की आज भी कमी है। ये सब आपकी सरकार में है, मंत्री जी (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय,

अभी पीछे 2008 में सरकार ने जींद में जाकर पत्थर लगाकर बड़े जोर-शोर से बाई-पास के निर्माण की घोषणा की थी। जोकि 2009 में शुरू होकर के दिसम्बर 2009 तक पूरा होना था। इसके लिए 17.71 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये लेकिन आज भी केवल 3.57 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। कैग ने जब वहां के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि यह काम इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हमारे पास माल अवेलेबल नहीं था जबकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की किताब में लिखा है कि उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि प्रदेश में अन्य जगह भी काम हो रहे थे।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : प्वॉयंट ऑफ आर्डर, सर। स्पीकर सर, सदन के पटल पर भी यह बात बता दी गई थी लेकिन शायद माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं होंगे। जिस एजेंसी ने बाई-पास के निर्माण का काम लिया था वह एजेंसी सीमित समय के अंदर काम नहीं कर पाई। हमने उसका कान्ट्रैक्ट ट्रमिनेट कर दिया और उसकी ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही शुरू कर दी और उसे ब्लैक लिस्ट का नोटिस दे दिया। 29 फरवरी यानि जो माह अभी खत्म हुआ है, उस दिन जो नया टैंडर था उसे खोला गया है और दोबारा से उस काम को किसी नई एजेंसी को अलॉट करके बहुत जल्दी वह पूरा कर दिया जायेगा। मैटीरियल की समस्या है, यह सबको मालूम है पर इसके बावजूद भी दूसरे पड़ोस के राज्यों से मैटीरियल लाकर भी हम यह बाई-पास के निर्माण का काम पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे।

Mr. Speaker : Yes, Hon'ble Member, you may continue, please.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : इसी रिपोर्ट के पेज नं० 87 पर पैरा नंबर 2.3.15.1–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत रजबाहों और नहरों की सफाई के आदेश दिये गये लेकिन उन आदेशों की हमारे जिले में पालना नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आज वहां भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, इन सबसे मुझे बड़ी चिंता हो रही है। सिंचाई के बारे में बड़ा कुछ कहा गया। हमारे इलाके के अंदर सुंदर ब्रांच है जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2611 थी लेकिन 1996 के बाद से आज तक उसकी सफाई न होने की वजह से वह दोनों तरफ से पूरी तरह से अटी पड़ी है और 10-10 फुट बंद है। 2008 में नहर महकमे द्वारा 5 करोड़ रुपये के लगभग की राशि खर्च करके सुंदर नहर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनकी रेजिंग की गई लेकिन इसके बावजूद वह नहर किसी भी दिन 1300-1400 क्यूसिक से ज्यादा नहीं चली। सिर्फ एक बार 2010-11 में बरसात के दिनों में वह तीन दिन कुछ ज्यादा चली थी। सिर्फ तीन दिन वह 1700 क्यूसिक के आसपास चली थी जिसकी वजह से हमारे जींद जिले और भिवानी जिले को नुक्सान हुआ। 1996 से आज तक न हांसी ब्रांच की सफाई हुई है न सुंदर ब्रांच की हुई है। सर, आज किसान को बिजली नहीं मिलती, समय पर खाद नहीं मिलता। उसे घंटों राशन की लाइन में लगकर पांच कट्टे यूरिया खाद के मिलते हैं। वह रात को दो बजे किसान लाइन में लगता है और सुबह जाकर उसे 5 कट्टे मिलते हैं। आज किसान को बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में किसान किस तरह से सिंचाई के कार्य पूरे कर लेगा। अध्यक्ष महोदय, आज यह बहुत ही चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आप मनरेगा स्कीम का अवलोकन करेंगे तो पायेंगे कि मेरे जिले में वर्ष 2008-09 में 22130 पंजीकृत परिवार थे उनमें से केवल मात्र 210 परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। इसी तरह से वर्ष 2009-10 में

[श्री परमिन्द्र सिंह ढूल]
24999 पंजीकृत परिवार थे उनमें से केवल मात्र 96 परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया जो कि प्रतिशत के हिसाब से .038 था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, अब आप वाइंडअप करें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढूल : सर, मेरे एक-दो प्वॉयंट बाकी रह गए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको दो मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढूल : धन्यवाद सर, सर, 2010-11 में पंजीकृत परिवारों की संख्या 27075 थी उनमें से केवल मात्र 137 परिवारों को रोजगार दिया गया, ये भी प्रतिशत के हिसाब से .050 बनता है। मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से आंकड़े आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज सदन में हमारे खेल मंत्री जी ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में बड़ा दावा किया कि सरकार द्वारा गोल्ड मैडलिस्ट खिलाड़ियों को नौकरियां और उनके गांव के विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। मेरे हल्के के गांव फतेहगढ़ से मनीषा दलाल और अकालगढ़ गांव से कप्तान सिंह गोल्ड मैडलिस्ट हैं। इन दोनों को न नौकरी मिली है और न ही गांव को विकास के लिए 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। मेरे हल्के में ग्रामीण क्षेत्र में एक निडानी स्पोर्ट्स स्कूल है वहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायता से खिलाड़ी तैयार किये जाते हैं और वे खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर गोल्ड मैडल प्राप्त करते हैं। उनको दी जाने वाली सारी सुविधायें सरकार ने बंद कर दी हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण से सहमत नहीं हूं क्योंकि यह तथ्यों से मेल नहीं खाता। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : सर, आपने मुझे इस सदन में जो बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर विकास की असत्य गौरव गाथा प्रस्तुत की है उस पर विचार रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। सर, आज हमारा प्रदेश बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। आज प्रदेश पर लगभग इस साल के अन्त तक 52000 करोड़ रुपये का कर्जा हो जायेगा यानी हर आदमी के ऊपर 25000 रुपये कर्जा है। आज जो बच्चा हरियाणा प्रदेश में जन्म ले रहा है वह 25000 रुपये का कर्जा अपने सिर पर लेकर जन्म ले रहा है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** सर, हमारा फिस्कल डैफिसिट बढ़ रहा है। हमारा रेवेन्यू डैफिसिट बढ़ रहा है और जो फाईनैंशिएल डिस्पिलीन हमें एडेहर करना चाहिए और जो फाईनैंशिएल रिसपौंस्बिलिटी एक्ट हमने पारित किया है जिसके तहत सन् 2012 तक हमें रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम उसको एचीव कर पायेंगे। सर, पर-कैपिटा इन्कम के बारे में बताया गया है कि हमारे प्रदेश की पर-कैपिटा इन्कम बढ़ रही है और इसके बारे में और भी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। जी.डी.पी. हमारा 9.6 प्रतिशत है और औद्योगिक विकास दर हमारी 7.9 प्रतिशत है। सर, पहले मैं पर-कैपिटा इन्कम के बारे में बताना चाहता हूं। सर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो पर-कैपिटा इन्कम 1,09,227 रुपये होने की संभावना दर्शाई गई है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि आज

हमारी पर-कैपिटा इन्कम 1,09,227 रुपये है जो वास्तव में सही नहीं है। पहले ये जो आंकड़े हैं ये प्रदेश की उन्नति के प्रतीक नहीं हैं। Sir, this is the mean value of the total Income of the State divided by the population of the State. सर, आप इसे ऐसा उदाहरण मान सकते हैं कि मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और मेरे पास 10 रुपये है तो हमारी पर-कैपिटा इन्कम 55 रुपये होगी और मेरे 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये ही रहेगी 55 रुपये नहीं हो जायेगी। ये आंकड़े पूरी तरह से मिसलीडिंग हैं और इस तरह से प्रदेश को इसमें कोई ईनाम नहीं मिलता क्योंकि पहले नम्बर के इस प्रदेश में जिसमें गरीबी रेखा से नीचे बी.पी.एल. परिवार राशन कार्ड बनाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आज पंचकुला जिले में राशन कार्ड बनाने के लिए संघर्ष करने वालों के जुलूस को हमारे अध्यक्ष लीड करके आये हैं। इस सरकार में लोग राशन कार्ड बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर किसी भी गांव में और किसी भी मौहल्ले में जब हम लोग जाते हैं तो लोग हमारे से सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बनवाने की बात करते हैं। हमारा प्रदेश गरीब और निर्धन हुआ है। ये जो आंकड़े हैं ये ऐसे हैं जो एन.सी.आर. और गुड़गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे बड़े धनी व्यक्ति जरूर हैं लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं लगाया जा सकता कि आज हमारा सारा प्रदेश धनी है या हमारे प्रदेश की बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है या उन्नति हुई है। ये आंकड़े वाजिब नहीं है। सर, जो पर-कैपिटा इन्कम के आंकड़े हैं वे उन 5 प्रतिशत लोगों के हैं जिनके पास देश की 38 प्रतिशत सम्पत्ति है। बाकी के 95 परसैंट लोग जो हैं उनके पास 62 परसैंट सम्पत्ति है। Speaker Sir, gap is widening between the haves and have-nots. सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में जो 77 परसैंट पॉपुलेशन है वह प्रतिदिन 20 रुपये से कम कमाती है। भारत सरकार ने जो बी.पी.एल. का आधार प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से शहर में 32 रुपये तक रोज कमाने वाला और गांव में 26 रुपये तक रोज कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है।

16.00 बजे

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकिशन फौजी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इसके साथ-साथ इस बारे में भी बता दें कि जब सैंटर में इनकी सरकार थी उस समय यह रेशो कितना था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, इनमें यह बहुत बुरी आदत है कि जब भी कोई बात कहो तो ये कहते हैं कि कल क्या होता था तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि कल आदमी जंगल में रहता था और नंगा घूमता था तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आज भी नंगा घूमे। उपाध्यक्ष महोदय, हम आगे की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, आप कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ******

श्री उपाध्यक्ष : इसको रिकॉर्ड न किया जाये। नरेश शर्मा जी, आप बैठिए। विज साहब, आप कंटीन्यू करें।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री मौहम्मद इलियास : उपाध्यक्ष महोदय, ******

श्री नरेश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ******

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी न करें और उनको सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में जो अनपार्लियामैंट्री शब्द कहे गए हैं वे रिकॉर्ड न किए जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, विज साहब ने एक चिंता जाहिर की है और वह चिंता यह थी कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उनकी चिंता वाजिब है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और विज साहब की सहमति से एक बात कहकर अपना स्थान ले लूंगा कि एक जमाना था जब एक सरकार दिल्ली में इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर आई और बहुत सारे लोक लुभावने वायदे इस देश की गरीब जनता से किए। यह सच है कि इस देश के अंदर आजादी के बाद गरीब और अमीर के बीच की खाई धीरे-धीरे बढ़ी है। जब दिल्ली में यू.पी.ए. की सरकार आई तो मनरेगा स्कीम के तहत देश के सबसे गरीब, सबसे कमजोर और सबसे पिछड़े व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि देने का काम किया गया। यू.पी.ए. सरकार के इस काम की तारीफ आपकी पार्टी ने भी की है और दूसरी विपक्षी दलों ने भी की है। (विघ्न) इसी तरह दिल्ली की यू.पी.ए. की सरकार डा० मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में नैशनल रूरल हैल्थ मिशन लेकर आई जिसके तहत आखिरी गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम किया गया है। नैशनल रूरल डिवैल्पमैंट मिशन के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की सबसिडी अलग-अलग फोर्म में गरीब आदमियों तक पहुंचाकर आज यू.पी.ए. की सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि गरीब और अमीर की खाई को पाटा जाये जो बढ़ती जा रही है। हम इण्डिया शाईनिंग का चमकता चेहरा दिखाकर इस देश की गरीबी को छुपाना नहीं चाहते। हम इस देश की गरीबी और गरीबों को ऊपर उठाकर उन्हें स्वाभिमानी और स्वावलम्बी बनाकर एक बराबरी का दर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देने का प्रयास कर रहे हैं। (विघ्न)

डॉ० अजय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, इनको 65 साल राज करते हुए हो गये और ये लगातार गरीबी को ऊपर उठा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अजय जी को बताना चाहूंगा कि हम 65 साल की बात कर देंगे परन्तु ये लोग यह बात भूल जायेंगे जब इनकी सरकार थी तो ये लोग दस-दस रुपये गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ईजाफा किसानों को देकर उनको चलता कर दिया करते थे। (शोर एवं व्यवधान) एन.डी.ए. की इण्डिया शाईनिंग का क्या हुआ गुर्जर साहब यह आपको पता है। अजय सिंह जी उस समय एम.पी. थे और ये भी इण्डिया शाईनिंग की सरकार में शामिल थे। इनके पांच सदस्यों के समर्थन से उस समय

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वह सरकार चलती थी। उसके बाद जब अजय जी उस सरकार को छोड़कर गये उसके बाद भी इन्होंने किसान के पूरे मूल्य के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने कभी यह नहीं कहा कि गेहूं और चावल का किसानों को पूरा मूल्य दिया जाये। उस समय दस-दस रुपये प्रति क्विंटल का भाव बढ़ाया जाता था। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, उस समय अजय जी ने कभी अनुरोध नहीं किया कि किसान की फसल का मूल्य बढ़ाया जाये। अगर ये चाहते तो उस समय समर्थन वापिस ले लेते। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता उस समय इनकी क्या मजबूरियां थी और ये क्यों एन.डी.ए. की सरकार को समर्थन देते रहे लेकिन सच्चाई यह है कि जब से सैंटर में यू.पी.ए. की सरकार को समर्थन देते रहे लेकिन सच्चाई यह है कि जब से सैंटर में यू.पी.ए. की सरकार आई तब से किसान की हालत बदली और डाक्टर मनमोहन सिंह तथा श्रीमति सोनिया जी की सरकार ने 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा एक कलम से किसानों का माफ किया गया। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से व्यवस्था बदलेगी और देश में तबदीली आयेगी। उस तरह से नहीं आयेगी जैसे गुर्जर साहब कह रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि—

तेरे हर सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा,
तेरे एक-एक लफ्ज को मुकम्मल किताब कर दूंगा,
कह दो विरोधियों से थोड़ा इंतजार करें,
वक्त आने पर मुकम्मल हिसाब कर दूंगा। (हंसी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी मानसिकता में यही अंतर है। आदर और मित्रता की बात कहकर ये विरोध और प्रतिरोध के नजरिये से देखते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक शेर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं मुझे बीच में इन्ट्रप्ट न किया जाये। सर, 6 महीने के बाद सैशन हो रहा है और केवल 8 सीटिंग्ज रखी गई हैं इसलिए जो 400 प्रश्न लगे हैं वे पूरे लिस्ट नहीं हो रहे। इस बारे में मैं उपाध्यक्ष महोदय सुझाव देना चाहता हूं और आप कर सकते हैं कि जितने भी हमारे तारांकित प्रश्न हैं जो लग नहीं पाते बेशक उनको अतारांकित कर दिया जाये लेकिन विभाग की तरफ से जवाब दे दिया जाये। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आज डैमोक्रेसी में हालत यह हो गई है कि हमारे देश में और प्रदेश में आफिसर्ज रिप्लाई नहीं देते। ऐसी हालत है कि या तो हमारा प्रश्न लगता ही नहीं और लगता भी है तो उसका जवाब नहीं आता है अगर किसी का उत्तर भी आ जाता है तो उस पर अमल नहीं होता। इस बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा कि मैंने सदन में कुछ प्रश्न उठाये और उनका 'हां' में उत्तर आया। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर विधान सभा सचिवालय की कार्य प्रणाली के बारे में श्री विज को किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो उसके बारे में वे आपको लिखित में दे सकते हैं क्योंकि इस समय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है न कि विधान सभा सचिवालय का मामला इस समय चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अनिल विज जी, आप कृपया गवर्नर एड्रैस पर ही बोलें ।

श्री अनिल विज : डिप्टी स्पीकर सर, मैं उसी पर आ रहा हूं । मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि हम सब यहां बैठकर जनता को क्या संदेश दे रहे हैं । जैसे सदस्यों को सदन में आश्वासन दे दिया जाता है । किसी सदस्य द्वारा कोई विषय उठाने पर सरकार द्वारा उस बारे में आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता । यह बात भी ठीक है कि इस बारे में विधान सभा में आश्वासन समिति का गठन भी किया हुआ है लेकिन वह तो किसी भी मामले को 5 से 10 साल के अंदर देखती है इतने लम्बे समय के बाद तो बहुत देर हो चुकी होती है । पिछले सत्र के दौरान मेरा अम्बाला कैंट में हाउस टैक्स की रिकवरी के बारे में क्वैश्चन था । मंत्री जी ने तब मुझे हाउस में यह कहते हुए आश्वासन दिया था कि आप बिल की कॉपी मुझे दे देना मैं उसे देख लूंगा कि ये बिल किसने और कैसे दिये हैं । अगर गलत बिल इश्यू हो गये होंगे तो उन्हें वापस ले लिया जायेगा और अगर किसी ने बिल जमा करवा दिये होंगे तो उस अमाउंट को आगे के बिलों में एडजस्ट कर दिया जायेगा । यह इस सदन में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने वे बिल वापिस नहीं लिये और इन बिलों की रिकवरी के लिए सारे के सारे शहर में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवरी के नोटिस जारी कर दिये गये । इस सदन में दिये गये आश्वासनों के बारे में सरकार क्या एक्शन लेती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं । इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि 1857 की जो क्रांति अम्बाला छावनी से आरम्भ हुई थी । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : अनिल विज जी, अब आप कृपया गवर्नर एड्रैस पर आ जायें ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं । जब हमें कहीं और बोलने नहीं दिया जाता तो जब मौका मिलेगा तभी हमें सारी बातें बोलनी पड़ेंगी । हमें अपने हल्के की बात भी करनी होती है और सदन की बात भी बोलनी होती है । डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने 10 मार्च, 2010 को सदन के अंदर आश्वासन दिया था कि अम्बाला छावनी में 1857 की आजादी की लड़ाई की जो पहली क्रांति हुई थी उसके शहीदों की याद में अम्बाला कैंट में एक मैमोरियल बनाया जायेगा लेकिन अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ । अभी तक तीन बार ज़मीन सुनिश्चित करने के लिए तारीख तय की गई लेकिन उससे आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि सरकार के पास शहीदों के लिए समय ही नहीं है । इसी प्रकार से इण्डियन ऑयल के डिपो को शिफ्ट करने की बात कही गई थी जिसके ऊपर यहां पर 'हां' में जवाब दिया गया था लेकिन वहां पर भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है । इसी प्रकार से वैट की बात कही गई थी कि सिलैण्डर से वैट हटाया जायेगा लेकिन इस बारे में भी अभी तक कोई काम नहीं किया गया जबकि सरकार द्वारा शराब से वैट कुछ कम किया गया है । इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से हमारे शहर में जो साईंटिफिक इण्डस्ट्री है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । Sir, Ambala was known as a city for scientific goods. जो कि आज के समय में पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है । मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे । माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे नहीं हैं अगर वे यहां बैठे होते तो ज़रूर कुछ रिलीफ देते । इस इण्डस्ट्री को वैट से रिलीफ की आवश्यकता है क्योंकि बाकी प्रदेशों में या तो इस इण्डस्ट्री पर वैट नहीं है और कहीं है भी तो

वह मात्र 4 प्रतिशत जबकि हमारी स्टेट के अंदर यह टैक्स 12 प्रतिशत है । मैं चाहता हूं कि इस टैक्स को खत्म किया जाये ताकि अम्बाला की जो साईंटिफिक इण्डस्ट्री है, जिसके कारण अम्बाला की सारे विश्व में अपनी विशेष पहचान है, उसको बचाया जाये । जब इण्डस्ट्री की बात आयेगी उस समय इस बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा । यह छोटी सी बात मैंने पहले कह दी है । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो सारे प्रदेश के व्यापारियों के ऊपर जो फार्म 38 है उसे अगर खत्म किया जाता है तो यह बहुत अच्छी बात होगी और अगर सरकार उसको खत्म नहीं कर सकती तो उसकी लिमिट जरूर बढ़ाई जानी चाहिए । आज के दिन उसकी लिमिट 25 हजार है और सभी व्यापारी इसकी मांग कर रहे हैं कि उसकी लिमिट बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी जानी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवालिया निकला हुआ है । मंत्री जी इस बात को अन्यथा न लें क्योंकि मैं आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं । जिस दिन से इस सरकार ने प्रदेश की बागडोर सम्भाली है तब से क्राइम रेट डबल हो गया है । 2005 में जहां रेप के 461 थे वहीं आज के दिन 717 हो गये हैं । इसी प्रकार से 2005 में किडनैपिंग के 493 मामले थे जो कि आज 950 हो गये हैं । 2005 में अगर चोरी की घटनाएं 8649 होती थी जो कि आज 16234 हो गई हैं । 2005 में डकैती के 88 मामले थे जो कि आज बढ़कर 146 हो गये हैं । इसी प्रकार से अगर मर्डर की बात की जाये तो 2005 में 782 केस थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बताया जाये कि अपराधियों को संरक्षण कौन देता था? आपको सभी सदस्यों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए । कभी विज साहब गालिब बनकर खड़े हो जाते हैं और कभी बड़ी-बड़ी भूमिकाएं बांधते हैं । बाकी सदस्यों को भी तो बोलना है । ये गवर्नर ऐड्रैस पर तो एक शब्द भी नहीं बोले हैं । ये रैली की तरह से भाषण कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकॉर्ड आँकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं हालांकि यह विडम्बना है कि पुलिस विभाग ने 2005 के बाद अपनी वैबसाईट पर इन आँकड़ों को अपडेट नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि यह गलत चीज है और यह लोगों तक नहीं जानी चाहिए । लेकिन ये आँकड़े मैंने हासिल किये हैं और ये करैक्ट आँकड़े हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । सर, मेरे काबिल दोस्त श्री अनिल विज जी सारी व्यवस्था के आँकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं । वे यह भूल रहे हैं कि जब ये भी 1999-2005 में उस सरकार का हिस्सा थे और उसके बाद जिन्होंने इनको बीच में ही छोड़ दिया और अब ये दूसरी जगह चले गये हैं और अब की बार हरियाणा में इनकी पार्टी किसके साथ जायेगी इस बात का कोई फैसला नहीं हुआ है । There was a complete ban on registration of FIR during the government when Shri Anil Vij's party was part of power in Haryana. An FIR could not be lodged by an ordinary person. He could not come to a police station and without the consent of those in power at that point of time, there was no pre-registration of FIR. (Interruption) For the first time, we have permitted it. Crimes and criminals were given protection at that point of time. I am saying on record with

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
some sense of responsibility that those who were convicted for murder, those who were convicted for NDPS, were released by the Cabinet at that point of time. Such a shamful act. They were released by the Cabinet. Those who were convicted under NDPS Act right upto the Supreme Court, those who were convicted for molestation charges, those who were convicted for murder and those who were convicted for dacoity, were released by their Government of which Shri Anil Vij was a part. On a top of that, non-criminals were kept in police custody in jails. The then people who were in power and some of them who are present in the House today, they used to go and meet the criminals who were convicted by the Courts in Rohtak Jail and other Jails. That was the atmosphere. Crimes and criminals were given protection and we have ended all that. All the criminals who had unorganized gangs, they have to leave Haryana and Ch. Bhupinder Singh Hooda led Congress Government ensures that the law and order and the rule of law prevails in the State, that is what we have done, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, आप कंकल्यूड कीजिए ।

श्री अनिल विज : सर, मेरा सारा टाईम तो ये खा जाते हैं । सर, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं । मैं तो अपने चारों साथियों का समय भी ले रहा हूं । सर, मैंने रिकॉर्ड से आँकड़े बताने की कोशिश की है । डिप्टी स्पीकर सर, मैं क्राईम के बारे में बात कर रहा हूं । सर, रोजाना घटनाएँ हो रही हैं, अगर एवरेज लगायें तो रोजाना तीन कत्ल होते हैं, दो बलात्कार होते हैं, एक लूट की घटना होती है और एक दहेज हत्या होती है । अभी कई चर्चित कांड भी हुए हैं । करनाल में पूर्व सरपंच की हत्या का कांड, कुरुक्षेत्र में स्वीटी हत्या कांड, रोहतक में मुख्यमंत्री की कांस्टीच्यूएंशी में सी.जे.एम. के घर का ताला तोड़कर चोरी की गई । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जयवीर सिंह) : डिप्टी स्पीकर सर, 6 फरवरी को एक गाड़ी पकड़ी गई जिसका नम्बर और फोटोग्राफ भी साथ हैं, वह वेरना गाड़ी है, उस पर लालबत्ती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है I.N.L.D. और उस गाड़ी पर हरी झंडी लगी हुई थी । मेरे पास एफ.आई.आर. की कॉपी है । (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए ।)**

Mr. Speaker : Vij Ji, your time is getting over.

श्री अनिल विज : नहीं सर, मुझे तो बोलने ही नहीं दे है । Sir, my time has been eaten away by all these Members.

Mr. Speaker : You are speaking for the last 28 minutes.

श्री अनिल विज : सर, मैं दो मिनट भी नहीं बोला हूं । मैं अपने चारों मैंबरों का टाईम लेना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश शर्मा : ये प्रजातंत्र का हनन कर रहे हैं और लोगों के समय को बर्बाद कर रहे हैं, उन पर अपनी बात थोप रहे हैं । ये कह रहे हैं कि मैं अपने चारों सदस्यों का भी टाईम

ले रहा हूं जबकि एक बार भी उन्होंने इनका इस बात के लिए समर्थन नहीं किया कि हम उसको टाईम दे रहे हैं। ये अपनी बात जबरदस्ती थोप रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इनको address करते हुए ऑनरेबल मैंबर कहिये, माननीय सदस्य कहिये, 'ये' कहने का क्या मतलब है?

श्री नरेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये भाई अपने आपको अपने साथियों पर थोप रहे हैं, प्रजातन्त्र का हनन कर रहे हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं।

Mr. Speaker : You have two more minutes please.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी अनिल विज जी बोले ही कहां हैं।

श्री अनिल विज : सर, प्रदेश की कानून-व्यवस्था का दिवाला निकाला हुआ है। मैंने आंकड़ों सहित अपनी बात रखने की कोशिश की है। हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी बैठे हैं। हमारे प्रदेश की सड़कों का भी बुरा हाल पड़ा है। वर्ष 2010 में सारे प्रदेश में 10934 एक्सीडैंट हुए हैं, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसमें 4724 लोगों की जान गई हैं। जिन लोगों की जान गई है उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेवारी ओटनी पड़ेगी। मेरा सैपरेट क्वैश्चन भी था। साहा स्कूल का इंसीडैंट भी हुआ है, पानीपत में भी इंसीडैंट हुआ है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इंसीडैंटस हुए हैं जोकि एक गंभीर चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, यह बातें अगर हम इस महान सदन के अंदर नहीं रखेंगे तो और कौन सा मंच है जहां हम इन बातों को रखें? क्या कभी सरकार इनके ऊपर विचार करेगी? आज इंपलॉइज की बात की गई है। आज प्रदेश में नौकरियों की जिस प्रकार से तिजारत हो रही हैं वह सबके सामने हैं। नये लोगों को रोजगार देने की बात तो दूर रही आज तो पुराने लगे हुए कर्मचारियों का भी शोषण किया जा रहा है जिसका थोड़ा सा चित्र मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। सरकार ने गैस्ट टीचर भर्ती कर लिये। एक नई टर्म निकाल दी गैस्ट टीचर की। अध्यक्ष महोदय, आज उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय है कि where they will go? उनका क्या होगा? आज उनके वेतन में भी बहुत बड़ी भिन्नता है। आज जो एक गैस्ट टीचर जे.बी.टी. है उसको 14 हजार रुपये मिलते हैं और जो रैगूलर है उसको 28 हजार रुपये मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कितने शोषण की बात है। एक गैस्ट टीचर के लिए कोई गारंटी भी नहीं है कि कल को उसको नौकरी पर रखा भी जायेगा या नहीं। आज कई गैस्ट टीचर तो 50 साल की उम्र क्रास कर चुके हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, the matter is in Court. Please do not comment on this.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट केस तो खत्म हो गया है। उनका तो अभी निपटान हुआ भी नहीं था कि सरकार ने एक लाख पात्र अध्यापकों की फौज और तैयार कर ली। वे भी रोजाना भटकते रहते हैं। वह बेचारे कहां जायेंगे और कब उनको रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, कल कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल भी हुई कि उन्हें पक्का किया जाये।

Mr. Speaker : Thank you very much. You have finished your time. आपके 32 मिनट हो गये ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, 32 मिनट तो दूर की बात अभी तक तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आदर पूर्वक बोल रहा हूं और आपको मेरी बात सुननी चाहिए । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुझे जो भी मिनट्स मिलते हैं उसमें से सारे मिनट्स तो यह नरेश शर्मा खराब कर देता है ।

श्री अध्यक्ष : विज साहिब, आप ऐसे मत बोलिये इनको माननीय सदस्य कहिये ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, नरेश जी आदणीय सदस्य ही हैं पर आप उस पर कुछ लगाम तो लगाईये । यह जब चाहे बीच में खड़ा हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : विज साहिब, आप फिर अशोभनीय तरीके से बोल रहे हो । प्लीज, शालीनता का परिचय दें ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी सी.पी.एस. साहिब ने कुछ बिंदुओं/प्वॉयंट्स पर विस्तार से अपना जवाब दिया जोकि उनका राईट है । जो उन्होंने बोलने में टाईम लिया उस टाईम को मेरे टाईम से काटना चाहिए और इसके साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम लिखकर दिया है कि जो टाईम हमारी पार्टी को बोलने के लिए मिलेगा उस सारे टाईम पर मैं ही अपने दल की तरफ से बोलूंगा और बजट पर जो भी चर्चा होगी उस पर हमारी पार्टी के दूसरे सदस्य बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : विज साहिब, क्या आप चेयर को निर्देशित कर रहे हैं?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं यह तो हैल्दी ट्रेडीशन्स है और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : सम्मानित सदस्य, आपने मुझे निर्देशित किया है । You cannot direct me.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप तो हाउस के कस्टोडियन हैं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है विज साहिब, बोलिये और केवल दो मिनट में ही कम्पलीट कीजिये, दूसरे मैंबर्स को भी बोलना है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बहुत बोलना है । मुझे इम्पलाईज की बात कहनी है जिनके भविष्य को खराब किया जा रहा है । मैं भूना शुगर मिल्ज की बात करना चाहता हूं जोकि 158 एकड़ में मशीनरी युक्त है उसको 40 करोड़ में बेच दिया गया । 20 करोड़ रुपया तो कैश आया और जो 20 करोड़ रुपये का चैक आया वह बाऊंस हो गया । आज भूना शुगर मिल्ज के 500 कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, वे बेचारे कहां जायेंगे? आज उनका भविष्य अंधकारमय है । अध्यक्ष महोदय, यह जो पी.पी.पी. और फ्रांचाईज का सिस्टम चलाया गया है.....(शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश शर्मा : स्पीकर सर, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि एम.आई.टी.सी. के जो कर्मचारी हटाये थे वे कहां जायेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, नरेश जी बगैर आपकी इजाजत के कैसे बोल रहे हैं? बोलने के लिए खड़ा होकर नहीं बल्कि बैठकर हाथ उठाकर परमिशन ली जाती है?

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आपको कम से कम बैठे-बैठे हाथ उठाकर यह तो कहना चाहिए था कि मैं बोलूंगा।

श्री नरेश शर्मा : स्पीकर सर, माननीय साथी बोल रहा था और मैंने आपकी इजाजत ली है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप बैठ जाईये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो ठेकेदारी प्रथा है, यह खत्म की जाए।

Mr. Speaker : Vij Sahib, please take the business of the House seriously.

श्री अनिल विज : सर, मैं सीरियसली ही ले रहा हूं। यह जो ठेकेदारी प्रथा है इससे ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। सर, मैं आपके समक्ष पंचकूला का ई.पी.एफ. स्कैम रखना चाहता हूं। जो सफाई कर्मचारी नगर परिषदों में होते हैं उनका ई.पी.एफ. कटता है, वह राशि उनके खातों में जमा होनी चाहिए लेकिन ठेकेदार उस राशि को संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा नहीं करवाते हैं। पंचकूला का मामला तो सामने आया है। पंचकूला ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर शहर में ऐसा हो रहा है। इसमें 320 रुपये सफाई कर्मचारी के कटते हैं और 80 रुपये कंट्रैक्टर ने अपनी तरफ से जमा कराने होते हैं। 500 कर्मचारी हैं और एक साल में कुल मिलाकर यह राशि 43 लाख 20 हजार रुपये बनती है। यह तो अकेले पंचकूला की बात है इस प्रकार हरियाणा की किसी भी कमेटी में यह पैसा जमा नहीं होता है। इस प्रकार से बहुत भारी शोषण कर्मचारियों का हो रहा है। इसी तरह से बिजली बोर्ड में जो लाइनमैन लगे हुए हैं उनकी ड्यूटी के वक्त किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलते समय सदन में कोई असत्य बात न कहें। हमारे विभाग में यदि कोई लाइनमैन ड्यूटी के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में दी जाती है।

Mr. Speaker : Anil Vij ji, you have finished your time. Please conclude your speech. I am calling next speaker to speak.

श्री अनिल विज : सर, मैं अब हल्के की दो एक बातें कह देता हूं। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की माली हालत बहुत खराब है। ओल्ड-ऐज पेंशन नहीं मिल रही

[श्री अनिल विज]
है । मैं दो बातें और करूंगा । इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना को सरकार द्वारा चलाए हुए लगभग डेढ़ साल हो गया है । लोगों के विवाह के बाद बच्चे भी हो गए हैं लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला ।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि उनकी नॉलेज में यदि कोई ऐसा केस लम्बित है तो जरूर बता दें, हम उनके खाते में पैसा डाल देंगे और माननीय सदस्य की समस्या का जरूर समाधान करेंगे ।

श्री अनिल विज : सर, गवर्नर साहब के ऐड्रस पर श्री विनोद शर्मा जी ने यहां प्रस्ताव मूव किया था और उस पर बोलते हुए उन्होंने अनेकों बातें कहीं थी, उनके साथ ही यह भी कहा कि अम्बाला में आई.एम.टी. की स्थापना पर दोबारा विचार होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से वहां के लोगों ने संघर्ष करके पंजोखरा में जो आई.एम.टी. लग रही थी, उससे जान छुड़ाई । इसके पक्ष में वे कहते हैं कि इससे लोगों को रोजगार मिलता है । अगर रोजगार मिलता है तो वे अपने हल्के में आई.एम.टी. लगवा लें । मेरे हल्के का क्यों नाश कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब आप लास्ट लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ऐग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी बातें यहां पर की गईं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप अपने हल्के की बात करिए । आप अम्बाला कैंट की बात नहीं कर रहे हैं । वहां के लोग क्या सोचेंगे । प्लीज, अब आप बैठ जाइए ।

श्री अनिल विज : सर, हल्के की बात भी कहना चाहता हूं । सर, आज प्रदेश में जाट आन्दोलन चल रहा है यही बात मैं जीरो आवर में भी कहना चाहता था । उसके बारे में मेरा शुरू से ही यह कहना है कि जब सदन चल रहा है तो सदन की गरिमा यह कहती है.....

Mr. Speaker : Are you speaking on Governor Address ?

श्री अनिल विज : सर, लॉ एण्ड आर्डर का मामला है । इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सदन चल रहा है और माननीय मन्त्री और मुख्यमंत्री सदन से बाहर ब्यान देते हैं, सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए उनको जो कहना है वह सदन के अन्दर कहना चाहिए । हमारे कैप्टन यादव साहब ने कहा कि रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए । मुख्यमंत्री जी से कल पीपली में किसानों की बात हुई है । We have a right to know, Sir. क्या बात हुई है? कब यह matter resolve होगा? कब प्रदेश में शान्ति होगी? यह बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, प्लीज आप बैठ जाईये । आपका मैटर कम्पलीट हो गया है । आपको बजट पर फिर बोलने का समय देंगे ।

श्री कृष्ण लाल पंवार (इसराना, एस.सी.) : स्पीकर सर, 23 फरवरी, 2012 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण पढ़ा है उसको पूरा पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि सरकार ने बड़े बलंग-बांग दावे किये कि आज हरियाणा प्रदेश में किसानों को बहुत बिजली दी जा रही है, उद्यमियों को बहुत बिजली दी जा रही है। स्पीकर सर, आज प्रदेश के अन्दर बिजली नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां सरकार किसानों को 20-22 घण्टे बिजली देने की बात करती है वहां किसानों को 4-6 घण्टे बिजली भी नहीं मिल पा रही है। आज की मौजूदा सरकार ने सबसे ज्यादा बिजली का प्रोडैक्शन करने का दावा किया है। पिछली बार सदन में आपने मुझे कहा था कि मैं कोई सुझाव दूं और सरकार उस पर अमल जरूर करेगी। उस समय भी मैंने इस सदन में एक सुझाव दिया था कि दीन बन्धु छोटुराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर की 300-300 मैगावाट की दो यूनिट्स हैं जो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार के समय में उनका टैण्डर लगाया गया था लेकिन उस टैण्डर का ऐसी कम्पनी को टैण्डर दे दिया जिसके द्वारा सारी मशीनरी चाईना से मंगाई गई। पिछली बार एक यूनिट का इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रैसिपिरेटर का डक्ट टूट कर नीचे पड़ गया था इसलिए उस इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रैसिपिरेटर को ठीक करवाने के लिए और उस दौरान जो लौस हुआ उसको मिलाकर कम से कम 500-700 करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान हुआ। अब की बार 25 दिसम्बर 2011 को दूसरी 300 मैगावाट दो नम्बर यूनिट में जो टरबाईन होती है उसमें 540 डिग्री का टैम्प्रेचर का प्रैशर एल.पी. और एच.पी. गलैण्ड में जाता है जब इस टरबाईन में वैक्यूम प्रैशर देना चालू किया तो टरबाईन की ड्रेन में जो पानी था वह वैक्यूम प्रैशर से टरबाईन के अन्दर चला गया जिससे टरबाईन का रूटर खराब हो गया। उसके बाद स्टीम को कन्डैन्सड किया जाता है लेकिन उसके नीचे जो ड्रेन लगी होती है वह यू आकार की लगी हुई थी जबकि होना यह चाहिए कि एच.पी. गलैण्ड की ड्रेन डायरेक्ट जाए और एल.पी. की डायरेक्ट जाए। जब टरबाईन को रोलिंग किया गया तो कम्प्रैशर से उसमें पानी एन्टर कर गया और रूटर खराब हो गया। उस रूटर को ठीक कराने के लिए 25 सितम्बर से सरकार की आंखें नहीं खुली और सरकार को 75 लाख यूनिट पर डे का और उत्पादन न होने के कारण कम से कम 3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 25 सितम्बर, 2011 से जनवरी, 2012 तक इस टरबाईन का रोलर ठीक नहीं करवाया गया जिस पर 2 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। अगर नया रूटर लेकर आयेंगे तो कम से कम 100 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। इसके अलावा स्पीकर सर, उसका जो पी.एल.एफ. हुआ वह वर्ष 2010-2011 में 62.6 प्रतिशत और वर्ष 2011-12 में 41.14 प्रतिशत हुआ है इस प्रकार जनरेशन बहुत कम हुआ है। इसी प्रकार से पानीपत थर्मल पावर प्लांट का 8.11.2011 को इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रैसिपिरेटर होता है उसका डक्ट भी टूटकर नीचे गिर गया क्योंकि उसके अन्दर ऐश भर गई जबकि एनवार्यनमैंट और फोरेस्ट मिनिस्ट्री, भारत सरकार ने यह कहा है कि इस ऐश का 100 प्रतिशत यूटिलाईजेशन होना चाहिए लेकिन वहां एम्बुजा सीमेन्ट फैक्टरी जोकि कम रेट पर ऐश उठाती थी और ऐश प्लांट का आपरेशन करती थी और इस प्लांट की मेन्टीनैंस का सारा खर्च वहन करती थी सरकार ने उस कम्पनी को दौड़ा दिया। अब थर्मल प्लांट की मेन्टीनैंस पर करोड़ों रुपये खर्च होता है परन्तु ऐश का यूटीलाईज न होने के कारण ई.एस.पी. टूटकर नीचे गिर गया। फिर सरकार ने सोचा कि प्रदेश के लोग इस बात के लिए उन्हें टोकेंगे इसलिए इन्होंने एक चालाकी की कि जो एक स्टैंड बाई लाइन होता है, उस स्टैंड बाई लाइन को चलाया और

[श्री कृष्ण लाल पंवार]
उसमें तेल फायर किया। अध्यक्ष महोदय, उसमें दो करोड़ का तेल जलाया गया और 12 करोड़ का हमारा जैनरेशन लोस हुआ। उसके बाद टरबाइन में वायबरेशन आने के कारण टरबाइन भी बैठ गई और वह यूनिट आज तक बंद पड़ा है और इससे एक बहुत बड़ा इंसीडैंट वहां हो सकता है। पानीपत थर्मल प्लांट पर एक ऐश डाईक है जिसका 3 किलोमीटर का रेडियस है। सातवें-आठवें यूनिट की सारी ऐश उसमें जाती है। पूरे हिन्दुस्तान में कोई भी ऐश डाईक 4 मीटर से ज्यादा ऊपर तक नहीं उठाई गई लेकिन इस सरकार में पानीपत की थर्मल प्लांट की उस ऐश डाईक की ऊंचाई 20-22 मीटर है और 8 मीटर तो उसमें केवल राख से वाइडनिंग किया गया है। आज उसके यह हालात हैं कि वह ऐश डाईक ऐश से ओवर फलो हो चुका है और कभी भी वहां से लीकेज होने के बाद वहां पर बहुत बड़ी कैज्युलिटी हो सकती है। सुताना गांव उसके साथ ही पड़ता है। सुताना गांव की 300 एकड़ जमीन में उस ऐश डाईक से सेम आ चुकी है। वहां पर कई सालों से फसल नहीं हो रही है। वहां के किसान बार-बार सरकार से कहते हैं कि हमारी जमीन एक्वायर कर ली जाए लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बिजली पैदा करने के बाद जो सुचयाड़ होता है वह खुखड़ाना और सुताना गांव की 55 एकड़ जमीन में आ जाता है और वहां के किसान 25 सालों से रो रहे हैं कि हमें इसके लिए मुआवजा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप कभी वहां से गुजरें तो देखें कि वहां एक तालाब बना हुआ है। (विघ्न) 1979 में पहली यूनिट ने जैनरेशन शुरू किया था। (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकिशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि माननीय साथी ने यह कहा कि 25 साल से किसान वहां रो रहा है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये 5 साल तक मौज करके चले गये इन्होंने उस समय किसान की सुध क्यों नहीं ली? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, खुखड़ाना गांव उसके साथ अटैच है और वहां ऐश आ जाती है इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 52 एकड़ जमीन शिफ्ट करने के लिए सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन किया था। हमारी सरकार जाने के बाद उस स्कीम को इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और मजबूरन लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट से अब डायरैक्शन हुई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गांव के लोगों को सहूलियतें देने के लिए उस जमीन को शिफ्ट करने के लिए सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन किया था।

श्री रामकिशन फौजी : उस समय किस भाव में जमीन को शिफ्ट करने का डिसीजन हुआ था?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 4 के तहत उस समय गांव को शिफ्ट करने के लिए जो रेट होता था वह किसान को मिलना था। उस समय का जो मार्किट रेट था वह किसान को मिलना था।

श्री अध्यक्ष : उस समय क्या रेट था?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, उस समय कम से कम 4-5 लाख रुपये प्रति एकड़ एग्रीकल्चर का रेट था। यह वर्ष 2000 की बात है और 2000 के बाद महंगाई बहुत बढ़ी है। जमीनों के रेट बहुत बढ़े हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गांव के लोगों को सहूलियतें देने के लिए गांव को शिफ्ट करने के लिए उस जमीन का सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि चूंकि यह बड़ा सैंसटेटिव मामला है इसलिए मंत्री जी को वहां तुरंत दौरा करना चाहिए नहीं तो वहां बहुत बड़ा इंसीडैंट हो सकता है। इसके इलावा मैंने एक सवाल में एक रिक्वैस्ट यह भी की थी कि उस गांव की 700 एकड़ जमीन ऐश डाईक में चली गई जिसमें से 300 एकड़ जमीन सेम में है। किसानों के पास अब खेती करने के लिए कम जमीन बची है। वहां डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा ऐसा है जहां लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है। लोग बार-बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारे इस डेढ़ किलोमीटर टुकड़े का रास्ता बना दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उन लोगों की भावना की कद्र करते हुए वह टुकड़ा अवश्य बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे थर्मल पावर प्लांट्स की प्रोडैक्शन डाउन होने की बात है उसका मेन कारण कोयले की कमी है। हमारे थर्मल प्लांट्स में डी ग्रेड का कोयला मिलना चाहिए लेकिन एफ ग्रेड का कोयला मिल रहा है। इसमें क्या घोटाला हो रहा है कि हमारे खेदड़ प्लांट की डेली की कैपेसिटी 20 से 25 हजार टन कोयले की है। 9 रैक प्रतिदिन कोयला लगता है और नार्म्ज के मुताबिक 21 दिन का कोयला एडवांस में होना चाहिए लेकिन वहां एक दिन का कोयला भी एडवांस में नहीं होता। इसी तरह से पानीपत थर्मल प्लांट की कैपेसिटी 25 से 28 हजार टन कोयला प्रतिदिन की है। वहां 10 रैक प्रतिदिन कोयला लगता है। वहां डेली जो कोयला जाता है वह यूज हो जाता है। इसी तरह से यमुनानगर थर्मल प्लांट की कैपेसिटी 15 हजार टन कोयले की है वहां भी कोयला नहीं मिल रहा। खेदड़ थर्मल प्लांट में मानंदी कोल, उड़ीसा से कोयला आता है जिसमें 48 से 50 प्रतिशत राख है। उसको कोल कम्पनीज में पानी से वाश करके लाया जा रहा है। पानीपत थर्मल प्लांट में वैस्टर्न कोल लिमिटेड कम्पनी से कोल आता है और उसमें 32 प्रतिशत राख है। इसी तरह से यमुनानगर में सैंट्रल कोल लि० से कोयला आता है और उसमें 35 प्रतिशत राख है। अध्यक्ष महोदय, जो हम इण्डोनेशिया से कोयला मंगवाते हैं उसमें क्लोरिफिक वैल्यू 5600-5700 होनी चाहिए। पूर्व एम.डी. ने श्री राम लैब से उसकी क्लोरिफिक वैल्यू चैक करवाई जो कि 4100 निकली। इस तरह से घटिया कोयला लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोयले की खरीद में जो गड़बड़ियां हो रही हैं यहां मैं उनका जिक्र कर रहा हूं इस तरफ मंत्री जी ध्यान दें। एक रिटायर्ड बी.एस. अहलावत को निगम का चीफ आपरेशन फ्यूल मैनेजमैंट का इंचार्ज लगा रखा है। उस पोस्ट पर एक सरकारी अधिकारी को लगाया जाये तो गड़बड़ी करने पर उसे डर रहेगा। एक रिटायर्ड आदमी लगा रखा है जो मजे काट रहा है। अध्यक्ष महोदय, खेदड़ प्लांट के अंदर क्लोरिफिक वैल्यू 4000 की बजाय 2800 से 3000 के करीब है और यमुनानगर में क्लोरिफिक वैल्यू 4000 की बजाय 3400 आ रही है। पानीपत में क्लोरिफिक वैल्यू 4100 की जगह 3500-3600 आ रही है। इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोयले की कंजम्पशन की बात है वर्ष 2003 में 0.744 किलो ग्राम कोयला प्रति यूनिट कंज्यूम होता था और अब 0.168 किलो ग्राम कोयला प्रति यूनिट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इसलिए इस मामले को ध्यान

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

से देखने की जरूरत है। इसमें करोड़ों रुपये लोगों की जेबों में जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा मामला है इसकी मंत्री जी इंक्वायरी करवायें। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यमुना नगर ओर खेदड़ थर्मल प्लांट्स में रिलायंस कंपनी ने कर्मचारियों की कॉलोनी बनाने के लिए 70 करोड़ रुपये देने के लिए कहा था लेकिन आज तक कॉलोनी नहीं बनी। सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है लेकिन कॉलोनी नहीं बनी है। वहां प्लांट में यदि कोई खराबी हो जाती है तो इंजीनियर हिसार से आता है जिसमें 3-4 घण्टे का समय बरबाद हो जाता है और प्लांट डाउन रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात करती है लेकिन सरकार ने दस दिन पहले इस बारे में पॉलिसी बनाई है। पहले उद्योगों के लिए 70 किलोवाट तक का ट्रांसफार्मर निगम लगाता था और सारा खर्चा निगम ही वहन करता था लेकिन अब पॉलिसी के तहत यह कर दिया गया है कि जिन उद्योगों में 50 किलोवाट तक का लोड है वे अपना अलग से ट्रांसफार्मर लगवायें और ट्रांसफार्मर का सारा खर्चा उद्यमियों को ही उठाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक ट्रांस्फार्मर पर एक लाख से डेढ़ लाख रुपये का खर्च आता है और सामान का अलग से खर्च होगा। सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल तक जिस उद्यमी ने अपना ट्रांस्फार्मर नहीं लगवाया उनके बिल में 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्त जोड़ दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सैल्फ फाईनैंस स्कीम के तहत किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन देने थे, किसानों को पैसे भी जमा करवाये हुए कई-कई साल हो गये लेकिन कनैक्शन नहीं दिए गए हैं। बिजली से संबंधित ही मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले सैशन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि प्रदेश में जहां कहीं भी चाहे शहर हैं या गांव हैं अगर उनमें लोहे के पोल होंगे तो उनको बदला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप भी आज के दिन देखते होंगे कि बहुत से गांवों और शहरों में लोहे के पोल लगे हुए हैं। जिसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और काफी कैल्यूलिटी हो जाती हैं इसलिए सरकार की तरफ से जो हाऊस में एश्योरैंस आया है उसके मुताबिक तुरंत लोहे के पोल हटवाकर पत्थर के पोल लगवाये जायें। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक उरलाना कलां गांव है जो कि बहुत बड़ा गांव है उसके अंदर 33 के.वी.ए. के पॉवर हाऊस के अंदर 6.3 और 8 एम.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मरज़ हैं, उनको अपग्रेड करके 10 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर लगाये जायें जिससे इलाका वासियों को अच्छी बिजली उपलब्ध हो सके। यह बात माननीय मंत्री जी के नोटिस में भी है। इस बारे में हाऊस में जो एश्योरैंस आया था उसको दो वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ एक बात मैं यह बताना चाहूंगा कि गांव सींक के अंदर 132 के.वी.ए. के पॉवर हाऊस का एश्योरैंस भी हाऊस के अंदर आ चुका है लेकिन अभी तक वहां पर भी काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से 220 के.वी.ए. का पॉवर हाऊस इसराना के पास बिजारा गांव में लगवाने का एश्योरैंस आया था लेकिन अभी तक वहां पर काम चालू नहीं हुआ है। इसी प्रकार मतलौडा में 33 के.वी.ए. के पॉवर हाऊस में 12.5 एम.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मरज़ लगवाये जाने की अप्रूवल है लेकिन आज तक भी ट्रांसफार्मरज़ अवेलेबल नहीं हैं। इसी प्रकार से नारा गांव के अंदर 2.10 एम.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मरज़ मंजूर हैं और सरकार की तरफ से अप्रूवल आ चुकी है लेकिन आज तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार हरियाणा प्रदेश में जब पांच साल में चुनाव आते हैं तो कहती है कि हम गरीब के हितैषी हैं। आज की प्रदेश सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश

में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनके बैकलॉग को कम्पलीट करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किये गये हैं । इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उनकी कुल संख्या 2694 और उसमें 539 आरक्षित हैं और लगे हैं 133 जोकि टोटल का 5 परसैंट है । इस प्रकार से बैकलॉग है 406 का । इसी प्रकार से सैकण्ड क्लास में 10 हजार 611 टोटल पद हैं और लगे हुए हैं 2122 इनमें से 988 आरक्षित हैं जो कि 9.3 प्रतिशत है और बैकलॉग है 1134 का । इसी प्रकार से क्लास थ्री में कुल पद 1 लाख 96 हजार 447 हैं जिनमें से लगे हुए हैं 39279 और 25173 आरक्षित हैं जो 22.83 प्रतिशत है और बैकलॉग है 14,116 का । इसी प्रकार से बोर्ड्स और निगमों में भी यही स्थिति है । प्रथम श्रेणी के कुल पद हैं 2990, आरक्षित हैं 600 और 99 कर्मचारी लगे हुए हैं यह है टोटल का 3 प्रतिशत और 511 का बैकलॉग है । इसी प्रकार से सैकण्ड क्लास में 3120 कुल पद हैं, 624 चाहिएं, 190 लगे हुए हैं और ये टोटल का 6 प्रतिशत है और इस प्रकार से 434 का बैकलॉग है । इसी प्रकार से क्लास 3 में 52285 पद आरक्षित हैं, 11657 लगे हुए हैं, 8000 कार्यरत हैं, यह टोटल का 14 प्रतिशत है और बैकलॉग है 3657 का । इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में पूरे हरियाणा प्रदेश में डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. की रिज़र्वेशन जीरो परसैंट है । हैडमास्टर की 9 परसैंट, सी. एण्ड वी. की 8 परसैंट, डी.ई.ओ. 5 परसैंट, लैक्चरार की 6 परसैंट, जे.बी.टी. की 11 परसैंट, प्रिंसीपल की 4.4 परसैंट, मास्टरज़ की 4.9 परसैंट और क्लर्कों की 7 परसैंट है । यह हालत आज प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के बैकलॉग की है । सर, जिस प्रकार से हम ड्यूटी पर आते हैं (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) : स्पीकर सर, अभी हमारे साथी ने बैकलॉग की बात कही है । इस बारे में एक बात तो मैं माननीय सदस्य से जानना चाहती हूं कि ये जिस बैकलॉग की बात कर रहे हैं वह किस वर्ष से किस वर्ष तक का है । मैं इनको यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार के समय में बैकलॉग को क्लीयर करने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है । दूसरी जो इन्होंने शिक्षा विभाग में डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. की बात की है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगी कि क्लास-एक और क्लास-2 के पदों पर पदोन्नति में रिज़र्वेशन फिलहाल नहीं है । इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य से यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या इनके समय में क्लास-1 और क्लास-2 के पदों पर पदोन्नति में रिज़र्वेशन थी?

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं ये सभी कुछ अखबारों में आया है । सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पवार जी, आपका समय हो गया है । मैं यह कहूंगा कि आप फीगर्ज़ की बात छोड़िए और आंकड़ों की बात को भी छोड़ दीजिए लेकिन आपकी जो स्पीच है यह बड़ी पॉजीटिव है इसलिए मैं आपको सिर्फ 30 सैकिंड और दे रहा हूं ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम जहां भी जाते हैं प्रदेश के पुलिस कर्मचारी हमें टोकते हैं । जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ौसी प्रदेश पंजाब ने पुलिस वालों को जे.बी.टी. के बराबर स्केल दिया है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी..... (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहती हूं कि वे आँकड़ों को क्लैरिफाई कर लें कि से आँकड़े कहां से इकट्ठे किये हैं और यह बैकलॉग किस वर्ष का है?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, ये आँकड़े 31.11.2006 से अपटूडेट हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों को पंजाब पैटर्न पर स्केल दिये जायें। इसके अलावा मेरे हल्के की कुछ सड़कें हैं जैसे खन्दरा से बालचतान वाया धर्मगढ़, इस सड़क का आश्वासन हाऊस में आया था लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है। इसी प्रकार अलूपुर से अहर का वर्क अलॉट हो कर काम शुरू हो चुका था उसके बाद बंद है। इसराना से माउपुर वाया कारद का भी काम बंद है। स्पीकर सर, इसराना में कम से कम 10-12 सड़कें हैं जिनके टैंडर हो चुके हैं जिन पर काम चालू नहीं हो रहा है। इसके साथ ही आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अनिल धन्तौड़ी (शाहबाद, एस.सी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा युवा सदस्यों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद। लगभग 7 वर्ष पूर्व हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में कमान आई। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत योजना तैयार की गई थी। तभी से वे हरियाणा को आधुनिक, जीवन्त और सम्पदाशील राज्य बनाने, आय और रोजगार सृजित करने, निवेश को बढ़ाने, कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों का विकास करने, राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, मानवीय गरिमा के साथ समावेश और प्रदेश की उन्नति को सुनिश्चित करने तथा पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरन्तर और निश्चित रूप से अग्रसर हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुख्य मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जिसके लिए मैं हरियाणा सरकार और माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश ने विकास का लम्बा सफर तय किया है। It is written in para 3 of the Governor's Address that—

> "I am hope to note that my Government has made significant gains in all these fields and the State has come a long way. As per Quick Estimate, the State economy has achieved a growth rate of 9.6% in Gross State Domestic Product during the year 2010-11. The average growth rate of industrial production was 7.9% during the year 2010-11 as per the index of the industrial production."

श्री ओम प्रकाश चौटाला : धन्यवाद तो उसका भी करना चाहिए जिसने आपको यह लिख कर दिया है।

श्री अनिल धन्तौड़ी : चौटाला साहब, मैं खुद लिखता हूं। आप यहां सबसे बड़े हैं और

मैं सबसे छोटा हूं। चौटाला जी, कृपया मेरा सहयोग करें।

Mr. Speaker : You are making a wonderful point. Carry on please.

Shri Anil Dhantori : Sir, I want to read out further that—

"As per the Advance Estimates for the year 2011-12, the per capita income of Haryana is expected to be Rs. 1,09,227 at current prices and the State ranks second, after Goa, amongst all the States." (Interruption)

Mr. Speaker : We must encourage young legislators.

श्री अनिल धन्तौड़ी : माननीय चौटाला जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया बीच में रुकावट पैदा न करें। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हरियाणा देश में औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। पिछले 7 सालों में बिजली के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति हुई है। वर्ष 2004-05 की तुलना में राज्य की अपनी बिजली

17.00 बजे

उत्पादन क्षमता तीन गुणा हुई है। (विघ्न) जनता से पूछ कर देखिए जनता यहां विराजमान है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से खेलों के क्षेत्र की बात करें तो खेलों के विकास के प्रति एक अभिनव और समग्र दृष्टिकोण से हरियाणा के खिलाड़ियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। माननीय मुख्य मंत्री जी की 'पदक लाओ और पद पाओ' नीति के अनुसार हमारे हरियाणा में आज खिलाड़ियों को बहुत मान और सम्मान दिया जाता है। हमारे देश के अनुरूप राज्य में अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या अधिक है। आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत की 72 प्रतिशत आबादी 40 वर्ष से ऊपर है और 47 प्रतिशत भारतीय 20 वर्ष से कम आयु के हैं। यह जरूरी है कि युवा शक्ति की क्षमता को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने युवाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 को 'युवा-वर्ष' घोषित किया है। सरकार खिलाड़ियों के लिए स्थान, समय और संसाधन अधिकार के तौर पर उपलब्ध करवा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए निवेश किया गया है। श्रेष्ठ खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाता है, उनको सरकार में नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहबाद मारकंडा के दो अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने डी.एस.पी. की नौकरी प्रदान की है। सुरेन्द्र कौर पूर्व महिला हॉकी टीम की कप्तान और पुरुष वर्ग में हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप जी को भी डी.एस.पी. की नौकरी दी गई है। खिलाड़ियों को हरियाणा पुलिस में भी विभिन्न पदों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्तियां दी हैं। The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries ने हरियाणा को खेल के क्षेत्र में Best Sports State for the Year अवार्ड के लिए भी चुना है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम चलाकर गरीब व आम जन के लिए सुविधा मुहैया करवाकर लाभ दिया है। E.S.I. निगम और फरीदाबाद में 550 करोड़ की लागत से 500 बिस्तरों का एक अति आधुनिक मैडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है जो वर्ष 2013 तक चालू होने की सम्भावना है। सात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य

[श्री अनिल धन्तोड़ी]
केन्द्रों और 145 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। मेवात, सोनीपत और करनाल में तीन मैडिकल कॉलेज बनाए जा रहे है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री चौ० भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इनफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : शाहबाद में मीरी-पीरी का जो मैडिकल कॉलेज है उसको भी मान्यता दिलवा दो। (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अरोड़ा साहब ने जो मीरी पीरी मैडिकल कॉलेज की चर्चा की है, वह तो एक फैमिली ट्रस्ट है।

श्री अध्यक्ष : यह फैमिली ट्रस्ट क्या है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एस.जी.पी.सी. का ठप्पा लगाकर मीरी पीरी नाम से एक मैडिकल कॉलेज बना रहे हैं और उसकी बाकायदा सदन में चर्चा हुई और उसमें यह पाया गया कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं और उनके जो पुत्र हैं, उन्हीं के बहुत नजदीकी व्यक्ति, पूरी उम्र के लिए उसके ट्रस्टी हैं। हमारे श्रद्धालु चढ़ावे के तौर पर गुरुद्वारा साहिब में पैसा चढ़ाते हैं। हरियाणा के गुरुद्वारों के गुल्लक से जो पैसा आता है, उस पैसे से बनने वाले मैडिकल कॉलेज का निर्माण सम्पूर्ण किया ही नहीं जा रहा है। हरियाणा के गुल्लक का पैसा एस.जी.पी.सी. हरियाणा में खर्च करने की बजाय पंजाब में ले जाती है। आदरणीय चौटाला जी मौजूद हैं उन्हीं की बात वे मानते हैं, वही इसको पूरा करवाएंगे। यह नौजवान तो कोशिश कर सकता है।

श्री अनिल धन्तौड़ी : अध्यक्ष जी, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तथा ग्रामीण आजीविका के अवसरों में बढ़ोत्तरी करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। (शोर एवं व्यवधान) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 जनवरी 2012 तक...... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Leader of the Opposition is speaking.

श्री ओम प्रकाश चौटला : अध्यक्ष जी, शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसा अदायरा है जो समुचे सिख समुदाय को रिप्रेजैंट करता है लेकिन उसको भी यह लोग पारिवारिक बताकर उसकी खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहिब, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट के अंदर तो काम नहीं करती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष जी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से तो बहुत कॉलेज बने हैं तथा अनेक सार्वजनिक हित के कार्य भी किये गये हैं।

Mr. Speaker : Not a family trust.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसी संस्था है जिसके पास किसी स्टेट से भी ज्यादा पैसा आता है और वह उस पैसे का प्रयोग लोगों

को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं और उस संस्था की इस पवित्र सदन में खिल्ली उड़ाना समूचे सिख समुदाय का अपमान है इसलिए....... (शोर एवं व्यवधान) । यह मैं जो बता रहा हूं यह असलियत है । यह सारे सिख समुदाय का अपमान है...... ।

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) : चौटाला साहब, आप सारे सिख समुदाय को बीच में क्यों लेते हो ?

श्री अध्यक्ष : चट्ठा साहिब, मैं आपको भी बोलने के लिए समय दूंगा, प्लीज, आप बैठिये ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी एक इलैक्टिड बाडी है और समूचे सिख समुदाय का रिप्रेजैंटेशन करती है । यहां समूचे सिख समुदाय का अपमान किया जा रहा है । अशोक अरोड़ा जी ने तो माननीय सदस्य से यह कहा था कि यह हमारे जिले का मामला है, एक अच्छा काम होने जा रहा है, हम आपके साथ हैं, उसके लिए प्रयास करो । यह तो सहमत थे इस बात के लिए, लेकिन यहां पर तो खिल्ली उड़ाई जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : चट्ठा साहिब, अब आप बोलिये ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहिब, इनको सारे समुदाय को बीच में नहीं घसीटना चाहिए (शोर एवं व्यवधान) Please, that is not the way. Sir, he is dragging the entire community into a college affair. (Noise & Interruption)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहिब, चट्ठा साहिब को अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिये । मैं आपकी भी सुनूंगा उनको कहने तो दीजिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक इलैटिड बॉडी है....... (शोर एवं व्यवधान) ।

Mr. Speaker : Yes, I know it is. मुझे पता है लेकिन उन्हें अपनी बात करने दीजिये । (शोर एवं व्यवधान)

Sardar Harmohinder Singh Chattha : Everybody knows that it is an elected body.

Mr. Speaker : Chattha Sahib, you may please continue.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी एक फैमली का ट्रस्ट है वह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ट्रस्ट नहीं है । अगर यह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ट्रस्ट होता तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनोनीत सदस्यों का नाम भी इसमें कहीं न कहीं शामिल होता । चौटाला साहिब वहां तो इंडीविजुअल नाम हैं । बादल साहब का नाम है, उनके लड़के का नाम है, उनके रिश्तेदारों का नाम है और अन्य किसी का कोई नाम नहीं है (शोर एवं

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा]
व्यवधान) मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इस बात को लेकर सारे सिख समुदाय को न घसीटें । यह तो महज एक कालेज की बात है (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी न सिर्फ पूरे सदन को बल्कि पूरे समूचे सिख समुदाय को गुमराह कर रहे हैं । शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक इलैक्टिड बॉडी है और यह जो मीरी-पीरी के नाम से जो कॉलेज बन रहा है यह शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा ही बन रहा है । (शोर एवं व्यवधान) यह बात अलग है कि पद की गरिमा को कायम न रखकर के एक कमेटी के चट्ठा साहब चेयरमैन बन गये जो अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बांटने का प्रयास कर रही थी ।

श्री शेर सिंह बड़शामी : चट्ठा साहिब, स्पीकर होने के नाते तो उस समय आपको उसका चेयरमैन बनना भी नहीं चाहिए था । (शोर एवं व्यवधान) आपने तो पद की भी गरिमा नहीं रखी । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर सर, अनफारचुनेटली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वोटर मैं तो हूं लेकिन ये तो वोटर भी नहीं हैं । He is not the voter. He absolutely knows nothing about the Gurudwara Prabandhak Committee. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी एक कमेटी है । अगर यह कॉलेज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन हो तो बात ठीक लगती है लेकिन जबकि नाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है, पैसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है और वहां पर नाम हैं बादल परिवार के सदस्यों का, यह बात सरकार को बुरी लगी है । (शोर एवं व्यवधान) चौटाला साहिब, आप किस बात को लेकर तड़फते हो (शोर एवं व्यवधान) आपके तो मित्र हैं । आप बादल साहिब से जाकर कह दो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं । शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा वह कॉलेज बनाया जा रहा है और यह कह रहे हैं कि बादल परिवार का नाम वहां पर क्यों है । यह कैसे किया जा रहा । (शोर एवं व्यवधान)

Sardar Harmohinder Singh Chattha : Speaker Sir, it is not headed by the Gurudwara Prabandhak Committee. It is headed by the Chief Minister of Punjab.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इनसे पूछिये कि क्या स्पीकर की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति किसी ऐसी संस्था का चेयरमैन बन सकता है जो विवाद के घेरे में खड़ी कर दी जाये ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : चौटाला साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, इन्होंने तो स्पीकर के पद की गरिमा को ही बिगाड़ने का काम किया है । स्पीकर सर, आप पता कीजिये हम आपसे इस मामले में रूलिंग चाहते हैं कि क्या स्पीकर के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति किसी कमेटी के चेयरमैन बन सकते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Yes, I will give my ruling.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला साहब को बताना चाहूंगी कि सभी सिख एस.जी.पी.सी. के अंडर हैं, यह गलत है। मैं भी सिख हूं और मैं इनको बताना भी चाहूंगी कि दिल्ली कमेटी है, महाराष्ट्र की अलग कमेटी है। सारे हिंदुस्तान के सिखों को एस.जी.पी.सी. रिप्रजैंट नहीं करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री चौटाला जी ने मेरा नाम लेकर यह कहा कि यहां एस.जी.पी.सी. की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की जा रही है, अगर मुझे सही सुना। साथ ही इन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि यह जो मैंने स्पेसिफिक बात कही है, यह गलत है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। ओम प्रकाश चौटाला जी आदणीय हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं और मेरे पिता की उम्र के हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात कहकर सदन को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। हम सब सिख मर्यादाओं व संगठनों का सम्मान करते हैं। इस मामले में अध्यक्ष महोदय, आप एक कमेटी का गठन कर लें जो कि चौटाला साहब को भी सम्मन कर ले और मुझे भी सम्मन कर ले। उसमें मीरी पीरी ट्रस्ट का रिकॉर्ड भी मंगवा लें। मैं फिर दोहराता हूं। मीरी पीरी ट्रस्ट के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल व उनके बेटे लाइफ टाइम ट्रस्टी हैं। (शोर एवं व्यवधान) एस.जी.पी.सी. का पैसा हरियाणा पंजाब के सिखों की मेहनत और खून पसीने की कमाई का पैसा है और उस पैसे का उपयोग एक परिवार नहीं कर सकता। इस बात को व्यवधान में डालकर ये हाउस को बरगला नहीं सकते। (शोर एवं व्यवधान) ये यहां जवाब दें कि एस.जी.पी.सी. का पैसा क्या किसी एक व्यक्ति की बापौती है। हमारे सिख भाई एक-एक पैसा जोड़कर जो गुल्लक में डालकर आते हैं, किसको अधिकार है कि उस पैसे का इस्तेमाल केवल एक परिवार कर ले। किसको अधिकार है कि उस पैसे से एक ट्रस्ट बना दी जाए और उसमें केवल बादल साहब व उनका बेटा पूरी जिंदगी के लिए ट्रस्टी बन जाएं, चट्ठा साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, यदि मेरी बात गलत है तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए, अन्यथा चौटाला साहब पर प्रिविलेज किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए तैयार हूं लेकिन इसके लिए रिकॉर्ड मंगवाया जाए कि तमाम जो मीरी पीरी हैं (शोर एवं व्यवधान) वह एस.जी.पी.सी. के तत्वाधान में बन रही हैं या किसी ट्रस्ट के लोगों के सहयोग से बन रही है। यह तो रिकॉर्ड की चीज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : ये तो आपके सामने ही मानने लग गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कहा है इन्होंने ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : ये कह रहे हैं कि हां साहब, वे लाइफ ट्रस्टी हैं और उनके नाम पूरी जिंदगी के लिए मैडीकल कॉलेज कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा असत्य बोलते हैं और हमेशा हाउस को गुमराह किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमारी विधान सभा ने तो उनको ट्रस्टी नहीं बनाया है। (शोर एवं व्यवधान) ट्रस्टी तो कोई भी हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये भी देखा जाये कि क्या ये कॉलेज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में बन रहा है या किसी ट्रस्ट के हिसाब से बन रहा है? ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि इस कॉलेज के लिए बादल साहब व उनके बेटे को लाइफ ट्रस्टी बना दिया गया है। तत्वाधान में किसी के भी बने। पूरी उम्र के लिए मुझे ट्रस्टी बना दिया जाये तो उस कॉलेज का असली मालिक होगा कौन? (शोर एवं व्यवधान) क्या एस.जी.पी.सी. के पदाधिकारी हैं आदणीय बादल साहब?

सरदार चरणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में सिर्फ 5-7 गुरुद्वारे हैं (शोर एवं व्यवधान) जिनकी गोलक का 63 परसैंट पैसा एस.जी.पी.सी. के पास जमा होता है शेष 15 परसैंट पैसा सिखी के प्रचार प्रसार के लिए लगाया जाता है और बाकी का पैसा एस.जी.पी.सी. में जमा हो जाता है लेकिन देखा हर गुरुद्वारे का काम जाता है। (शोर एवं व्यवधान) सिर्फ पांच या सात गुरुद्वारों का थोड़ा सा पैसा एस.जी.पी.सी. में जाता है। (शोर एवं व्यवधान) इसके बावजूद एस.जी.पी.सी. सभी गुरुद्वारों को सुन्दर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपये की राशि देती है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे गुरुघर बहुत ही सुन्दर बने हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, बात यहां से शुरू हुई थी कि मेडिकल कॉलेजिज तीन बनाये गये हैं। मैंने धन्तौड़ी जी से यही कहा था कि आपके अपने शहर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है जहां से आप एम.एल.ए. चुनकर आये हैं उसको भी आप बनवा लीजिए। अगर एस.जी.पी.सी. किसी भी ट्रस्ट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज बनाकर कुरुक्षेत्र, शाहबाद मारकण्डा के लोगों को सुविधा देना चाहती है तो सरकार उस सुविधा को क्यों नहीं लेना चाहती है। अगर इस ट्रस्ट में बादल साहब का नाम शामिल है इसलिए सरकार यह सुविधा नहीं लेना चाहती।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने कभी मना नहीं किया है। इसमें व्यवस्था का प्रश्न उठा था और प्रश्न यह उठा था कि मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शाहबाद में कौन कर रहा है? उस कॉलेज के ट्रस्टीज कौन हैं और उस कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है और कौन उसका निर्माण करना नहीं चाहता? बादल साहब का पूरा जिम्मा आदरणीय चौटाला जी की पार्टी के पास हरियाणा और पंजाब में हैं फिर ये उस कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं करवाते।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उस कॉलेज का निर्माण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार ने उस कॉलेज का एन.ओ.सी. रोका हुआ है। सरकार एन.ओ.सी. दिला दे तो हम कुरुक्षेत्र के लोगों को सुविधा देना चाहते हैं और हम उस कॉलेज को बनवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : जब चौटाला साहब जो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ने एक बात कह दी फिर पार्टी के दूसरे सदस्यों को वह बात बोलनी नहीं चाहिए।

श्री अनिल धन्तौड़ी : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी

योजना (मनरेगा) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2012 तक 67.68 लाख रुपये मानव दिवस सृजित किये गये हैं । इनमें से 51 प्रतिशत मानव दिवस अनुसूचित जातियों के लिए तथा 36 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के लिए सृजित किये गये हैं । इस कार्यक्रम के तहत 12,697 विकास कार्य प्रारम्भ करवाए गये । मनरेगा के तहत श्रमिकों को 170 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है जोकि देश के राज्यों में सर्वाधिक है । भारत सरकार ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया । प्रथम चरण में इसे चार जिलों नामतः कैथल, मेवात, भिवानी और झज्जर के 12 खण्डों में शुरू किया जाएगा । इस स्कीम का हरियाणा के सभी जिलों में चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाएगा । राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया है । अब सभी विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति दी गई है । अब से निधियां ग्राम पंचायतों को सीधे ही हस्तांतरित की जाएंगी और उन्हें 10 लाख रुपये तक के कार्य अपने स्तर पर करवाने की शक्ति प्रदान की गई है । शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया है । मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि हरियाणा एजुकेशन का हब बनाया जाए । अनेक कॉलेजिज और यूनिवर्सिटीज स्थापित किए जा रहे हैं और युवाओं को उच्चतर शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसके लिए मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । सड़क और परिवहन सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । हर जिले में नई सड़कें बनाई जा रही हैं और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ।

Mr. Speaker : Thank you very much.

श्री अनिल धन्तौड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेन पुलों पर ओवर ब्रिज बनाये जा रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को सुविधा हो ।

श्री अध्यक्ष : कितने ओवर ब्रिज बनाये गये हैं?

श्री अनिल धन्तौड़ी : अध्यक्ष महोदय, 17 ओवर ब्रिज बनाए गये हैं । कानून व्यवस्था के लिए माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सोच है कि प्रदेश में सुशासन को सुविचारित रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है । जिला सोनीपत में खरखौदा, जिला हिसार में बरवाला और जिला कुरुक्षेत्र में शाहबाद तीन नए उप मण्डल बनाए गए हैं । विशेषता यह है कि इसमें दो विधान सभा क्षेत्र शाहबाद और खरखौदा दोनों ही विधान सभा क्षेत्र सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनको उप मण्डल का दर्जा दिया है । मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय की सोच दूरदर्शी है कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जाए जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं । उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहबाद मारकंडा को उप-मण्डल का दर्जा दिया है । गुड़गांव और फरीदाबाद की तर्ज पर अम्बाला और पंचकूला में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू की गई है । हरियाणा प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में निर्णायक रूप से अग्रणी है । हरियाणा की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से विकसित हो रही है जिसका प्रभाव देश भर में महसूस किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अन्तर्गत इस बात पर पूरी तरह से सहमति व्यक्त करती हूं कि हमारा प्रदेश हरियाणा बड़ी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी वर्तमान सरकार की जो नई-नई जन-हित की नीतियां और कार्यक्रम हैं उनको सरकार बड़े प्रभावी रूप से लागू कर रही है। इसके नतीजे हर क्षेत्र के अंदर सार्थक उपलब्धियों के रूप में सामने आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, पशु पालन, ग्रामीण एवं शहरी विकास, स्वच्छ पेयजल, कृषि सिंचाई एवं जल संरक्षण, बिजली, उद्योग, सड़क एवं परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, युवा एवं खेल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, महिला सशिक्तकरण, बाल विकास, लैंगिक संतुलन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शासन एवं कानून व्यवस्था और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण आदि शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास की गति को बाधित करने वाली बुराइयों के खिलाफ डट कर संघर्षशील है। इसमें सबसे बड़ी बुराई भ्रष्टाचार है। सरकार द्वारा हर स्तर पर ऐसी नीतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया जाए। खासतौर से सरकारी रोजगार के अवसरों के संदर्भ में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार ने पारदर्शी और न्यायसंगत नीति अपनाई है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन को सुशासन की अहम प्राथमिकता में शामिल किया गया है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में प्रस्तुत हरियाणा के विकास के आंकड़े आगे आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि हमारा प्रदेश हरियाणा देश के अंदर एक न्यारा तरक्की की मिसाल बनकर आगे आ रहा है। जिसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील नेतृत्व को जाता है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस बात पर जोर देती थी कि कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्का इरादा हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली में स्पष्ट रूप से दिखता है कि वे कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्के इरादे से हरियाणा को बड़ी तेजी से प्रगति के पथ पर आगे ला रहे हैं। हमारे प्रदेश की जो तरक्की है इसकी मिसाल देश के अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्यों और पाकिस्तान के अंदर भी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सबके बावजूद भी प्रदेश की तरक्की की बेहतरी के लिए और बहुत कुछ करना बाकी है जिसे हमें एक लक्ष्य बनाकर बेहतर से बेहतर नीतियों के साथ आगे बढ़ना है। विकास के हमारे जो ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं उसमें मैं हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि अपने प्रदेश के विकास के लिए आप सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें सरकार का समर्थन करें। प्रदेश की तरक्की जो सदियों में होनी थी वह दशकों में होगी और जो दशकों की तरक्की है वह चंद वर्षों में होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देना चाहूंगी। आज के दिन जो पर्यावरण है वह न केवल हमारे प्रदेश या देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। आज से दो दशक पहले जब हरियाणा में नैशनल हाई-वे या दूसरे रोड़ज पर निकलते थे तो दोनों तरफ बहुत हरियाली नजर आती थी परंतु अब हम देखते हैं कि इन पर हरियाली पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अध्यक्ष महोदय, अब हमें चाहिए कि हम हरियाणा प्रांत में बहुत ज्यादा वृक्षारोपण करके ऐसी क्रांति लायें जो पूरे देश में मिसाल बनकर रह जाये। इसमें हम पंचायती राज संस्थाओं और दूसरे संगठनों की भी मदद ले सकते हैं। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि हमारे हरियाणा की जो संस्कृति है और हमारी जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको संगठित कर राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना के रूप में एक संग्रहालय स्थापित करें। जिसमें महाभारत काल से लेकर अब तक जो हमारे युद्धवीर, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्य कला से संबंधित जो विशेष स्मृतियां हैं वे सभी संगठित हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें सदन में रखना चाहूंगी कि डायबिटीज की बीमारी जिसको हिंदी में शूगर या मधुमेय रोग भी कहा जाता है यह बीमारी सुनामी की तरह उत्तरी भारत में मानव शरीर को नुक्सान पहुंचा रही है। आज के दिन ग्रामीण क्षेत्र में भी यह बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का मुख्य कारण हमारा लाईफ स्टाइल है और इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में फर्टीलाईजर और कैमीकल्ज का इस्तेमाल तथा बाजार में खाने में मिलावट और नकली दवाईयां हैं। यह बीमारी आज के दिन सुनामी की तरह आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से पोलियो ओर टी.बी. की बीमारियों को समाप्त करने के लिए सरकारी तौर पर अभियान चलाये जाते हैं उसी तरह से इस बीमारी को रोकने के लिए भी अभियान चलाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगे आपके माध्यम से रखना चाहूंगी कि हमारे करनाल शहर के अंदर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। वहां पार्किंग का कोई स्थान नहीं है और शहर के अंदर से निकलने में बहुत मुश्किल होती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि करनाल शहर में पार्किंग की व्यवस्था की जाये। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो करनाल नगर निगम की बिल्डिंग शहर के अंदर बनी हुई है जिसके कारण ट्रैफिक की भी समस्या आती है वह आज बहुत पुरानी हो गई है। वह बिल्डिंग बहुत जर्जर कंडीशन में है इसलिए एक नई और मॉडर्न बिल्डिंग करनाल नगर निगम की शहर से बाहर बनाई जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं करनाल का बस स्टैंड शहर से बाहर बनाने के लिए पिछले 7 साल से कह रही हूं और इस बारे में मैंने प्रश्न भी लगाया था और हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर विश्वास दिलाते हैं कि अगले सैशन से पहले बस स्टैंड बनवा दिया जायेगा। करनाल शहर का बस स्टैंड मेन शहर में है जिसके कारण भी ट्रैफिक की समस्या रहती है। मुझे इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के साथी महिला को तो बोलने दें, जब इनकी बारी आये तब ये बोल लें। अध्यक्ष महोदय, हमारे करनाल शहर के अंदर 50 से 60 अनअथोराईज्ड कॉलोनीज हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और मेरी बात भी सुन रहे हैं। हमारे वहां जो अनअथोराईज्ड कालोनीज हैं उनको जल्दी से जल्दी एप्रूव किया जाये क्योंकि जिन कॉलोनीज का रैजोल्यूशन एप्रूवल के लिए भेजा गया था वे कॉलोनी अभी एप्रूव भी नहीं हुई हैं और दूसरी अनएप्रूव्ड कॉलोनीज वहां बनने लग गई हैं। अध्यक्ष महोदय, करनाल के सदर बाजार एरिया में जूता उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। आज के दिन वह जूता उद्योग बंद होने के कागार पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि करनाल के अंदर जूता उद्योग बंद न हो क्योंकि वहां पर वे अपने घरों में जूते बनाने का काम करते हैं। उनके लिए करनाल के अन्दर कोई स्पैशल शू हब बनाया जाए और वहां पर उनको स्पेशल रिबेट भी दी जाये। इसके साथ-साथ मैं एक जनरल बात भी करना चाहूंगी कि हम 10 परसैंट महिलायें विधान सभा में चुनकर आई हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे सभी साथियों को महिलाओं के प्रति इज्जत और आदर का भाव दिखाना चाहिए क्योंकि महिलाओं की इज्जत करने के हमको संस्कार दिये जाते हैं

[श्रीमती सुमिता सिंह]
लेकिन जब वे बोलना शुरू करती हैं तो हम यहां कुछेक सदस्यों को महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हुए देखते हैं इससे हमें बहुत दुःख होता है। हमें उम्मीद है कि आगे से ऐसा मौका नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

Mr. Speaker : My observation is that this was found lacking the other day. This should not be happened again.

डॉ० बिशन लाल सैनी (रादौर) : स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2012 को दिये गये अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जो भी बोलूंगा वह इस अभिभाषण के विरोध में बोलूंगा। सर, मैं अभिभाषण के विरोध में इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि जो बातें इसके अन्दर लिखी गई हैं वे सारी की सारी पुरानी हैं और नकली हैं। जो पाप सरकार ने इसको छापकर किया और वही पाप इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान से पढ़वाकर किया जिसे हमने सुना। सर, यह आपने भी देखा होगा कि जिस समय महामहिम जी अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे उस समय उनके माथे पर सिलवटें आई हुई थी क्योंकि वे बहुत नाराज़ थे और वे इसको पढ़ना नहीं चाहते थे। मैं इस अभिभाषण के पैरा नम्बर 53 पर बोलने से पहले अगर आप नाराज़ न हों तो मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से प्रश्न क्यों करना चाहते हैं?

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई सरपंच बनता है तो वह सारे गांव का सरपंच होता है या फिर अपने घर का ही सरपंच होता है? मैं अपनी बात इस प्रकार से शुरू करना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मंत्री सुरजेवाला जी एक बहुत अच्छे मंत्री हैं। मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि ये केवल कैथल के ही मंत्री नहीं हैं ये यमुनानगर के भी मंत्री हैं और सारे हरियाणा प्रदेश के भी मंत्री हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको सिर्फ कैथल तक ही सीमित नहीं करना चाहिए कभी यमुनानगर के अंदर भी आकर देखना चाहिए कि वहां की सड़कों का क्या हाल है? मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि ये हमारे जिले में आयें हम इनका दिल से स्वागत करेंगे, इनको अच्छी जगह ठहरायेंगे, अच्छा खाना भी खिलायेंगे। इसके साथ-साथ अगर ये बुरा न माने तो मैं इनको यह भी कहना चाहूंगा कि अपने साथ ये अपनी धर्मपत्नी को भी लेकर आयें। वे भी हमारी मेहमान होंगी। हमारे जिले में चार विधान सभा क्षेत्र हैं उन चारों विधान सभा क्षेत्रों की 400 सड़कों की हम इनको एक लिस्ट देंगे। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय उनमें से सिर्फ कोई चार सड़कें ही चुन लें और उन चारों सड़कों पर ये सुबह-सुबह नहा धोकर जिस प्रकार से ये विधान सभा में आते हैं अच्छे सफेद कपड़े पहनकर, शाल ओढ़कर पूरी तरह से तैयार होकर उन सड़कों पर घूमने के लिए जायें। (शोर एवं व्यवधान) वहां पर आगे-आगे पुलिस की जिप्सी होगी और पीछे-पीछे इनकी गाड़ी होगी। हम इनसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि ये अपनी कार के शीशे खुले रखें उन्हें बंद न करें। जब ये आधे घंटे तक उन सड़कों पर घूमकर आयेंगे अगर इनकी धर्मपत्नी इनको पहचान ले कि ये उनके मंत्री जी ही हैं तो ये समझें कि

हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं और अगर पहचान न पायें और यह कहें कि आपने ये क्या हाल बना लिया है आपने तो सफेद कपड़े पहने थे ये इतने गंदे कैसे हो गये, चलो दोबारा से बाथरूम में जाओ और नहाकर दूसरे कपड़े बदलकर आओ तो फिर यह समझो कि हमारी सड़कों का नाश हो चुका है। सर, यह बिलकुल सच्ची बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में सड़कों की वजह से एक पोस्ट मार्टम रोजाना होता है यानि 30 दिन में 30 आदमी परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। अभी आपने एक बात कही थी कि अगर आपको अपनी मांग बनवानी हो, अपनी बात कहनी हो तो मंत्री जी को अलग से लिख कर भेजो। आपके कहने के अनुसार मैंने 2 चिट्ठियाँ माननीय मंत्री जी को 2 महीने पहले लिखी थी लेकिन उनका जवाब आज तक नहीं आया है। यहां तो मंत्री जी एक मिनट में खड़े हो जाते हैं। चौटाला साहब जब अपनी बात कह रहे थे तो मंत्री जी 15 बार खड़े हुये जैसे स्प्रिंग लगे हुये हों और मैं दो महीने से इंतजार कर रहा हूं मुझे मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला। हमारे कृषि मंत्री जी ने एक पत्र का जवाब मुझे जरूर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अगर अपनी बात कहनी है तो वे मर्यादा में रह कर ही अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : इसमें इन्होंने कौन सी बात अमर्यादित कही है?

श्री अध्यक्ष : अब ये आगे से मर्यादा में ही बोलेंगे।

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने मर्यादा से बाहर कुछ कहा हो तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। सरदार परमवीर सिंह हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने लिखा है कि आपके रादौर विधान सभा क्षेत्र में हमारी 88 सड़कें हैं। 88 में से 38 सड़कें अच्छी हालत में हैं बाकी 50 बैड कंडिशन में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हमारी 88 की 88 सड़कें बुरी हालत में हैं। मंत्री जी को एक बात और कहना चाहता हूं कि 1999 से लेकर 1.4.2005 तक जब हरियाणा में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने रादौर विधान सभा क्षेत्र में 58 सड़कें बनवाई थीं। यह रिकॉर्ड की बात है लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो 7 साल में केवल 3 नई सड़कें बनी हैं। एक तरफ तो 58 सड़कें बनी और दूसरी तरफ इन्होंने केवल 3 सड़कें बनाई हैं और ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह केवल मेरे हलके की बात नहीं है हमारे पूरे जिले की बात करूँ तो चौटाला साहब के समय में 183 सड़कें बनी थीं और अगर किलोमीटर की बात की जाये तो 308 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी। अगर इस सरकार की बात की जाये तो हमारे 4 विधान सभा क्षेत्रों में 21 रोड बनाये गये हैं और अगर 22वीं सड़क बनी हो तो मुझे बता दें। कहां तो एक तरफ 183 और दूसरी तरफ 21। उत्तर प्रदेश में जाकर बयान देते हैं कि अच्छी, चौड़ी सड़कें देखनी हों तो हमारे हरियाणा में आकर देखें। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार हमारे जिले का दौरा जरूर करें। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के पैरा नं० 21 का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें थर्मल प्लांट का जिक्र किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां कहीं भी घोषणा करते हैं तो वह पूरी होती है। मुख्यमंत्री जी ने थर्मल प्लांट का जब नींव पत्थर रखा, पहले चौटाला साहब ने रखा था, फिर इन्होंने भी दोबारा से रखा है। सर, मेरे पास सात साल

[डॉ० बिशन लाल सैनी]
पुराना अखबार है इन्होंने 28.8.2005 को जब इसका नींव पत्थर रखा, उस समय यहां लगभग पांच हजार आदमी होंगे। उनके सामने जब अनाउंस किया तो इन्होंने दो बातें कही कि एक तो जिन गांव के किसानों ने जो जमीन दी है मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं स्टेज से अनाउंस करता हूं कि जिन परिवारों की जमीनें आई हैं, उनके परिवार के एक-एक सदस्य को इसमें नौकरी देंगे। उस टाईम हमारे मंत्री थे कैप्टन अजय सिंह यादव जी, वह भी वहां प्रेजैंट थे, उनके सामने ये बात कही थी, लेकिन आज तक भी वह अनाउंसमैंट पूरी नहीं हुई। स्पीकर सर, अभी 26 जनवरी को हमारे बिजली मंत्री जो पहले वित्त मंत्री थे, ये वहां गए थे और उनसे जब अखबार वालों ने, मीडिया ने पूछा कि आपने ये नौकरियों की अनाउंसमैंट की थी किन्तु ये अनाउंसमैंट आपने पूरी नहीं की तो स्पीकर सर, हमारे मंत्री जी ने यह कहा कि मेरे को तो पता नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं। जबकि उनकी फोटो भी मुख्यमंत्री जी के साथ छपी हुई थी। यह फोटो तब की है और ये मैंने संभाल कर रखी हुई है इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिनकी जमीन गई है, उन परिवारों के बच्चों को नौकरी दी जाए। यह बहुत अच्छी बात होगी।

Mr. Speaker : Thank you very much, your time is over.

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मुझे 5 मिनट का समय और देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आपको दो मिनट का समय और दिया जाता है, अभी अन्य सदस्यों को भी बोलना है, माजरा जी ने बोलना है, कविता जी ने बोलना है। आप बजट पर भी बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि उस फोटो में मैं साथ था। मैं उस समय बिजली मंत्री नहीं था। गलत बात यहां हाउस में कहना अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० बिशन लाल सैनी : मंत्री जी, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। ये फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, आप वहां थे, ये आपकी फोटो है। मैं गलत होऊंगा तो मैं आप से माफी मांग लूंगा। आप यहां आकर के देख लीजिए क्योंकि मैं तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत के बिना आपकी सीट पर नहीं आ सकता।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम किशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : यदि कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर है तो बताएं?

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर सर, आपके माध्यम से साथी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने चौटाला साहब के कार्यकाल के बारे में कई बार यहां कहा। ये अच्छी बात है, वे आदरणीय हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने मुझे परमीशन दी है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सैनी साहब ये बताएं कि चौटाला साहब ने अपने छः साल के कार्यकाल में

बिजली के कितने कारखाने लगाए? उन कारखानों का नाम बताएं कि कौन सा कारखाना लगाया, व उनमें कितनी नौकरियां दी? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Saini, you may continue please.

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, इसमें दादूपुर नहर का जिक्र आया, इसका जिक्र पिछली बार भी आया था और अब की बार भी आया है।

Mr. Speaker : This is the last line.

डॉ० बिशन लाल सैनी : सर, पिछली बार भी यही बात थी कि पहला चरण पूरा हो गया और दूसरे का काम चल रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या छोटी-छोटी नहरों का काम भी चरणों में होगा और उसके भी चरण बनाए जाएंगे? इससे अच्छा तो ये है कि इस काम को बंद ही कर दो। इस सरकार को बने हुए आज सात साल हो गए हैं मगर इन नहरों के एक चरण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ। इस हिसाब से 21 साल में तीन चरण पूरे होंगे तब ये नहर चलेगी।

श्री अध्यक्ष : क्या आप दादूपुर नहर के अगेंस्ट हैं?

डॉ० बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, दो नाले हैं जो कि बरसाती नाले हैं, एक राक्षी नदी है और दूसरा चलंग है। जब ऊपर बरसात होती है तो उसका पानी आता है और पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। दूसरी तरफ वह नहर खुद रही है, जिसके कारण उसमें आकर वह पानी भर जाता है। तीन साल से किसानों का इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लेकिन इसके बावजूद इस नहर के काम को पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी चट्ठा साहब इस विषय पर मुझसे नाराज हो गए थे। वे कह रहे थे कि नहर का काम तीन चरण में पूरा होगा। बताओ नहर तीन चरण में कैसे पूरी होगी? स्पीकर सर, पुलों का जिक्र आया। मेरे जिले में तीन पुल हैं, वैसे तो चार पुल हैं, जिनके ऊपर से हमारे जिले के लगभग 30 प्रतिशत गांवों के लोग यमुनानगर शहर में आते हैं और वहां से जाते हैं। उन चार पुलों में से तीन पुल टूटे पड़े हैं जिसकी वजह से हमारे जिले के 30 परसैंट लोगों को कम से कम 20 किलोमीटर का चक्कर काटकर शहर में जाना पड़ता है और इसी तरह 20 किलोमीटर का वही चक्कर काटकर वापिस आना पड़ता है। विशेषतौर से जो छोटे-छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनका इतना लम्बा चक्कर काटने से बहुत समय खराब होता है। उनके माता-पिता को उन्हें छः बजे तैयार करके बस में बैठाना पड़ता है ताकि वे समय पर स्कूल पहुंच सकें। इसी तरह शाम को इतना लम्बा 20 किलोमीटर का चक्कर काटकर जब बच्चे वापिस घर आते हैं तो शाम के छः बज जाते हैं जिससे उनकी पढ़ाई का, सोने का तथा खाने का सिस्टम खराब हो जाता है। स्पीकर सर, इतना बुरा हाल आज मेरे हल्के में इन टूटे पुलों की वजह से हो चुका है।

Mr. Speaker : Thank you, Saini ji. आप बैठिये! आपके दूसरे मैंबर मोहम्मद इलियास जी एक मिनट के लिए बोलेंगे।

मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, क्या मैं भी एक मिनट ले सकता हूं?

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद इलियास जी, अगर आप ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो मैं इसकी आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो मुझे एक मिसाल देकर सरकार की पोजीशन बताने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, मैं आपको बोलने की अनुमति दे सकता हूं मिसाल देने की नहीं। (विघ्न)

मोहम्मद इलियास : सदर साहिब, आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, यदि आपके साथी सैनी साहब बैठ जायेंगे तब आपको मौका दूंगा। एक समय में दो आदमी कैसे बोल सकते हैं?

डॉ० बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरी अभी बहुत बातें बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने यह कहा है कि जहां तक बोलने के समय की बात है बोल सकते हैं लेकिन अभी खत्म करें क्योंकि मैं कविता जी को नैक्स्ट स्पीकर के लिए इन्वाईट कर चुका हूं। (विघ्न) वह एक महिला सदस्य हैं उनको सम्मान के तौर पर आपको बोलने का मौका देना चाहिए। वैसे सैनी साहब आपने अपना दृष्टिकोण बड़े अच्छे ढंग से रखा है, अब आप बैठिये। I am so happy with you.

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कविता जैन जी, अब आप पांच मिनट के लिए बोलिये।

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, बस पांच मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल द्वारा दिया गया अभिभाषण मात्र सरकार का झूठा गुणगान है और यह बात विधानसभा में रखी गई कैग की रिपोर्ट से साफ जाहिर होती है। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि किस तरह सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया है। चाहे वह कोई भी डिपार्टमैंट हो, चाहे वो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट हो, फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैंट हो, एजुकेशन डिपार्टमैंट हो या इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट हो सभी डिपार्टमैंट्स में जमकर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया। वास्तव में यदि हम संक्षेप में कहना चाहें 'सो रही सरकार करोड़ों गये बेकार' यह बिल्कुल सच साबित होता है। स्पीकर सर, एक तरफ तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में टैक्स हटाने की बात कही गई है लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के जो गैर-घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार द्वारा 100 से 130 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह बिल से अलग चार्ज डालकर छोटे-छोटे उद्योगों को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है और इसी तरह से शहरों के अंदर जो व्यवसायिक नक्शा पास करवाने की फीस थी उसे भी 1431 रुपये की बजाय शहर अनुसार 6000 रुपये से लेकर 13500 रुपये प्रति वर्ग गज तक बढ़ाकर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है। स्पीकर सर, एक तरफ तो सरकार हमेशा किसान के हित की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाये तो किसान आज

बर्बादी के कगार पर है। धान, कपास की जो फसल है उसके दाम इस वर्ष पिछले वर्ष से आधे दिये गये हैं जबकि खाद, बीज और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर सरकार वाकई में किसानों का भला चाहती है तो रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, सरकार हमेशा अधिग्रहण की नीति के बारे में हमेशा बड़ी-बड़ी बातें कहती रहती है तो फिर क्या कारण है कि सोनीपत के अंदर जैसे बड़खालसा, राई, शैदपुर कुंडली के किसान काफी लंबे अर्से से अधिग्रहण के खिलाफ बैठे हुए हैं। वास्तव में यह तो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है। स्पीकर सर, बिजली उत्पादन के केस के अंदर मैं कहना चाहूंगी कि सरकार बार-बार बिजली उत्पादन बढ़ोतरी का गुणगान करती रहती है, लेकिन बिजली की हालत क्या है? प्रदेश के अंदर जो बिजली की बुरी स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। सर्दियों का आलम भी यह है कि यहां हर रोज शहरों के अंदर 6 से 8 घंटे के कट लगाये जाते हैं। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट का तो दिवाला ही निकल चुका है क्योंकि बिजली बोर्ड आज 6617 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। स्पीकर सर, 5 साल पहले 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए गए थे और उसका भार उन उपभोक्ताओं पर डाला गया था जो रैगुलर बिल भरते हैं। हालत यह हो गई है कि 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करने के बावजूद भी 3900 करोड़ रुपये के बिल आज भी बकाया हैं और इस वजह से बिजली विभाग फिर से बिजली के रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यह बात बहुत ही गलत है और उन लोगों के लिए गलत है जो समय पर बिजली के बिल भरते हैं। सरकार को उन उपभोक्ताओं के बारे में भी सोचना चाहिए जो वाकई में बिजली के बिल पे करते हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के ऐड्रस में ग्रामीण विकास की बात कही गई है जबकि सच्चाई यह है कि गांव में जाने वाली सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। ईंटों का सरकारी रेट 3800 रुपये प्रति हजार है जबकि बाजार में यह 4000 रुपये की दर से मिलती हैं। इस बारे में जैसा कि क्वैश्चन ऑवर में क्वैश्चर भी लगा था उसके जवाब में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने साफ तौर पर मना किया था कि गांव में सीवरेज नहीं डाल सकते। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनका कि हुडा डिपार्टमैंट की तरफ से जमीन का अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। गांव में गन्दे पानी की निकासी के लिए कोई जमीन नहीं बची है। ऐसे में सरकार किस आधार पर दावे पेश करती है कि ग्रामीण विकास हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार सचेत है। इसी तरह से मैं ऐजूकेशन डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहूंगी कि शिक्षा का एक तरह से बेड़ा ही गर्क हो चुका है। हालांकि हमारी शिक्षा मंत्री महोदया हमेशा ही क्वालिटी और क्वांटिटी ऐजूकेशन की बात करती हैं लेकिन यदि सही मायनों में देखा जाये तो आज जो हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, वह प्राइवेट स्कूलों के सहारे से चल रही है। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार यदि वाकई में शिक्षा के प्रति इतनी सोच रखती है तो क्या कारण है कि किसी भी सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करता? यहां तक कि कैग की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर लिखा है कि ऐजूसेट प्रणाली लागू करने के लिए किस तरह से सरकार के करोड़ों रुपयों का नुक्सान किया गया है। हमारे सोनीपत शहर में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां न कोई लैंड है, न बिल्डिंग है तो फिर वे कैसे ऐजूसेट प्रणाली का लाभ उठा पाएंगे।

इसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि राजीव गांधी एजूकेशन सिटी का प्रचार केवल अखबारों तक सीमित होकर रह गया है जबकि उसके लिए भूमि अधिग्रहण करते वक्त साफ

[श्रीमती कविता जैन]
शब्दों में यह कहा गया था कि वहां ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिटी बनाई जायेगी और उसमें यूनिवर्सिटी भी बनेगी। मुझे लगता है कि यह ड्रीम प्रौजैक्ट ड्रीम ही बनकर रह जायेगा, कभी पूरा नहीं होगा।

आज लोगों के स्वास्थ्य की बात कही जा रही है जबकि सच तो यह है कि अस्पताल खुद ही बीमार हो चुके हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है कि मेडीकल कॉलेज बनाया जाए लेकिन होता यह है कि जिला अस्पताल का स्टाफ उस मेडीकल कॉलेज के अंदर भेज दिया जाता है। हमारे सोनीपत का जो सिविल अस्पताल है वहां नयी भर्ती तो होती नहीं है यहां जो वर्तमान में स्टाफ है उसको भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। एक रेडियोलॉजिस्ट था उसे भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। आई स्पेशिलिस्ट को भी मेडीकल कॉलेज में भेज दिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि राजीव गांधी ऐजूकेशन सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रौजैक्ट है और वह इनका विधान सभा क्षेत्र है इनको तो खुशी होनी चाहिए कि वहां उन्होंने वर्ल्ड लैवल की यूनिवर्सिटी बना दी है। वहां इतना विकास हो रहा है, इनको तो इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए बजाय इसके ये गवर्नर साहब के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा और न जाने क्या-क्या कह रही हैं। अध्यक्ष महोदय, न केवल वहां ऐजूकेशन सिटी बननी है बल्कि जिस दिन राजीव गांधी ऐजूकेशन सिटी में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जायेगा उससे वहां नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ऐजूकेशन आएगी और ओवरआल इंफ्रास्ट्रक्चर डवैल्प होगा। मैं तो इसके लिए माननीय सदस्या को कहूंगी कि इनको तो मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।

श्रीमती कविता जैन : वहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आयेंगे तो हम उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे जोर-शोर से धन्यवाद करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप बैठिये, आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गये हैं।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, सामाजिक और न्याय के अधिकार की बात करते हैं। कई महीने हो गये हैं लेकिन वृद्धा अवस्था, विकलांग और विधवाओं को समय पर पैंशन नहीं दी जा रही है। इसी तरह से लाखों की संख्या में लोगों के नाम बी.पी.एल. कार्ड की लिस्ट से काट दिए गये हैं। बिना लोगों को इन्फार्म किये लोगों को राशन देना बन्द कर दिया है जोकि सरासर गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बी.पी.एल. कार्ड बनाने का आधार बनाया गया है वह 443.21 रुपये प्रति माह है जोकि सरासर ही गरीब लोगों की भावनाओं के साथ एक खेल रचा गया है। एक तरफ तो गवर्नर एड्रेस में प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम वर्तमान मूल्यों पर 1,09,227 रुपये बताई गई है और दूसरी तरफ बी.पी.एल. कार्ड बनाने का आधार 443.21 रुपये प्रति माह किया गया है जोकि सरासर गलत है। इसी तरह से शहरी विकास के मामले में मैं कहना चाहती हूं कि सोनीपत के अन्दर रोहतक रोड़, गोहाना रोड़, बाबा तराना रोड़ और ककरोई रोड़ पर चलना मुश्किल हो गया है। पिछले बार जब विधान सभा का गठन हुआ था उस समय पहले गवर्नर एड्रेस में सोनीपत शहर को मैगा सिटी बनाने का

प्रचार किया गया था और उस समय हमने इस बात का स्वागत भी किया था। मैंने जब शहरी निकाय विभाग से मैगा सिटी के बारे में प्रश्न लगाया था तो उसका जवाब इन्कार में आया था तो यह साफ तौर से जाहिर होता है कि गवर्नर एड्रेस में प्रदेश की जो बात लिखी गई है वह सही नहीं होती।

Mr. Speaker : Thank you very much.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर की बुरी हालत है। मैं प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। आज प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो गया है और आज कॉमन पीपल तो क्या एम.एल.ए. और एम.पी. भी प्रशासन से त्रस्त हो चुके हैं। सरकार ने प्रशासन के सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था जिस पर आज तक 1.75 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। अगर प्रशासन की मनमानियों से जनता को राहत देना चाहते हैं तो सिटीजन चार्टर को लागू करना चाहिए और इसके बारे में कानून बनाना चाहिए। अन्त में मेरा यह कहना है कि सरकार को कहने में नहीं करने में विश्वास करना चाहिए तभी प्रदेश की वास्तव में तस्वीर बदलेगी।

श्रीकृष्ण हुड्डा (बड़ौदा) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और सदन में उपस्थित सत्तापक्ष व विपक्ष के मेरे समस्त साथियों व हरियाणा के जन मानस को बधाई देता हूं कि हमारा प्रदेश राज्यपाल महोदय के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के प्रभावशाली नेतृत्व में दिन-दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। हरियाणा में बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, जो एक लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, हरियाणा सरकार को मिल रहे पुरस्कार, खेल व शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन, इस बात के साक्षी हैं कि हमारी विकास की गाड़ी सरपट दौड़ रही है। बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। सन् 2004 में औसतन बिजली उत्पादन 578 लाख यूनिट था जो अब बढ़कर 1009 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गया है। वर्तमान में जो परियाजनाएं चल रही हैं उनसे हरियाणा बिजली उत्पादन अधिशेष वाला राज्य बन जाएगा। जिससे हर गांव शहर, किसान उद्योग को 24 घंटे बिजली मिलेगी और सस्ती भी होगी क्योंकि बाहर से महंगी दरों पर खरीदनी नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की आर्थिक विकास दर 2011 में 9.6 प्रतिशत होना ये दर्शाता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी होते हुए भी हरियाणा ने प्रगति की है जोकि सरकार की सूझबूझ और कुशलता का परिचय देती है। हरियाणा एक छोटा राज्य होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्यान्न

18.00 बजे

भण्डार में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अध्यक्ष महोदय, खेल के क्षेत्र में हरियाणा की पहचान व प्रतिष्ठा देश में सर्वोपरि है। एशियाई खेलों में लगभग दो दर्जन स्वर्ण पदक परोक्ष व अपरोक्ष रूप से हरियाणा से सम्बन्धित है। देश के दूसरे सभी राज्य हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए यहां हर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। चाहे वो धन से सम्बन्धित हो चाहे ढांचा गत सुविधा हो। गांव-गांव में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों को बड़ी धन राशि के साथ- साथ उन्हें पुलिस विभाग में ऊंचे सरकारी पद भी दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में हरियाणा को शिक्षा हब के रूप में जाना जाने लगा है। सरकार ने सैंकड़ों कॉलेजों के साथ-साथ दर्जन भर विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने पाठ्यक्रम, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक

[श्रीकृष्ण हुड्डा बड़ौदा]

बदलाव के साथ- साथ ऐजूसैट व कम्प्यूटर शिक्षा सभी स्कूल व कालेजों में लागू की है। जिससे हरियाणा के युवा अब बड़े शहरों में उच्च स्तर की नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने थोड़े से अरसे में काफी उन्नति की है पर यात्रा कभी रुकती नहीं है। विकास के कई पड़ाव अभी हमें पार करने हैं। इसके लिए हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सकारात्मक सहयोग की जरूरत है। अतः मैं प्रदेशवासियों, सत्ता पक्ष व विपक्ष के साथियों से आह्वान करता हूं कि आओ हम मिलकर हरियाणा को एक उन्नत और स्वर्ग समान सुन्दर राज्य बनाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं दो चार समस्याएं अपने हल्के की भी कहना चाहूंगा। मेरे हल्के के अंदर जो हमारी मार्किटिंग बोर्ड की सड़कें हैं उनकी बड़ी खस्ता हालत है, उनकी तरफ भी मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। मैं एक डिमांड यह करूंगा कि बड़ौदा हल्के के अंदर कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और मेरे हल्के का विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल माजरा जी, अब आप बोलें। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यदि आपको परेशानी है तो ------

श्री अध्यक्ष : रामपाल माजरा जी, मुझे परेशानी नहीं लेकिन आपने बैठे-बैठे ऐसे कमैंट्स किया, यह अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं और यही आपसे अस्पैक्ट करता हूं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे तरसा कर जो समय दिया मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप पार्टी के चीफ स्पीकर हैं और हम चाह रहे थे कि पहले और लोग बोल लें और आप बाद में आराम से बोल लेते। आपने मेरी चिट भी पढ़ी होगी और अगर वह चिट आपका सम्मान न कर रही होती तो आप खुद अपने आप अंदाजा लगाइए। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह चिट पिछली बार भी आई थी, आपने यह कहा था कि बजट पर आप बोलेंगे लेकिन आपने यह कह दिया कि मेरी मजबूरी थी।

श्री अध्यक्ष : मेरी आज कोई मजबूरी नहीं है। आप बोलिए।

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातें भूलकर यही कहूंगा कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय जब अपना अभिभाषण दे रहे थे और जब वे इस अभिभाषण को पढ़ रहे थे तो ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से कहीं भी किसी भी योजना के ऊपर मेजें नहीं थपथपाई गई। केवल पार्लियामैंट्री एफेयर्ज मिनिस्टर अकेले पड़े हुए थे और दूसरे मैम्बर्ज की तरफ देख रहे थे कि कोई और भी मेजें थपथपाए। उनका दिल भी मान रहा था कि मेजें थपथपाने वाला अभिभाषण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस

अभिभाषण को सुनकर और पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि—

दिखने में जो प्यार संभाले बैठे हैं, अंदर से अंगार संभाले बैठे हैं।
सच तो यह है कि सच से है परहेज इन्हें, ये झूठा व्यापार संभाले बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जब किसान आयोग बना उस समय मैंने समझा था कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की समस्याओं का कोई समाधान होगा। कमीशन बनने के बाद डॉक्टर परोदा इस आयोग के चेयरमैन बने। उन्होंने वैबसाईट भी जारी की कि सुझाव दिए जायें लेकिन तब से लेकर आज तक किसानों को सबसे ज्यादा समस्या आई है। सर, अब 10 पैसे प्रति किलो गन्ने के भाव बढ़ते हैं और 20 पैसे प्रति किलो गेहूं के भाव बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार एम.एस.पी. तय करती है और इसके साथ-साथ कई चीजें इंटरनैशनल मार्केट पर निर्भर करती हैं। इंटरनैशनल मार्केट में यदि चावल के दाम बढ़ जाते हैं तो ये कहते नहीं कि इंटरनैशनल मार्केट की बात है और दीवारों पर लिखा जाता है "हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में"। आज वही राज है जिसमें "जीरी गई ब्याज में और पराली गई लाज में" क्योंकि बासमती जीरी का जो भाव 20 साल पहले 1600-1700 रुपये प्रति क्विंटल था वह आज 20 वर्ष बाद भी कम होकर 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल है। सत्तापक्ष के सदस्य भी बाई इलैक्शन में गये थे और इन्होंने देखा होगा कि किसान ने घरों में जीरी इस आस से रखी हुई है कि जीरी के भाव बढ़ेंगे। किसान तरस गये लेकिन भाव नहीं बढ़े। किसानों ने तरसने के बाद यह समझा कि आज वह नारा जो दीवारों पर लिखा होता था वह कहां गया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किसान (विघ्न)

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Speaker Sir, on a point of order. माननीय सदस्य जीरी का जिक्र कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह पी.आर. जीरी की बात नहीं है यह 1121 या दूसरी जीरी होगी जिसका भाव कभी एम.एस.पी. पर निर्भर नहीं होता। एम.एस.पी. पर केवल पी.आर. जीरी निर्भर होती है। पी.आर. जीरी का रेट बता दें कि इनकी सरकार में क्या थे और अब क्या हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं किसान की और बातें भी बता सकता हूं। इनके समय में किसानों से 11 प्रतिशत ब्याज मिनी बैंकों में लिया जाता था जो हमने कम करके 4 प्रतिशत तक कर दिया है। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के साथी जो किसान की बात करते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999 से 2005 तक 4392 एकड़ 6 कनाल 11 मरला भूमि अधिग्रहण की गई थी और इनके समय में वर्ष 2005 से 2010 तक 43234 एकड़ भूमि किसानों की कहीं सेज के नाम पर, कहीं आई.एम.टी. के नाम पर और कहीं उद्योग खड़े करने के नाम पर अधिग्रहण की गई है। इस तरह से 750 एकड़ भूमि प्रति वर्ष अधिग्रहण की गई है।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि मेरे काबिल दोस्त रामपाल माजरा जी सदन को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। माननीय साथी जिस सेज की बात कर रहे हैं उस सेज की जमीन का मैं आज नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। वह नोटिफिकेशन इनके समय की है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, ये उस बात को विद्ड्रा कर रहे हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हम विद्ड्रा नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी बता दूंगा कि किस-किस प्रोजैक्ट के लिए कितनी-कितनी भूमि किसानों की अधिग्रहण की गई है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, मंत्री जी यह बता रहे हैं कि सेज की जमीन आपकी सरकार के वक्त में अधिग्रहण की गई। आप यह बात विद्ड्रा कर लो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नोटिफिकेशन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, ये विद्ड्रा कर रहे हैं। You need not reply.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी जिस जमीन की बात कर रहे हैं उसका मुआवजा ये लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख और 5-5 लाख रुपये प्रति एकड़ दिया करते थे। हरियाणा प्रदेश में पहली बार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने इस देश की सबसे बेहतरीन फ्लोर रेट पॉलिसी बनाई और एक-एक करोड़ रुपये तक प्रति एकड़ मुआवजा उस जमीन का दिया जिसका इन्होंने 5-6 लाख रुपये मुआवजा प्रति एकड़ दिया था। मेरे पास सारे आंकड़े और तथ्य मौजूद हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दस गुणा जमीन कहीं होजरी कम्पलैक्स के नाम पर, कहीं औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर, कहीं न्यूक्लीयर पावर प्लांट के नाम पर और कहीं आई.एम.टी. के नाम पर अधिग्रहण करके किसानों से छीन ली। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरी डिटेल प्रोजैक्टवाईज है यदि ये कहेंगे तो मैं वह जानकारी भी सदन में रख दूंगा। इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी कहा है कि...... (शोर एवं व्यवधान) सर, इसके अलावा न्युक्लीयर पावर प्लांट के बारे में भी इन्होंने पूछा है। इन लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा मैं इनको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सौम्या दत्ता ने कहा है कि न्युक्लीयर पावर प्लांट के 15 किलोमीटर के आस-पास के क्षेत्र में खतरनाक विकिरण होगा और 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैंसर बढ़ेगा और दूसरी बीमारियां भी बढ़ेंगी। जिस न्युक्लीयर पावर प्लांट की ये बात कर रहे हैं उससे हैल्थ की कोई सिक्योरिटी नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा नीतिगत मुद्दा है। ये सभी पार्टियों के एक्रॉस भी बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, क्या मैं यह समझूं कि श्री रामपाल माजरा जी उनकी पार्टी की तरफ से यह कह रहे हैं कि वे हरियाणा प्रदेश में न्युक्लीयर पावर प्लांट लगाने के विरोधी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, रामपाल माजरा जी कह रहे हैं कि वे हरियाणा प्रदेश में न्युक्लीयर पावर प्लांट लगाने के विरोधी हैं। (शोर एवं व्यवधान) बड़ी सिम्पल सी बात है ये विरोधी हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस न्युक्लीयर पॉवर प्लांट के लगने से फतेहाबाद और सिरसा जिले के अन्दर 50 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश आयेगा। (शोर एवं व्यवधान) ये बात कर देते हैं जापान की। (शोर एवं व्यवधान) सर, अगर ये न्युक्लीयर पॉवर प्लांट के विरोधी हैं तो ये हरियाणा के किसान के हितों के विरोधी हैं, हरियाणा के गरीब मज़दूर

और हरियाणा के आम व्यापारी के हितों के भी विरोधी हैं क्योंकि ये चाहते नहीं कि वहां पर पॉवर आये। सिरसा और फतेहाबाद जिले के अन्दर हम इससे ज्यादा पॉवर किसी और सोर्स से नहीं दे सकते। ये न्युक्लीयर पॉवर प्लांट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आशीर्वाद से और उनकी ही मदद से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल से फतेहाबाद के लिए लेकर आये हैं।

श्री रामपाल माजरा : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि देश के दूसरे प्रदेशों में जहां पर न्युक्लीयर पॉवर प्लांट लगे हुए हैं क्या वहां के मुख्यमंत्री भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ही हैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम न्युक्लीयर पॉवर प्लांट नहीं लगायेंगे तो हमारे पास alternative sources of energy क्या हैं?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, जो हमारे पास थर्मल पॉवर प्लांट्स हैं उनके लिए हमें कोयला कोल प्राईवेट इण्डिया लिमिटेड से बहुत मुश्किल से मिलता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या जो ये ज़मीन अधिगृहित की गई थी क्या उन थर्मल पॉवर प्लांट्स के लिए ही अधिगृहित हुई है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं कि यह ज़मीन न्युक्लीयर पॉवर प्लांट के लिए ही अधिगृहित हुई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही इम्पोर्टैंट प्रोजैक्ट है और इसके द्वारा हरियाणा को बहुत भारी फायदा होने वाला है। विपक्ष के साथियों की सोच बहुत गलत है। ये वहां पर जाकर किसानों को भड़काते हैं। (शोर एवं व्यवधान) सर, मैं आपकी, तमाम सदन और इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 80 परसैंट किसानों ने लिखकर दिया है कि उनको इस न्युक्लीयर पॉवर प्लांट के लिए सरकार द्वारा ज़मीन एक्वायर करने से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद भी ये विपक्ष के लोग हाउस को गुमराह करते हैं। पता नहीं ये हाउस को क्यों मिसलीड करते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण न्युक्लीयर पॉवर प्लांट है जिससे 1500 मैगावाट बिजली पैदा होगी। ये इसका विरोध कर रहे हैं यह बड़े ताज्जुब की बात है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस न्युक्लीयर पॉवर प्लांट के लगने से न केवल सिरसा और फतेहाबाद में बिजली ही आयेगी बल्कि 50 हज़ार करोड़ रुपये के लगभग का निवेश भी आयेगा। उस न्युकलीयर पॉवर प्लांट का जो विरोध करते हैं वे फतेहाबाद, सिरसा के साथ-साथ पूरे हरियाणा के हितों के विरोधी हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इसके साथ-साथ मैं यह भी विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि उस न्यूक्लीयर पॉवर प्लांट में सारे के सारे लेटैस्ट सेफ्टी मेजर्स को लिया जा रहा है। वहां पर दुनिया की सबसे बैस्ट टैक्नालॉजी का इस्तेमाल किया जायेगा। ये यह कहकर कि वहां पर लोगों को कैंसर की बिमारी होगी, वहां पर लोगों का नुकसान होगा, हाउस को मिसलीड कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ढुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में न्युक्लीयर पॉवर प्लांट के विरोध में वातावरण बना हुआ है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा न्युक्लीयर पॉवर प्लांट था वह फोकोसीमा (जापान) में था उसे भी विधिवत रूप से इसी वजह से बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके विकिरण की स्थिति किसी से सम्भाली नहीं जा सकी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी केवल संकीर्ण और नकारात्मक सोच रखते हैं। Some people have negative thoughts. Government has passed Bill on nuclear energy. It has been decided umpteen number of times right from the times of Pandit Jawaharlal Nehru uptill today that Nuclear energy will sustain energy needs of this country. It makes us independent. Sir, we are going to get Coal from 3000 kilometres. सर, 3000 किलोमीटर से हरियाणा सरकार को कोयला लाना पड़ता है उसके बाद उसकी सफाई होती है। उसके बाद ही हम बिजली पैदा करते हैं क्योंकि हमारे पास बिजली पैदा करने का कोई नैचुरल सोर्स नहीं है। स्पीकर सर, मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 64 वर्ष से हम न्युक्लीयर पॉवर प्लांट से बिजली पैदा कर रहे हैं। आज तक हिन्दुस्तान का रिकॉर्ड है कि यहां पर न्युक्लीयर पॉवर प्लांट के मामले में कोई एक्सीडैंट नहीं हुआ। कभी विपक्ष के साथी रशिया पहुंच जाते हैं और कभी जापान पहुंच जाते हैं। सर, यहां पर हम जापान या रशिया की नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की बात कर रहे हैं। सर, दुर्भाग्य से लोकदल के साथी जिनको न इस बात की पूरी जानकारी है और न ही तकनीक की समझ है, हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता के ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) It is important for the sustenance of this country. And anybody who opposes nuclear energy, opposes the energy sustenance of the country. I am saying that anybody who is opposing the production of nuclear energy is going against the national interests. (Noise & Interruption)

Mr. Speaker : It is very important. Please resume your seats.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये इस बात को पहले भी कह चुके हैं। जब चौटाला साहब बोल रहे थे तब भी इन्होंने इस बात को कहा था। इस बात को बार-बार कहने का कोई औचित्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रणदीप जी, ये तो खिलाफ हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें कोट कर लो, हम तो खिलाफ हैं।

श्री अध्यक्ष : हाँ, ठीक है।

श्री रामपाल माजरा : ठीक है सर, बात खत्म हुई। ये कहते हैं कि हमने पंचायतों का सशक्तिकरण कर दिया। स्पीकर सर, पहले पंचायतों के पास रिवैन्यू के राईट्स होते थे, सिविल राईट्स थे और ज्यूडिशियल कम्पलैंट्स भी पंचायतें सुनती थी लेकिन इन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से ये ग्रामीण विकास की बात करते हैं। स्पीकर सर, 2 अक्तूबर, 2008 को इन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना शुरू की और 607447 लोग इसके लिए चिन्हित किये गये। (शोर एवं व्यवधान) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया

है कि 3,80,000 लोगों को 100-100 गज के प्लॉट मिले हैं। स्पीकर सर, 2,27,447 लोगों को अभी प्लॉट मिलने बाकी हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल रजिस्ट्री करने से काम नहीं होगा, जब से जाकर नींव भरेंगे तब जाकर पता चलेगा कि प्लॉट मिला है या नहीं। यह योजना फेल हुई, स्पीकर सर। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकिशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माजरा जी से पूछना चाहता हूं, ये हरिजनों के हितैषी बने फिरते हैं। ये बता दें कि इन्होंने अपने 6 साल के राज में एक इंच जमीन भी हरिजनों को कभी दी हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, इनकी बात का जवाब दीजिए और अगर जरूरी नहीं समझते तो मत दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने पूछा है कि क्या आपकी सरकार ने एक इंच जमीन भी हरिजनों को दी थी। (शोर एवं व्यवधान) किसी हरिजन, बाल्मीकि, ब्राह्मण या बैकवर्ड को एक इंच भी जमीन दी है या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो इनकी सरकार ने भी नहीं दी। यह तो पंचायतों की जमीन थी ये तो सूखी वाह-वाही लेकर गये हैं। ग्राम पंचायतों की जमीन दी गई है। हमारे राज में भी 75-75 गज के प्लॉट दिये जाते थे। 75 गज के प्लॉट हमारी पंचायतों से दिये जाते थे। मैंने खुद रजिस्ट्री करवाई हुई है, उस समय मैं सरपंच था। स्पीकर सर, मेरी बात सुनो। यह ग्राम पंचायतों की जमीन थी। मैं खुद सरपंच था, मुझे सब पता है। यह पुरानी परम्परा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप माजरा जी की इस बात का जवाब दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धर्मबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने भी विधायक विपक्ष में बैठे हुये हैं, उनसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं वे आत्मा पर हाथ रख कर कह दें कि मेरे हलके में एक भी प्लॉट आबंटित नहीं हुआ। कोई एक भी कह दो। आप कहलवा कर दिखा दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सरकार ने नहीं दिये। आप एक प्लॉट तो बताईये जो सरकार ने दिया हो। कोई सिंगल प्लॉट भी सरकार ने दिया हो। यह तो ग्राम पंचायतों की जमीन थी उसमें से ही दिये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्दिरा आवास योजना के तहत साढे आठ लाख लोगों में से 17293 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार से हरियाली की बात करते हैं। इन्होंने 11 हर्बल पार्क नियमों का उल्लंघन करके बना दिये और संजीव चतुर्वेदी की उस रिपोर्ट को जिसकी सी.बी.आई. से जाँच करवाई जानी चाहिए थी सी.वी.सी. ने रिकमैंड किया था और सी.बी.आई. ने कहा था कि इंडीपैंडैंट इन्कवायरी होनी चाहिए, इन्होंने उसको ठण्डे बस्ते में रख दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं माजरा साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हांसी-बुटाना नहर बनाई थी और फिर कह दिया कि इसका लेवल गलत है। आज

[श्री रामपाल माजरा]
हमारी सरकार हर्बल पार्क बना रही है तो ये कहते हैं कि ठीक नहीं है। आज हमारी सरकार 100-100 गज के प्लॉट बांट रही है तो ये कहते हैं कि यह गलत है। बिजलीघर बनाये जा रहे हैं, वह भी गलत है। इससे नुकसान हो जायेगा। किसान को बिजली की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please resume your seat. (Interruption)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। इन्होंने कहा कि हर्बल पार्क बनवाए तो उसमें क्या बुरी बात है? हमने जो हर्बल पार्क बनाये हैं उनमें कोई अनियमितता नहीं है और वे बिल्कुल एज पर नॉर्म बने हैं और उसके लिए लोग हमारा धन्यवाद करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, जो गरीब लोगों को प्लाट देने की बात है, यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। यह मेरी आदत है कि जब आप सढौरा में जाते थे तो मैं आपका भाषण सुनने जाया करता था और जब कहीं भी उस इलाके में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी आते थे तो मैं उनका भी भाषण सुनने जाया करता था। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ये बताएं कि ये उसका समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप किस बारे में कह रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, गरीबों को जो प्लाट दिए जा रहे हैं मैं उसके बारे में कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप समर्थन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : सर, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने नंगला गाँव में....... । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सरकार ने खरीद कर दिए हों तो बताएं ये तो पंचायत पहले भी देती थी और अब भी दे रही है। फौजी साहब, आपने मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से तीन सौ कीले जमीन बना ली है आप भी गरीब की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने नंगला गाँव में ये ब्यान दिया था.... । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Mr. Bhukri, Please listen to me. आप अपना प्रश्न दोहराईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : सर, ओमप्रकाश चौटाला जी का ये ब्यान था कि ये जो गरीबों को प्लाट दिए जा रहे हैं, ये कटने नहीं देने और जनता इसका विरोध करे। ये चौधरी ओमप्रकाश चौटाला का भाषण था मैं यही कहना चाहता था सर। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, राजपाल भूखड़ी जी ने यह बहुत वाजिब बात उठाई है, लोकदल के साथियों ने दलितों को प्लाट देने का विरोध किया था और हमें इस

बात पर ऐतराज है। अगर किसी दलित के बेटे के पास जमीन है तो इसमें क्या पाप है, क्या दलित के बेटे को ये अधिकार नहीं कि वो जमीन का मालिक हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो दुलिना में पांच-पांच हरिजन दलितों के बच्चों को जिंदा जलवा दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज। Please be seated.

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती अनिता यादव) : स्पीकर सर, वैसे तो यह हरिजनों का मुद्दा है। हरिजनों के लिए इन लोगों ने हमेशा ही मनमर्जी से काम लिया। जब हम लोग अपोजिशन की साईड बैठते थे तो माजरा साहिब इधर से जहां आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बोलते हैं, बोला करते थे। आपने नरेश जी को बोलने से रोका लेकिन मैं नरेश जी का समर्थन करती हूं। मेरे बारे में तो प्रैस में भी आता है कि मैं नरेश जी की बात को जरूर उठाती हूं। जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर होते थे तो हमारे नठेड़ा गांव से इनकी सिर्फ पांच वोटें आई थी। एक बार जब नठेड़ा गांव का सरपंच इनके पास गया तो यह उनसे बोले कि नठेड़ा से कितनी वोट आई थी, वह बोला की पांच आई थी। इसके जवाब में यह बोले कि पर्ची तुम्हारे गांव से आवे पांच और तुम सोचो के मैं तुमने दे दूं प्लाट, यहां से भाग जाओ। स्पीकर सर, विपक्ष की बात तो वही बतायेगा जो उस टाईम यहां पर हाजिर हुआ करता था (विघ्न) अरोड़ा जी उस वक्त आप मंत्री थे और हम भी इस सदन के सदस्य थे लेकिन आप विपक्ष को बोलने नहीं दिया करते थे। आज जब नरेश जी या श्री रामकिशन फौजी जी आपके बारे कोई बात कह रहे हैं तो वह बिल्कुल सच कह रहे हैं। उस वक्त रामपाल माजरा जी जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो एक-एक घंटा सदन को गुमराह किया करते थे और आज भी इनकी यही मंशा है कि सदन को गुमराह किया जाये। (विघ्न) बहादूर सिंह जी, आपसे मेरी कोई बात नहीं हो रही है, मेरा सदन में प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। मैं चेयर की इजाजत पर खड़ी हुई हूं। मैं आपकी परमिशन से नहीं खड़ी हुई हूं।

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, आप बोलिये। मैंने आपको अलॉऊ किया है।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने की है और यह बात बिल्कुल सच है कि आज हर एक हरिजन भाई को प्लॉट अलॉट हो रहे हैं। जिन ग्राम पंचायतों में जमीन नहीं है, वहां जमीन को खरीदकर के उस पर प्लॉट काटकर हरिजनों को दिये जा रहे हैं। क्या रामपाल माजरा जी बतायेंगे कि वह हरिजनों के हित में हैं या विरोध में हैं? क्या उनको प्लॉट मिलने चाहिएं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : खटक जी, आप बोलिये।

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, रामपाल माजरा जी ने अभी कहा कि प्लॉट के लिए पंचायती जमीन का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माजरा जी से पूछना चाहती हूं कि जब इनका शासन था क्या उस समय पंचायती जमीन नहीं थी? इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आज हमारे मुख्यमंत्री जी हरिजनों के हितैषी हैं तो यह उनका विरोध कर रहे हैं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भूक्कल, मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, 100 गज के प्लॉट पर बहुत लंबी चर्चा इस सदन में हो रही है। ये प्लॉट न केवल अनुसूचित जाति के लोगों को बल्कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, हमारे अपोजिशन के लोग इस बात के खिलाफ हैं कि ये प्लॉट जो दिये जा रहे हैं ये पंचायत की जमीन से क्यों दिये जा रहे हैं?

श्रीमती गीता भूक्कल, मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, यह प्लॉट बी.पी.एल. को भी दिये जा रहे हैं, बी.सी.-ए को भी दिये जा रहे हैं। वास्तव में यह लोग इस बात के खिलाफ हैं कि गरीबों की हितैषी यह सरकार गरीबों के लिये इस तरह के कार्य क्यों कर रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, कोई भी कंट्रोवर्शियल बात न कहें, मैं सभी को बोलने के लिए समय दूंगा। यदि आप प्लॉट देने की स्कीम के खिलाफ हैं तो आप अपना स्टैंड दीजिये। इतनी पॉजिटीविटी तो होनी ही चाहिए कि आप लोग यह कहें कि हम इसके खिलाफ हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहता। मैं प्लॉट देने की स्कीम के खिलाफ नहीं हूं। परन्तु ये असलियत में दे नहीं रहे हैं।

अभी से क्यों झलक आये आंसू, तेरे आंखों में नादान,
अभी तो छेड़ी है दास्तां फिर भी तूने मेरे दोस्त।

हरियाणा ओवरसीज प्लेसमैंट सोसायटी बनाई गई। नौजवानों को कहा गया कि हम उन्हें रोजगार के लिए विदेशों में भेजेंगे। स्पीकर सर, अनपढ़, गरीब व मजदूर टाईप के लोग विदेशों में जाते हैं तथा दलाल उनसे 10-10, 12-12 लाख रुपये ठग लेते हैं। हरियाणा सरकार ने इमिग्रेशन एक्ट 1983 भी बनाया परन्तु उस पर इंप्लीमैंटेशन कुछ नहीं हुआ फलतः नौजवानों को ठगा जा रहा है। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमैंट सोसायटी पर लाखों रुपये खर्च किये जाने के बाद भी वह कारगर सिद्ध नहीं हो सकी।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for five minutes ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : OK, the time of the sitting of the House is extended for five minutes.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, सदन का समय कम से कम एक घंटे के लिए बढ़ाया जाये ।

Mr. Speaker : You please conclude in five munutes. आप पांच मिनट में पूरी बात कहें ।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा । मैं तो केवल जनता की ही बात कहूंगा । हरियाणा प्रदेश की 25 प्रतिशत जनता डेरों और ढाणियों में रहती है लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 10 और 11 फैमिलीज को डेरे और ढाणियों में बिजली देने की योजना बनाई है । कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसका 6833 लोगों ने फायदा उठाया है । सर, यह भी कमाल की बात है कि जहां लाखों डेरे और ढाणियां हैं फिर भी इसे वहां की जनता से पूछकर भी नहीं बनाया गया । इन्होंने अपनी मर्जी से और यह सोचकर कि इसके लिए 50-50 परसैंट के हिसाब से खर्चा देना पड़ेगा । इसलिए इन्होंने सारे डेरों और ढाणियों को बिजली नहीं दी । इस वजह से लोग आज अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं श्रीमान् जी, आज वे आपकी इंतजार कर रहे हैं कि आप इस नियम में रिलैक्सेशन दे दीजिए । इन्होंने कहा था कि हमने तो बिल माफ कर दिये, 2008-2009 में 2899 करोड़ रुपया बिलों का बकाया था और 2009-10 में 3142 करोड़ रुपया बिजली के बिलों का बकाया था, वर्ष 2010-11 में 3842 करोड़ बकाया था और ये बकाया दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । 750 करोड़ रुपये की ट्यून पर प्रतिवर्ष के हिसाब से इसमें बढ़ौत्तरी हो रही है । इस बढ़ौत्तरी से ऐसा लगता है कि इनमें या तो वसूल करने की इच्छा शक्ति नहीं है या बिलों में कोई हेराफेरी है जो जनता देना नहीं चाहती या ये चाहते होंगे, कहते भी होंगे, या ये माफ करना चाहते होंगे, इनकी दोबारा से कोई ऐसी नीति होगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : बिजली के दोनों निगम उत्तरी और दक्षिणी में 6671 करोड़ रुपये के घाटे में हैं । आज इनके हालात ये हैं कि इनको कोई लोन देने वाला नहीं रहा ।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि इनके राज में न मीटर होगा न रीडर होगा । (शोर एवं व्यवधान) फ्री बिजली देंगे । जब ये सत्ता में आए तो इनको जब इनके वादे की किसानों ने याद दिलाई तो कंडेला में इन्होंने निहत्थे किसानों की हत्या करा दी । आज वे किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं । छाज तो बोले छलनी भी बोले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, बिजली के दोनों निगमों पर आज 15568 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं और कोई भी इनको लोन देने को तैयार नहीं है । सवा 13 परसैंट के रेट ऑफ इंट्रस्ट पर ये लोन ले रहे हैं । जहां तक कृषि क्षेत्र के नलकूपों की बात है वहां

[श्री रामपाल माजरा]

3.96 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली दी गई और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम 4.7 घंटे की सब्सिडी मांग रहा है और यू.एच.बी.वी.एन. ने 3.49 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली दी है और 7.08 घंटे के हिसाब से सब्सिडी मांग रहा है। इसी प्रकार से..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये फैक्चुअली इनकरैक्ट बात है कि नलकूपों को 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली दी जाती है। पॉवर मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। इस बारे में पॉवर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लीयर इंस्ट्रक्शंज दे रखी हैं जिसके फलस्वरूप चाहे बाहर से बिजली खरीद कर दी लेकिन हरियाणा के किसानों के ट्यूबवैल को प्रतिदिन 8 से 10 घंटे हरियाणा सरकार द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है.... (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ये मैंने नहीं कहा है एच.आर.ई.सी. ने कहा है। इसके अलावा 2009-10 में इन्होंने बड़े ढोल पीटे थे कि एच.वी.डी.एस. बनेगा उससे सैग्रेगेशन ऑफ पॉवर हो जायेगी। इस पर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने तो 1497 करोड़ रुपये भी खर्च दिये कि लाइन लौसिज कम हो जाएंगे लेकिन लाइन लौसिज आपके सामने हैं। सर, 2011-12 में 23 प्रतिशत है, टी. एण्ड डी. लौसिज..... (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। इनके समय में तो लाइन लौसिज 41 परसैंट थे अब घटकर 24 परसैंट पर आ गए हैं। इनका यह कहना कि नलकूपों के लिए तीन घंटे बिजली दे रहे हैं, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। तीन घंटे नहीं बल्कि 8 से 10 घंटे प्रतिदिन बिजली ट्यूबवैल को दे रहे हैं और 20-22 घंटे बिजली शहरी क्षेत्र में दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, झज्जर में 35 प्रतिशत लाइन लौसिज हैं, जींद में 28 प्रतिशत लाइन लौसिज हैं। ये कैग की रिपोर्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, आपका समय समाप्त हो गया है। आपको सिर्फ एक मिनट का समय वाइंड अप करने के लिए और दिया जाता है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मार्च 2011 में 33 फीडर टी. एण्ड डी. लौसिस और लाइन लौसिस 25 से 30 परसैंट थी। (शोर एवं व्यवधान) मार्च 2011 में विभिन्न परिचालन मण्डलों में 11 के.वी.ए. के 2737 फीडर थे और उनमें 25 प्रतिशत से अधिक लाइन लौसिज थे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : इनके समय में कितने सब स्टेशन बने थे और कितने फीडर्स कितने लाइन लौस में थे?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, 483 फीडर्स में 25 परसैंट लाइन लौसिज थे, 267 फीडरों में 50 प्रतिशत से अधिक लाइन लौसिज थे। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल, मातनहेल) : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इनके हल्के में 132 के.वी. के पावर हाउस का अभी सी.एम. साहब उद्घाटन करने जा रहे हैं जो कि कलायत में बना है, इसी तरह से एक संगाण में बना है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House stands adjourned till 2.00 P.M. tomorrow, the 2nd March, 2012.

*18-35 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Friday, the 2nd March, 2012.)

49990—H.V.S.—H.G.P., Pkl.